सारांश

मानव विकास रिपोर्ट २००६

बढ़ती कमी:

सत्ता, गरीबी और वैश्विक जल-संकट

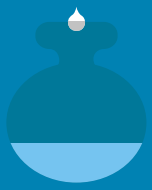

इस पुस्तक का 'कवर डिज़ाइन' इस विचार पर आधारित है कि दुनिया के करोड़ों लोग पानी की कमी के कारण नहीं, बल्कि गरीबी, असमानता और सरकारों की असफलता के कारण पानी से वंचित हैं। इन समस्याओं से निपटना ही वैश्विक जल संकट की कुंजी है।

सुरक्षित पानी और स्वच्छता मानव विकास की आधारभूत आवश्यकताएं हैं, इस क्षेत्र में कमी रहने पर मनुष्यों के तौर पर अपनी सम्भाव्यता को प्राप्त करने के अवसर बहुत कम रह जाते हैं। असुरक्षित पानी और अपर्याप्त स्वच्छता विश्व में गरीबी और असमानता के दो बहुत बड़े कारक हैं। यह लाखों जाने ले लेते हैं, आजीविकाओं को नष्ट करते हैं, सम्मान की हानि करते हैं और आर्थिक वृद्धि की प्रत्याशा को कम करते हैं। मानवीय लागत का बोझ गरीब लोगों, खासतौर पर गरीब स्त्रियों और बच्चों पर पड़ता है।

इक्कीसवीं सदी की शुरूआत में हम अभूतपूर्व रूप से समृद्ध संसार में जी रहे हैं। लेकिन फिर भी साफ पानी और शौचालय उपलब्ध न होने के कारण लगभग 20 लाख बच्चे हर वर्ष मर जाते हैं। एक अरब से ज्यादा लोगों को सुरक्षित पानी नसीब नहीं हो पाता और करीब 2.6 अरब को पर्याप्त स्वच्छता नहीं मिल पाती। दूसरी ओर एक उत्पादक स्त्रोत के तौर पर पानी तक पर्याप्त पहुंच का न होना करोड़ों लोगों को गरीबी और असुरक्षा में धकेल देता है यह रपट पानी के अधिकार के लगातार उल्लंघन को दर्ज करती है, संकट के कारणों की पहचान करती है और बदलाव के लिए एजेन्डा प्रस्तुत करती है।

सारांश
मानव विकास रिपोर्ट २००६

बढ़ती कमी:
सत्ता, गरीबी और वैश्विक जल-संकट

संयुक्त राष्ट्र
विकास कार्यक्रम
(यूएनडीपी)
के लिए प्रकाशित

प्रकाशनाधिकार 2006
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएन प्लाज़ा न्यू यार्क, 10017 यूएसए

सभी अधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी भाग को पूर्व अनुमति के बिना प्रतिरूपित, पुनः प्रापणीय प्रणाली में संचित या बिजली, मशीनी, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग व अन्य किसी भी प्रकार या रूप में प्रसारित न किया जाए।

पालग्रेव मैकमिलन
हाउण्ड्समिल्स, बेसिंगस्टोक, हैम्पशायर आर जी 21 6Xs और
175 फिफ्थ एवेन्यू, न्यूयॉर्क, एन वाई 10010

हमारी कम्पनियां और प्रतिनिधि संसारभर में हैं।

पालग्रेव मैकमिलन, सेंट मार्टिन्स प्रेस एलएलसी और पालग्रेव मैकमिलन लिमिटेड के पालग्रेव मैकमिलन का वैश्विक अकादमिक इम्प्रिंट है।

मैकमिलन अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों में एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है
पालग्रेव यूरोपियन यूनियन और अन्य देशों में एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है।

987654321
टोप्पान प्रिंटिग कम्पनी द्वारा क्लोरीन– रहित कागज़ पर वनस्पति स्याही से मुद्रित व पर्यावरण– अनुकूल तकनीक से प्रतिरूपित।

आवरण एंव रूपांकनः ग्रंडी एण्ड नॉर्थेज इंफोर्मेशन डिज़ाइनर्स, लंदन
सूचना रूपांकनः फिलिप रेकाचवीश्ज, नारेस्टा, नॉर्वे
तकनीकी संपादन, रूपांकन व उत्पादन व्यवस्थाः कम्यूनिकेशन्स डेवेलपमेंट इन्कॉर्पोरेटेड वाशिंगटन, डी.सी.
संपादकः ब्रूस रॉस–लार्सन, मेता द कॉकूमॉ और किस्टॉफर ट्रॉट

मा० वि० रि० 2006 में मुद्रण के बाद पाई गए किसी भी गलती या चूक की सूची के लिए कृपया हमारी वेबसाईट http://hdr.undp.org देखें।

मानव विकास रिपोर्ट २००६ की टीम

निदेशक व मुख्य लेखक
केविन वॉट्किन्स

शोध, लेखन व आंकड़े
लिलियाना कारवाहाल, डेनियल कॉपार्ड,
रिकार्डो फेन्टेस, अरूणाभा घोष,
कियारा गियाम्बेरार्डिनी, क्लेस जोहानसन
(कार्यकारी सांख्यिकीय प्रमुख)
पापा सेक, सिसिलिआ उगाज़
(वरिष्ठ नीति सलाहकार)
व शाहीन याकूब

सांख्यिकी सलाहकारः टॉम ग्रिफिन

संपादन प्रबंधन और अनुवाद संयोजनः
कार्लोत्ता ऐलो और मार्टा जैक्सोना

संपादकः ब्रूस रॉस–लार्सन, मेता द
कॉकूमॉ और किस्टॉफर ट्रॉट

आवरण व लेआउट डिज़ाइन : पीटर
ग्रन्डी और टिली नॉर्थेज

सूचना रूपांकनः फिलिप रेकाचवीश्ज

मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय (एचडीआरओ)

मानव विकास रिपोर्ट कई लोगों के मिले–जुले प्रयास का फल है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट इकाई (एनएचडीआरयू) के सदस्य इस रिपोर्ट के लिए विश्वस्त जानकारी व सलाह प्रदान करते हैं। वे विकासशील देशों में इस रिपोर्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय शोध नेटवर्क से जोड़ने में भी सहायता करते हैं।एनएचडीआरयू टीम की अध्यक्ष सराह बर्ड–शार्प्स(उप–निदेशक) हैं, व इस में एमी गे, शर्मिला कुरूकुलासुरिया, हन्ना श्मिट,व टिमोथी स्कॉट शामिल हैं। एचडीआरओ की प्रशासकीय टीम कार्यालय का कामकाज संभालती है, और इस टीम में ऑस्कर बर्नल, ममये गेबर्टसादिक व मेलिसा हर्नेन्डेज़, फ़े हुआरेज़ और मेरी एन्न म्वांगी शामिल हैं। एचडीआरओ के कामकाज का प्रबंधन सारान्तूया मेंड करते हैं। प्रचार–प्रसार के काम की ज़िम्मेदारी का प्रबंधन मारिसॉल सांहिन्ये करती है।

आमुख

मानव विकास का अर्थ है लोगों को वैसा जीवन जीने देना जिसका वे सम्मान कर पाएं और उन्हें मनुष्यों के तौर पर अपनी सम्भावनाओं को साकार कर पाने में समर्थ बनाना। मानवविकास का नियामक ढांचा आज सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों में प्रस्तुत मोटी– मोटी रूपरेखा में प्रतिबिम्बित होता है जो बेहद गरीबी में कमी लाने, स्त्री–पुरूष की समानता के विस्तार देने और स्वास्थ्य और शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत नियत समयसीमा के अन्दर प्राप्त किए जानेवाले लक्ष्यों का समुच्चय है। इन लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति संकल्प को कृत्य में बदलने के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निश्चय को मापने के लिए एक मानदण्ड उपलब्ध करवाती है। इससे भी बढ़कर यह हमारे दिनोंदिन अधिक अर्न्तनिर्भर होते जा रहे संसार में साझी समृद्धि और सामूहिक सुरक्षा की रचना की एक शर्त है।

इस बरस की मानव विकास रिपोर्ट एक ऐसे मुद्दे पर केंद्रित है जो मानवीय सम्भाव्यता और सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति पर गहरा प्रभाव डालता है। मनुष्यों की प्रगति सदा से ही साफ पानी तक पहुंच और एक उत्पादक संसाधन के तौर पर पानी की सम्भाव्यता को दुह पाने की समाज की सामर्थ्य पर निर्भर रही है। घर में जीवित रह पाने के लिए पानी और उत्पादन के माध्यम से आजीविका के लिए पानी, मानवीय विकास के दो आधार हैं। लेकिन बहुसंख्य मनुष्य इस आधार से वंचित हैं।

विकास के क्षेत्र में कभी–कभी संकट का उपयोग अतिरेकपूर्ण ढंग से होता है। लेकिन अब माना जा रहा है कि जब पानी की बात आती है तो संसार के समक्ष एक ऐसा संकट खड़ा है जिसकी रोकथाम न की गई तो यह सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति को पटरी से उतार कर मानव विकास को ठप्प कर देगा। कुछ लोगों के लिए वैश्विक जल संकट का अर्थ है पानी की वास्तव में दिखती एकदम कमी। प्रस्तुत रपट इस विचार को नकारती है। यह मानती है कि जल के संकट की जड़ें गरीबी, असमानता और असमान सत्ता सम्बन्धों के साथ–साथ उन दोषपूर्ण जल प्रबन्धन नीतियों में भी हैं जो कमी को और बढ़ाती हैं।

जीवन के लिए जल तक पहुंच एक आधारभूत मानवीय आवश्यकता और मानवाधिकार है। लेकिन हमारे निरन्तर समृद्ध हो रहे संसार में 1 अरब लोगों को साफ पानी का अधिकार प्राप्त नहीं है और 2.6अरब लोगों की पर्याप्त स्वच्छता तक पहुंच नहीं है। यह आंकड़े समस्या के केवल एक ही पक्ष को पकड़ पाते हैं। हर बरस गंदे पानी और अस्वच्छता के

कारण करीब 18 लाख बच्चे मर जाते हैं। इक्कीसवीं सदी की शुरूआत में गंदा पानी बच्चों के मरने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। हर रोज़ लाखों स्त्रियां और लड़कियां अपने परिवारों के लिए पानी ढोती हैं– यह रिवाज़ रोज़गार और शिक्षा में स्त्री–पुरूष असमानता को मजबूत करता है। दूसरी ओर पानी और स्वच्छता की कमी से जुड़ी अस्वस्थता उत्पादकता और आर्थिकवृद्धि में पलीता लगा कर वैश्वीकरण के मौजूदा प्रारूपों की अभिलक्षण बन चली गहरी असमानताओं को मजबूत करके दुर्बल परिवारों को गरीबी के चक्र में फंसा देती है।

रपट दिखाती है कि समस्या के स्त्रोत हर देश में अलग–अलग हैं, लेकिन यहां भी कई बिंदु उभरते हैं। पहला, सीमित बजट प्रावधानों को देखकर लगता है कि पानी और स्वच्छता कम ही देशों की राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं। दूसरा, संसार के सबसे गरीब लोगों में से कुछ पानी की सबसे ज्यादा कीमत चुका रहे हैं, गरीब लोग जहां रहते हैं उन स्लमों और अनौपचारिक बस्तियों में पानी की सुविधा सीमित होती है। तीसरा, सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की पूर्ति के लिए गढ़ी गई विकास सम्बन्धी भागीदारियों में पानी और स्वच्छता को प्राथमिकता पर रखने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय असफल रहा है। इन सभी समस्याओं की तह में यह तथ्य दिखा है कि पानी और स्वच्छता के संकट से सबसे अधिक पीड़ित लोगों– गरीब और विशेषतः गरीब स्त्रियों के पास पानी पर अपना दावा दमदार ढंग से पेश कर पाने लायक राजनीतिक स्वर भी नहीं है।

रपट में इन तमाम मुद्दों की सावधानी से पड़ताल की गई है। इस के द्वारा प्रस्तुत चुनौतियां डराती हैं। लेकिन लेखकगण हताशा की वकालत नहीं करते। साक्ष्यों से स्पष्ट है कि हम यह लड़ाई जीत सकते हैं। साफ पानी और स्वच्छता उपलब्ध करवाने के मामले में कई देशों ने अद्भुत प्रगति की है। पूरे विकासशील संसार में स्लमों और देहातों के वासी अपनी समस्याओं को हल करने के लिए संसाधन जुटा रहे हैं, ऊर्जा और नवाचार के नए–नए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इक्कीसवीं सदी की शुरूआत में हमारे पास वित्त, प्रौद्योगिकी और पानी और स्वच्छता के संकट को उतने ही निश्चित रूप से इतिहास बना देने की क्षमता है जैसे एक सदी पहले आज के समृद्ध देशों ने बनाया था। कमी रही है तो बस राजनीतिक संकल्प को प्रेरित करने और संसाधनों को जुटाने की एक वैश्विक कार्ययोजना द्वारा समर्थित सुकल्पित और ढंग से वित्तपोषित राष्ट्रीय योजनाओं के माध्यम से सब के लिए पानी और स्वच्छता उपलब्ध करवाने की।

आजीविका के लिए पानी का प्रश्न अलग किस्म की चुनौतियां प्रस्तुत करता है। संसार में पानी खत्म तो नहीं हो रहा लेकिन उसके करोड़ों सबसे दुर्बल लोग जिन क्षेत्रों में रह रहे हैं वहां पानी की कमी बढ़ रही है। करीब 1.4 अरब लोग ऐसे नदी बेसिनों में रहते हैं जहां पानी का उपयोग जमीन में पानी पहुंचने की दर से कहीं अधिक होता है। अतिउपयोग के लक्षण चिंतित करनेवाले हैंः नदियां सूख रही हैं, भूजल स्तर गिर रहे हैं और जल–आधारित पारिस्थितिकीतंत्रों का तेजी से अपक्षय हो रहा है। दो टूक बात यह है कि संसार अपने अमूल्य संसाधनों में से एक को उड़ा रहा है और एक ऐसा दुर्वह पारिस्थितिकीय कर्ज़ ले रहा है जो हमारी आनेवाली पीढ़ियों को चुकाना पड़ेगा।

मानव विकास को जलवायु परिवर्तन से होनेवाली हानि को देखते हुए भी बहुत कुछ किया जाना जाना चाहिए। जैसाकि रिपोर्ट जोर देकर कहती है, यह कोई ऐसा संकट नहीं है जो भविष्य में कभी आएगा, वैश्विक तापमान वृद्धि शुरू को चुकी है–और कई देशों में यह पीढ़ियों के प्रयासों से सम्भव हुए मानवीय विकास को कई कदम पीछे ले जा सकती है। पहले से ही पानी

की कमी से जूझ रहे इलाकों में पानी की आपूर्ति में और कमी, अधिक विषम मौसम और ग्लेशियरों का गलना हमारे सामने खड़ी चुनौती का हिस्सा हैं। कार्बन उत्सर्जनों को कम करके जलवायु परिवर्तन के क्रम को घटाने के लिए बहुपक्षीय

कार्रवाई उस चुनौती का सामना करने के लिए जननीति प्रतिक्रिया का पहला चरण है। दूसरा चरण है अनुकूलन रणनीतियों को सहयोग देने पर पहले से अधिक जोर।

यह तो स्पष्ट है कि आनेवाले दशकों में पानी के लिए प्रतिस्पर्धा गहराएगी। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिक विकास और कृषि सम्बन्धी जरूरतें, सभी सीमित मात्रा में उपलब्ध एक संसाधन की मांग बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही यह बात भी समझ में आ रही है कि भविष्य में जल उपयोग के नमूनों का अन्दाज़ा लगाते हुए पर्यावरण की जरूरतों को भी गणना में शामिल किया जाना चाहिए। दो खतरे स्पष्ट दिखते हैं। पहला, जैसे–जैसे पानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता गहराएगी शक्तिशाली गुट स्त्रियों और छोटे किसानों के पानी के अधिकारों में सेंध लगाएंगे। दूसरा, पानी चरम चलायमान संसाधन है जो नदियों, झीलों और जलभरों के माध्यम से सीमाओं के पार चला जाता है– इससे पानी की कमीवाले क्षेत्रों में पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ने की सम्भावना बनी रहेगी। दोनों ही खतरों को सार्वजनिक नीतियों और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से हल किया जा सकता है, टाला जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और संयुक्त राष्ट्र तंत्र के कार्मिकों के शोध और विश्लेषण से तैयार हुई इस रिपोर्ट का मंतव्य उन मुद्दों पर बहस और संवाद को प्रेरित करना है जो सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों और मानवविकास की प्राप्ति की दिशा में प्रगति पर गहरा प्रभाव डालेंगे।

कमाल दरविश

प्रशासक, यूएनडीपी

इस रिपोर्ट में दिये गए विश्लेषण व नीति सुझाव आवश्यक रूप से यूएनडीपी, उसके आधिकारिक बोर्ड, या सदस्य देशों के दृष्टिकोण को नहीं दर्शाते। यह रिपोर्ट यूनडीपी द्वारा अधिकृत एक स्वतंत्र प्रकाशन है। यह मानव विकास रिपोर्ट टीम व कई प्रतिष्ठित सलाहकारों के मिले-जुले प्रयास का फल है। इस प्रयास का नेतृत्व एचडीआरओ के निदेशक केविन वॉट्किन्स ने किया है।

मानव विकास रिपोर्ट 2006 की विषय सूची

बढ़ती कमीः सत्ता, गरीबी और वैश्विक जलसंकट

पानी और स्वच्छता सम्बन्धी वैश्विक कार्रवाही के कारण सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों के संबंध

अध्याय 1 पानी और स्वच्छता के संकट का खात्मा

इतिहास से मिले सबक
पानी और स्वच्छता का आज का वैश्विक संकट
संकट की मानव विकास लागत
संकट गरीबों पर कड़ी मार करता है
सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य और उनसे आगे
प्रगति को वास्तविकता में बदलना

अध्याय 2 मानव– उपभोग के लिए पानी

गरीबों को अधिक मूल्य चुकाकर कम पानी क्यों मिलता है?
कार्यकुशलता और समता की प्राप्ति के लिए संजाल प्रबंधन
परिणामपरक नीतियां

अध्याय 3 स्वच्छता की भारी कमी

स्वच्छता के बिना जी रहे 2.6 अरब लोग
स्वच्छता का मुद्दा पानी के मुद्दे से पीछे क्यों रह जाता है?
स्वच्छता को सबकी पहुंच में लाना
आगे की राह

अध्याय 4 पानी की कमी, जोखिम और असुरक्षा

पानी की कमी से जूझते संसार में कमी पर पुर्नविचार
जोखिम, असुरक्षा और अनिश्चितता से निपटना
आगे की राह

अध्याय 5 कृषि में पानी की प्रतिस्पर्धा

पानी और मानव विकास–आजीविका से जुड़ी कड़ियां
प्रतिस्पर्धा, अधिकार और पानी के लिए भगदड़
सिंचाई प्रणालियों में सुशासन
गरीबों के लिए अधिक जल – उत्पादकता
आगे की राह

अध्याय 6 सीमाओं के आरपार जलस्त्रोतों का प्रबंधन

जलविज्ञानी अंर्तनिर्भता
असहयोग की लागतें
सहयोग आवश्यक क्यों?
मानव विकास के लिए नदी बेसिन सहयोग

मानव विकास सूचक

मानव विकास की स्थिति
पाठकों की गाइड और सारणियों के नोट्स
सूचक सारणियां

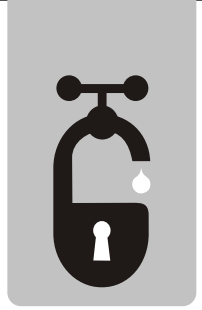

परिदृश्य

बढ़ती कमी

सत्ता, गरीबी और वैश्विक जल–संकट

लेकिन यह एक ऐसा संकट है जो मानव प्रगति को धीमा रखता है और बहुसंख्य मनुष्यों को गरीबी और असुरक्षा से भरे जीवन जीने पर मजबूर करता है।

इस तालाब का पानी अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें इसी से काम चलाना पड़ता है। हम सभी और हमारे जानवर भी इसी तालाब का पानी पीते हैं। इस पानी के कारण हमें तरह–तरह की बीमारियां भी हो रही हैं।

जेनेबिल जमेल,
चौबोरमेनो,इथियोपिया।

मेरा भी दिल करता है कि मैं स्कूल जाऊं। मैं पढ़ना–लिखना सीखना चाहती हूं लेकिन कैसे सीखूं?पानी भरने के लिए मां को मेरी मदद चाहिए।

येनीबाज़ान, आयु 10 वर्ष,एलआल्टो,बोलीविया।

यहां परिस्थितियां बहुत खराब है। चारों तरफ सीवर की गन्दगी फैली है। इससे हमारा पानी प्रदूषित होता है। ज्यादातर लोग पाखाने के लिए बाल्टियों और प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल करते हैं। इतनी गन्दगी की वजह से हमारे बच्चे हमेशा डायरिया और दूसरी बीमारियों से परेशान रहते हैं।

मेरी आकिन्यी, किबेरा,
नैरोबी, केन्या।

ये (फैक्ट्रियां) इतना पानी इस्तेमाल करती हैं जबकि हमको फसल की सिंचाई तो दूर , अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए भी पूरा पानी नहीं मिल पाता।

गोपाल गूजर,
किसान,राजस्थान, भारत।

चार देशों से सुनाई दे रही यह चार आवाज़ें एक ही बात कहती हैं–पानी तक पहुंच से वंचित होने की। इस वंचना को आंकड़ों मापा जा सकता है, लेकिन आंकड़ों के पीछे उन लाखों–लाख लोगों के चेहरे हैं जिन्हें अपनी संभावना को साकार करने के अवसर से वंचित कर दिया गया है। जीवन और मूलभूत मानव अधिकार का तत्व–पानी –उस दैनिक संकट का केन्द्र है जिसे संसार के सबसे दुर्बल करोड़ों लोग रोज़ झेलते हैं। यह संकट जीवन के लिए खतरा है और आजीविकाओं का भयावह रूप से नष्ट करता है।

युद्धों और प्राकृतिक विनाशों के विपरीत जल का वैश्विक–संकट मीडिया में सुर्खियों में नहीं आ पाता। न ही इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही शुरू होती है। भूख की ही तरह पानी तक पहुंच से वंचित हो जाना एक ऐसा बेआवाज संकट है जिसे गरीब लोग झेलते हैं और उसे खत्म कर पाने लायक संसाधनों, प्रौद्योगिकी और राजनैतिक सत्ता से सम्पन्न लोग सहन करते हैं। लेकिन यह एक ऐसा संकट है जो मानव प्रगति को धीमा रखता है और बहुसंख्य मनुष्यों को गरीबी और असुरक्षा से भरे जीवन जीने पर मजबूर करता है। यह संकट रोग के माध्यम से इतने प्राण ले लेता है

वैश्विक जल संकट का कारण बनी कमी की जड़ें पानी के उपलब्ध न होने में नहीं, सत्ता, गरीबी और असमानता में हैं।

जितने बन्दूकों के माध्यम से युद्ध नहीं ले पाते। यह एक निरन्तर समृद्धि होते और अन्तर्सम्बद्ध संसार में अमीर और गरीब देशों को विभाजित करनेवाले जीवन अवसरों में भयंकर असमानता को भी बढ़ाता है।

पानी और स्वच्छता के संकट से पार पाना इक्कीसवीं सदी के शुरूआती वर्षों में मानव विकास के क्षेत्र की बड़ी चुनौतियों में से एक है। एक संयुक्त राष्ट्रीय और अंर्तराष्ट्रीय प्रत्युत्तर के माध्यम से इस चुनौती के समाधान में सफलता जन–स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी में कमी में प्रगति के लिए उत्प्रेरक का काम करेगी और आर्थिक गतिशीलता का स्त्रोत बनेगी। यह गरीबी को कम करने के लिए गठित वैश्विक साझेदारी के हिस्से के तौर पर सरकारों द्वारा अपनाए गए सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को भी एक निर्णायक गति देगा। जैसा चलता है वैसे ही चलने देने का विकल्प अपनाया जाए तो हमें ऐसी पीड़ा और मानवीय संभावना की हानि के एक ऐसे स्तर को झेलते रहना है जिससे बचा जा सकता है और जिसे सभी सरकारों को नैतिक रूप से अस्वीकार्य और आर्थिक रूप से अपव्यय मानना चाहिए।

जीवन के लिए जल, आजीविका के लिए जल

कुरान कहती है'' पानी से हम हर चीज को जीवन देते हैं''। यह आसान सी नसीहत खुद में गहरा ज्ञान समाये है। लोगों को पानी की जरूरत वैसे ही है जैसे आक्सीजन की होती है– इसके बिना जीवन का अस्तित्व नहीं रह पाएगा। लेकिन पानी एक अधिक व्यापक

अर्थ में भी जीवन देता है। अपने स्वास्थ्य और गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों को साफ पानी और स्वच्छता की जरूरत होती है। लेकिन घर–गृहस्थी के परे पानी पारिस्थितिकी तंत्रों का पोषण भी करता है और यह आजीविकाएं बनाए रखनेवाले उत्पादक–तंत्रों में एक निवेश भी है।

अन्ततः मानवविकास का अर्थ संभावना को प्राप्त कर पाना और लोग जो कर सकते हैं या बन सकते हैं– उनकी क्षमताओं और अपने जीवन में वास्तविक चुनाव कर पाने की स्वतन्त्रता है। पानी मानवविकास के सभी पक्षों में व्याप्त है, जब घरों में लोगों को साफ पानी नहीं मिल पाता या एक उत्पादक संसाधन के तौर पर उस तक उनकी पहुंच नहीं होती तब बुरे स्वास्थ्य, गरीबी और असुरक्षा के कारण उनके चुनाव और स्वतंत्रताएं बाधित होते हैं। पानी सब कुछ को जीवन देता है, मानव विकास और मानवीय स्वतंत्रता को भी।

इस वर्ष की मानव–विकास रपट में हम वैश्विक जल संकट से जुड़े दो स्पष्ट विषयों पर गौर कर रहे हैं।

एक से तीसरे अध्याय तक हमने पहले विषय 'जीवन के लिए जल' पर विचार किया है। मानवविकास के तीन सबसे आधारभूत आधार हैं– साफ पानी की आपूर्ति, अपशिष्ट जल को हटाना और साफ सफाई उपलब्ध करवाना। हम इन आधारों को स्थापित न करने की कीमत पर गौर कर रहे हैं और साथ ही सबके लिए पानी और स्वच्छता तक पहुंच को संभव बना पाने के लिए आवश्यक रणनीतियां प्रस्तुत कर रहे हैं।

अध्याय चार–से छः दूसरे विषय 'आजीविका के लिए पानी' पर केंद्रित हैं। यहां हम पानी को देशों के अन्दर और दूसरे देशों के साथ साझा होने वाले एक उत्पादक स्त्रोत के रूप में देख रहे हैं और समान रूप से और कुशलतापूर्वक प्रबन्धित करने में कई सरकारों के सामने आ रही बड़ी चुनौतियों की ओर ध्यान दिला रहे हैं।

कुछ टिप्पणीकार पानी की वैश्विक चुनौती को कमी की समस्या से जोड़ते हैं। आहार की कमी की भविष्यवाणी करके उन्नीसवीं सदी में राजनीतिक नेतृत्व को चौंका देनेवाले अर्थशास्त्री 'माल्थस' को पानी पर अंतर्राष्ट्रीय बहसों में बार–बार याद किया जाता है। तर्क यह दिया जा रहा है कि जनसंख्या के बढ़ने और संसार के जल पर मांग का दबाव बढ़ने के कारण भविष्य में पानी की कमी और बढ़ेगी। हम

आकृति – 1 धीरे–धीरे घट रही पानी और स्वच्छता की वैश्विक कमी

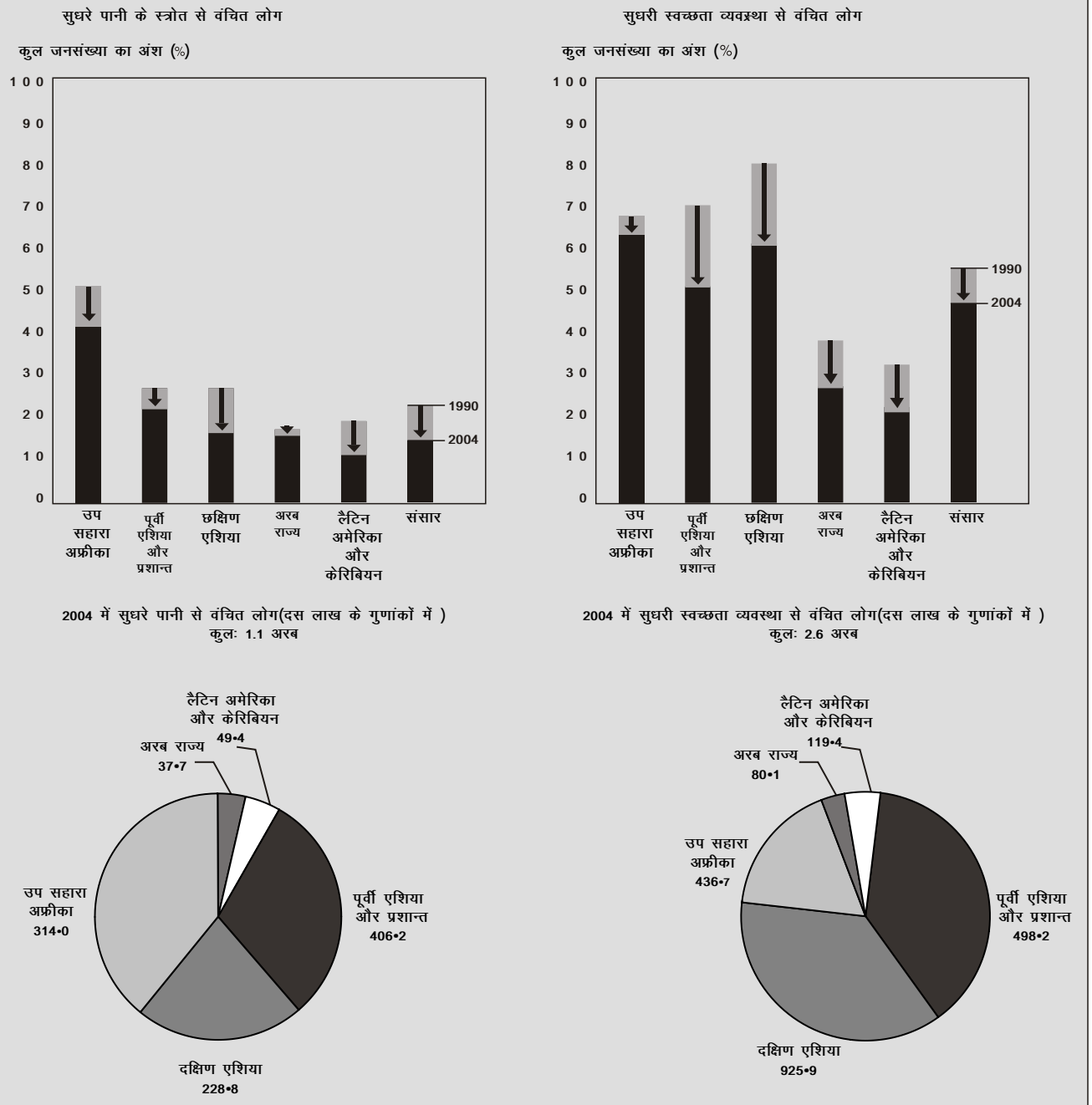

स्त्रोतःयूनिसेफ 2006 a के आधार पर आकलित

इस बिन्दु को अस्वीकार करते हैं। पानी की कमी कुछ देशों में चिन्ता का कारण जरूर है लेकिन वैश्विक जल संकट का कारण बनी कमी की जड़ें पानी के उपलब्ध न होने में नहीं, सत्ता, गरीबी और असमानता में हैं।

जीवन के लिए पानी के क्षेत्र में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती है। आज करीब 1.1 अरब लोग पानी तक पर्याप्त पहुंच से वंचित हैं और 2.6 अरब लोग आधारभूत साफ सफाई से (आकृति1) इन दोनों कमियों का कारण पानी की उपलब्धता नहीं संस्थान और राजनीतिक चुनाव हैं,। पानी की घरेलू स्तर पर जरूरत ,पानी के कुल उपयोग के 5 प्रतिशत से भी कम होती है, लेकिन घरेलू स्तर पर साफ पानी और साफसफाई में तक पहुंच भयंकर असमानता है। एशिया, लैटिन अमेरिका और

पानी और स्वच्छता तक ''पहुंच का न होना'' वंचन के एक ऐसे रूप का ही दूसरा नाम है जो जीवन के लिए खतरा है, अवसरों को नष्ट करता है और मानवीय गरिमा

उप–सहारा अफ्रीका के शहरों के उच्च आयवर्गीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से रोज़ाना सैकड़ों लिटर पानी उपलब्ध रहता है। जबकि इन्हीं देशों में स्लमों में रहनेवाले और देहाती क्षेत्रों के गरीब परिवारों को बहुत ही आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिदिन बीस लिटर पानी भी नहीं मिल पाता। स्त्रियों और छोटी लड़कियों पर असुविधा की दोहरी मार पड़ती है क्योंकि पानी जमा करने के लिए उन्हें अपनी शिक्षा और समय की भेंट चढ़ानी पड़ती है।

आजीविका के लिए पानी के मामले में भी यही देखने में आता है। दुनिया भर में कृषि और उद्योग पानी की कम उपलब्धता की स्थिति से तालमेल बिठा रहे हैं। पानी की कमी एक बहुत व्यापक समस्या है लेकिन इसका अनुभव सभी को नहीं होता। भारत के पानी की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों में सिंचाई के पम्प सम्पन्न किसानों के लिए जल सम्भरों से चौबीसों घंटे पानी खींचते रहते हैं जबकि पड़ोस में ही छोटे किसान वर्षा की कृपा पर निर्भर रहते हैं। यहां भी ज्यादातर मामलों में पानी की कमी का असली कारण वास्तव में पानी की अनुपस्थिति नहीं सांस्थानिक और राजनीतिक है। बहुत से देशों में कमी उन जननीतियों का परिणाम है जो मूल्य में छूट और कम दाम पर आपूर्ति के माध्यम से पानी के आवश्यकता से अधिक उपयोग को उत्साहित करती रही हैं।

घरेलू उपयोग, कृषि और उद्योग की जरूरतों के लिए संसार में आवश्यकता से अधिक पानी उपलब्ध है। समस्या यह है कि कुछ लोग– खासतौर पर गरीब लोग– अपनी गरीबी, अपने सीमित कानूनी अधिकारों या जीवन और आजीविका के लिए पानी उपलब्ध करवानेवाले आधारभूत ढांचों तक पहुंच को सीमित करनेवाली सार्वजनिक नीतियों के कारण बहुत सोच–समझकर पानी से वंचित किए जाते हैं। संक्षेप में, कमी गरीबों को नुकसान पहुंचाने वाले संस्थानों और राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। साफ पानी के मामले में कई देशों में स्थिति यह है कि गरीब लोगों को कम पानी मिलता है, वे उसकी अधिक कीमत भी चुकाते हैं और कमी से जुड़ी मानव विकास लागतों का बोझ भी वही उठाते हैं।

मानवीय सुरक्षा, नागरिकता और सामाजिक–न्याय।

करीब एक दशक पहले 1994 में मानव विकास रिपोर्ट ने विकास पर चल रही व्यापक बहस में मानव–सुरक्षा का विचार जोड़ा। हमारा उद्देश्य सैन्य–खतरों और रणनीतिक, विदेशनीतिक लक्ष्यों की सुरक्षा के मायनों में परिभाषित राष्ट्रीय सुरक्षा की संकीर्ण अवधारणाओं से आगे बढ़कर लोगों के जीवनों में रची–बसी सुरक्षा के सपने को साकार करने की ओर बढ़ना था।

जल–सुरक्षा, मानव–सुरक्षा की इस व्यापक अवधारणा का अभिन्न अंग है, मौटे तौर पर जल–सुरक्षा का अर्थ है पानी उपलब्ध करानेवाले और पानी पर निर्भर पारिस्थितिकीतंत्रों को बनाए रखते हुए यह सुनिश्चित करना कि हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अन्दर एक सही मूल्य पर पर्याप्त सुरक्षित पानी भरोसेमन्द ढंग से मिले ताकि वह एक स्वस्थ, गरिमापूर्ण और उत्पादक जीवन जी सके। जब यह शर्तें पूरी नहीं होती या पानी तक पहुंच में बाधा पड़ती है तो लोग बुरे स्वास्थ्य और आजीविका में बाधा के माध्यम से जबर्दस्त मानव सुरक्षा जोखिमों से दो–चार होते हैं।

शुरूआती इक्कीसवीं सदी के संसार में अंतर्राष्ट्रीय एजेन्डा(कार्यसूची) पर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिन्ताएं महत्वपूर्ण हो चुकी हैं। हिंसक संघर्ष, आंतकवादी धमकियों को लेकर चिंता, आणविक हथियारों में वृद्धि और हथियारों और मादक पदार्थों का बढ़ता व्यापार भी जबर्दस्त चुनौतियां हैं। इस पृष्ठभूमि में कुछ आधारभूत मानव– सुरक्षा प्रश्नों का नजरअदांज हो जाना बहुत आसान बात है। जिनमें पानी से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। गंदे पानी और अस्वच्छता के कारण हर साल

अठारह लाख बच्चे मर जाते हैं, हिंसक संघर्षों में इससे कहीं कम मौतें होती हैं। आतकंवादी कृत्यों से होनेवाली आर्थिक विनाश पानी और स्वच्छता की कमी से होने वाला आर्थिक विनाश की तुलना में बहुत कम है, लेकिन फिर भी पानी और स्वच्छता का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय एजेण्डा पर महत्वपूर्ण नहीं है।

राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता की तुलना में पानी और सफाई के मुद्दों के महत्व का कम होना ही ध्यान नहीं खींचता। आज आठ देशों के समूह के एजेण्डा पर एच.आइ.वी./एड्स के संकट से निबटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही एक स्थाई बिन्दु बन चुकी है। बर्ड फ़्लू के रूप में एक संभावित जनस्वास्थ्य संकट का खतरा दिखते ही संसार बहुत तेजी से वैश्विक कार्यवाही की योजना तैयार करने के लिए लामबंद हो जाता है। लेकिन पानी और स्वच्छता के संकट की जीवन्त वास्तविकता पर प्रतिक्रिया बहुत ही कम और छिटपुट होती है। ऐसा क्यों होता है?एक संभावित कारण तो यह है कि एच.आई.वी./एड्स और ब्र्ड फ़्लू के विपरीत पानी और स्वच्छता का संकट सबसे गरीब देशों के उन सबसे गरीब लोगों के लिए ही सबसे प्रत्यक्ष खतरा होता है जिनका मानवीय सुरक्षा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बोधों को आकार देने में कोई योगदान नहीं होता।

लोगों पर पड़ने वाले साफ दिखते दुष्प्रभावों के अलावा पानी सम्बन्धी असुरक्षा सामाजिक न्याय के कुछ बेहद आधारभूत सिद्धांतों का अतिक्रमण करती है। उनमें से कुछ हैं:

- *समान नागरिकता-* हर व्यक्ति को नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों का अधिकार है जिसमें इन अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर पाने के साधन भी शामिल है। जल असुरक्षा इन अधिकारों को अप्रभावी बनाती है। पानी इकट्ठा करने के लिए घंटों बितानेवाली स्त्री, पानी से जुड़े रोगों से निरन्तर पीड़ित रहने वाली स्त्री अपने देश की सरकार को चुनने में भले ही हिस्सा ले पाए लेकिन समाज में भागीदारी की उसकी क्षमता कम हो जाती है।

- *समाजिक न्यूनतम* सम्मानपूर्वक जी पाने और अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधनों तक पहुंच सभी नागरिकों को प्राप्त होनी चाहिए। साफ पानी सामाजिक रूप से न्यूनतम आवश्यकता का हिस्सा है। हर व्यक्ति को हर रोज कम से कम बीस लिटर पानी उपलब्ध होना चाहिए।

- *अवसर की समानता* पानी सम्बन्धी असुरक्षा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए परम आवश्यक अवसर की समानता को कम करती है। हम सभी मानते हैं कि शिक्षा अवसर की समानता का अभिन्न अंग है। उदाहरण के लिए गंदे पानी के कारण लगातार रोगों से पीड़ित होनेवाले जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते वह सार्थक रूप से शिक्षा के अधिकार का उपयोग नहीं कर पाते।

- *न्यायपूर्ण वितरण* सभी समाज असमानता की न्याय–सम्मता की सीमा निश्चित करते हैं। घर में साफ पानी और खेत में उत्पादक पानी तक पहुंच में असमानता, न्यायपूर्ण वितरण की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। तो खासतौर पर नहीं जब उनके कारण गरीबी और बच्चों की मृत्यु की दरें बढ़ती हों।

पानी को एक मानवाधिकार के रूप में देखने के विचार में यह सब चिंताएं प्रतिबन्धित होती हैं।जैसाकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है,'' साफ पानी तक पहुंच एक आधारभूत मानवीय आवश्यकता है और इसीलिए एक मानवाधिकार है।''पानी को मानवाधिकार मानने का आग्रह अपने आप में एक लक्ष्य और मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित व्यापक अधिकारों को अर्थपूर्ण बनाने का एक साधन भी है।

हर व्यक्ति को हर रोज कम से कम बीस लिटर साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना जल के अधिकार के सम्मान के लिए न्यूनतम आवश्यकता और सरकारों के लिए न्यूनतम लक्ष्य है।

हर व्यक्ति को हर रोज कम से कम बीस लिटर साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना जल के अधिकार के सम्मान के लिए न्यूनतम आवश्यकता और सरकारों के लिए न्यूनतम लक्ष्य है।

सम्मान के लिए न्यूनतम आवश्यकता और सरकारों के लिए न्यूनतम लक्ष्य है।

मानवाधिकार वैकल्पिक अतिरिक्त प्रश्न नहीं है। न ही वे ऐच्छिक कानूनी प्रावधान हैं जो सरकारों की मर्जी से अपनाए या छोड़ दिए जाएं। यह बाध्यकारी दायित्व हैं जो सार्वभौम मूल्यों को प्रतिबिम्बित करते हैं, जो सरकारों पर जिम्मेदारियां डालते हैं लेकिन फिर भी पानी के मानवाधिकार का व्यापक रूप से और योजनाबद्ध ढंग से धड़ल्ले से उल्लंघन होता है– और गम्भीर हनन गरीबों के मानवाधिकारों का होता है।

2015 में सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य की प्राप्ति– मानवता की परीक्षा।

बेहद गरीबी, भूख और बालमृत्यु में कमी लाने; बच्चों को शिक्षा के चक्र में लाने और स्त्री–पुरूष की असमानता से निपटने के सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तय वर्ष 2015 अब एक दशक भी दूर नहीं रहा। इन सभी क्षेत्रों में प्रगति इस बात पर निर्भर होगी कि सरकारें पानी के संकट से कैसे निबटती हैं। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पानी के मानवाधिकार की दिशा में प्रगति को मापने की दिशा में एक मानक उपलब्ध करवाते हैं। यही कारण है कि सुरक्षित पीने के पानी और आधारभूत स्वच्छता से वंचित जनसंख्या के अनुपात को आधा कर देना अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परम –आवश्यक है। साफ पानी और स्वच्छता असंख्य बच्चों की जाने बचाएंगे, शिक्षा में प्रगति को सहारा देगें और लोगों को उन रोगों से बचाएंगे जो उन्हें गरीबी में जकड़े रखते हैं।

पानी और स्वच्छता सम्बन्धी सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के महत्व को समझ पाने के लिए एक ही उदाहरण काफी है– इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेने पर भी 2015 तक 80 करोड़ से ज्यादा लोग पानी और 1.8 अरब लोग स्वच्छता से वंचित रह जाएंगे। प्रगति के बावजूद संसार के सबसे गरीब देशों में जिस की आवश्यकता है उस की कमी बनी ही रह गई है। इस तस्वीर को बदलने के लिए अगले दशक में अथक कार्रवाही करने के साथ–साथ ''जैसा चल रहा है वैसे ही'' काम चलाने की मनोवृत्ति को भी बदलना होगा।

2015 प्रायौगिक और प्रतीकात्मक कारणों से महत्वपूर्ण है। प्रायौगिक स्तर पर यह हमें समय के बीतने की याद दिलाता है– याद दिलाता है कि परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवेशों और नीतियों की अंतिम तिथि सिर पर जा पहुंची है। प्रतीकात्मक रूप से 2015 गहरे अर्थों में महत्वपूर्ण है। उस वर्ष संसार की स्थिति आज के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की स्थिति पर एक टिप्पणी होगी– यह सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य शपथ पर हस्ताक्षर करनेवाले नेताओं की पीढ़ी का परीक्षाफल बताएगी और तय करेगी कि सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य वचनबद्धता का पालन हुआ या नहीं।

2015 में ही किसी समय एक और कम महत्वपूर्ण लेकिन इतनी है प्रतीकात्मक घटना घटेगी। यू.एस. नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन(नासा) जुपिटर आइसी मून्स परियोजना की शुरूआत करेगा। फिलहाल विकसित की जा रही प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वृहस्पति के तीन चंद्रमाओं की परिक्रमा करने के लिए एक अंतरिक्षयान भेजा जाएगा जो उनकी बर्फ़ानी सतह के नीचे उपस्थित खारे पानी की विशाल झीलों के संघटन की पड़ताल करके यह नियत करेगा कि क्या वहां जीवन के अस्तित्व के लिए स्थितियां विद्यमान हैं। अगर हम केवल एक बहुत सरल प्रौद्योगिकीः सभी के लिए साफ पानी और स्वच्छता उपलब्धा करवाने के लिए आधारभूत ढांचे के न होने के कारण पृथ्वी पर जीवन और मानवीय क्षमताओं को नष्ट हो जाने दें तो दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना के संधान के लिए खर्च किए जा रहे अरबों डॉलर जबर्दस्त विडम्बना और त्रासदी होंगे। एक गिलास साफ पानी और एक शौचालय उपलब्ध करवाना चुनौतीपूर्ण

हो सकता है लेकिन इसके लिए बेशकीमती प्रौद्योगिकी की जरूरत नहीं पड़ती।

महात्मा गांधी ने एक बार कहा था,'' हम जो करते हैं और जो हम कर सकते हैं उसके बीच की खाई अगर पट जाए तो संसार की ज्यादातर समस्याएं सुलझ जाएं।'' गांधी जी की यह टिप्पणी सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों पर भी लागू होती है। आज हमारे पास मौजूद संसाधनों और प्रौद्योगिकी का अभूतपूर्व संयोग 2015 तक लक्ष्यों के पूरा न हो पाने की बात को नैतिक और बौद्धिक रूप से अस्वीकार्य और अरक्षणीय बनाता है। हमें निर्धारित लक्ष्यों तक न पहुंचा पानेवाली या मानवजाति के एक बड़े हिस्से की अनदेखी करनेवाली प्रगति से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए।

जीवन के लिए जल– पानी और स्वच्छता का वैश्विक संकट

साफ पानी और स्वच्छता मानव विकास के सबसे सशक्त कारक हैं। वह अवसर को विस्तार देते हैं, गरिमा को बढ़ाते हैं और सुधरते स्वास्थ्य और बढ़ती समृद्धि का एक सुचक्र रचते हैं।

आज समृद्ध देशों में रह रहे लोगों को इस बात का बहुत धुंधली सी ही जानकारी है कि साफ पानी से उन के खुद के देशों में प्रगति कैसे सम्भव हुई। एक सदी से बस कुछ ही बरस ज्यादा पहले तक लंदन, पेरिस और न्यूयार्क डायरिया, पेचिश और टायफॉयड जैसे संक्रामक रोगों के गढ़ थे। उन दिनों वहां बालमृत्यु की दर उतनी ही अधिक थी जितनी आज उप सहारा अफ्रीका में है। औद्योगिकीकरण के कारण बढ़ती समृद्धि से आमदनी तो बढ़ी लेकिन बालमृत्यु दर और जीवन अपेक्षा में कोई फर्क नहीं पड़ा।

पानी और स्वच्छता के मामलों में हुए जबर्दस्त सुधारों ने तस्वीर बदल दी। साफ पानी मानव–प्रगति की लम्बी छलांग का वाहक बना। सामाजिक सुधार के हामी गठबन्धनों, नैतिक सरोकारों और आर्थिक हितों की प्रेरणा से सरकारों ने पानी और स्वच्छता को राज्य और नागरिकों के बीच एक नए सामाजिक करार का केंद्रीय मुद्दा बनाया। एक ही पीढ़ी की अवधि में उन्होंने पानी और स्वच्छता को सबकी पहुंच में लाने के लिए जरूरी वित्त, प्रौद्योगिकी और विनियमों की व्यवस्था कर ली।

नए आधारभूत ढांचे ने गंदे पानी और संक्रामक रोग का दुष्चक्र तोड़ दिया। एक अनुमान के अनुसार बीसवीं सदी की पहली तिहाई में मृत्युदर में लगभग पचास प्रतिशत की कमी पानी को साफ करने की प्रक्रिया के कारण सम्भव हुई। ग्रेट ब्रिटेन में स्वच्छता के विस्तार के कारण 1880 के बाद के चार दशकों में जीवन अपेक्षा में 15 वर्ष बढ़ गए।

स्वच्छता और पानी के बीच की खाई

आज समृद्ध देशों में टोंटी घुमाते ही साफ पानी उपलब्ध है। गोपनीय और स्वास्थ्यकर स्वच्छता को सहज उपलब्ध माना जाता है। कभी–कभी किन्हीं देशों में पानी की कमी को लेकर चिन्ता दिखाई देती है लेकिन उस चिन्ता के उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। समृद्ध देशों में साफ पानी के एक गिलास के बिना बच्चे नहीं मरते, लड़कियों को स्कूल न भेजकर दूर से पानी भर लाने के लिए घर पर नहीं रोका जाता, वहां पानी से फैलनेवाले संक्रामक रोग इतिहास की किताबों का विषय बन कर रह गए हैं।

दूसरी और गरीब देशों में स्थिति धुर विपरीत है– पानी और स्वच्छता की कमी का स्तर अलग–अलग क्षेत्रों में अलग–अलग है लेकिन वैश्विक जल संकट के तथ्य अपनी कहानी खुद कहते हैं। विकासशील संसार के करीब 1.1 अरब लोगों की पहुंच साफ पानी की न्यूनतम मात्रा तक भी नहीं है। उप सहारा अफ्रीका में पानी तक पहुंच की दर सबसे कम है लेकिन साफ पानी से वंचित सबसे अधिक लोग एशिया में रहते हैं। सफाई से वंचित होना तो और भी व्यापक घटना है। करीब 2.6 अरब लोग– विकासशील संसार की जनसंख्या का पचास प्रतिशत– आधारभूत स्वच्छता तक पहुंच से वंचित हैं। और इस

स्वच्छता संक्रामक रोगों को कम करने के लिए सरकारों को उपलब्ध सबसे सशक्त दवाएं हैं। इस क्षेत्र में निवेश का डायरिया जैसे घातक रोगों पर वही प्रभाव होगा जो टीकाकरण का खसरे पर हुआ– लाखों जानें बचाई जा सकेंगी।

तरह के आंकड़ों के पूरी तरह दर्ज़ न हो पाने को ध्यान में रख कर देखा जाए तो समझ में आता है कि आंकड़े जितना बताते हैं समस्या उस से कहीं अधिक व्यापक है।

पानी और स्वच्छता तक ''पहुंच का न होना'' वंचन के एक ऐसे रूप का ही दूसरा नाम है जो जीवन के लिए खतरा है, अवसरों को नष्ट करता है और मानवीय गरिमा को ध्वस्त करता है। पानी तक पहुंच न होने का मतलब है लोग मनुष्यों और पशुओं की विष्टा से प्रदूषित गड्ढों,नदियों और झीलों पर निर्भर होंगे। इसका अर्थ यह भी होगा कि उन्हें सबसे आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं के लिए भी पानी नहीं मिल पाएगा।

आधारभूत आवश्यकताएं अलग–अलग हो सकती हैं, लेकिन पानी की न्यूनतम आवश्यकता मात्रा करीब 20 लिटर प्रतिदिन है। साफ पानी तक पहुंच से वंचितों की श्रेणी में रखे गए 1.1 अरब लोगों में से अधिकांश करीब 5 लिटर पानी का उपयोग करते हैं– समृद्ध देशों में एक व्यक्ति हर रोज इससे दस गुना पानी शौचालय फ़्लश करने में खर्च करता है। यूरोप में पानी के उपयोग का प्रति व्यक्ति औसत 200 लिटर है और अमेरिका में 400 लिटर से अधिक। जब एक यूरोपियन व्यक्ति शौचालय को फ्लश करता है या कोई अमेरिकी फुहारा चला कर नहाता है तो वह विकासशील संसार के शहरी स्लमों या शुष्क क्षेत्रों में रह रहे करोड़ों लोगों को उपलब्ध पानी की मात्रा से कहीं अधिक पानी खर्च कर रहा होता है। एक अरब से अधिक लोग जितने पानी का इस्तेमाल करते हैं समृद्ध देशों के टपकते नलों से उससे कहीं ज्यादा पानी बह जाता है।

स्वच्छता तक पहुंच न होने का मतलब है लोगों का खेतों, गड्ढों और बाल्टियों में मलत्याग पर मजबूर होना। नैरोबी, केन्या की मलिन बस्ती किबेरा के 'उड़न शौचालय' स्वच्छता की व्यवस्था के बिना जीने की स्थिति को रेखांकित करते हैं। शौचालय उपलब्ध न होने के कारण लोग पॉलिथीन की थैलियों में मलत्याग करके उन्हें सड़कों पर फेंक देते हैं। शौचालयों की कमी लड़कियों और स्त्रियों के लिए खासतौर पर गम्भीर स्वास्थ्य और सुरक्षा खतरे बढ़ा देती है। पानी की तरह ही स्वच्छता के मामले में भी स्त्री–पुरूष असमानता हानि की मानवीय लागत को नियत करती है।

पानी और स्वच्छता तक पहुंच मानव–विकास की कुछ दीर्घजीवी शिक्षाओं को प्रबलित करती है। औसतन देखा जाता है कि आय में वृद्धि के साथ–साथ पानी और स्वच्छता तक पहुंच बढ़ती है। लेकिन औसत के चारों ओर बहुत व्यापक विभिन्नाएं हैं। कुछ देशों में– जैसे स्वच्छता के मामले में बाग्लादेश और थाईलैंड और पानी के मामले में श्रीलंका और विएतनाम में – इतना अच्छा काम हुआ है कि सिर्फ आय के आधार पर इसकी अपेक्षा नहीं की जाती। दूसरी ओर सफाई के मामले में भारत और मैक्सिको का प्रदर्शन इनकी तुलना में बहुत खराब है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि आय महत्त्वपूर्ण तो है लेकिन सार्वजनिक नीतियां आय को मानव विकास में बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

मानव–विकास की भारी लागत

पानी और स्वच्छता से वंचित होने की स्थिति में बहुत से और प्रभाव भी होते हैं। मानव विकास की कुछ लागतें इस प्रकार हैं–

- डायरिया के कारण हर वर्ष 18 लाख बच्चों की मृत्यु–हर रोज 4900 मृत्यु या लन्दन और न्यूयार्क में कुल मिलाकर पांच वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों की संख्या के बराबर(आकृति 2) गंदा पानी और खराब साफ–सफाई संसार में बच्चों की मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। 1990 के दशक में सशस्त्र संघर्षों में से जितने लोग मारे गए उससे छः गुना ज्यादा तो 2004 में डायरिया से मरे।

- पानी के कारण होनेवाले रोगों के कारण हर वर्ष 44.3 करोड़ स्कूल दिवसों की

हानि होती है। 000

- लाखों स्त्रियां हर रोज दिन के कई घंटे पानी जमा करने में बिताती हैं।
- असुविधाओं का जीवनव्यापी चक्र लाखों लोगों को प्रभावित करता है। बचपन में अस्वस्थता और शैक्षणिक अवसरों को खो देने के कारण वयस्क गरीबी का जीवन बिताते हैं।

इन मानवीय लागतों में पानी और स्वच्छता की कमी से जुड़े भारी आर्थिक अपव्यय को भी जोड़ा जा सकता है। इन लागतों को मापना अंर्तनिहित रूप से कठिन है। फिर भी इस वर्ष की मानव–विकास रिपोर्ट के लिए किया गया नया शोध संसार के कुछ सबसे गरीब देशों में हो रही भारी हानियों को रेखांकित करता है। शोध में स्वास्थ्य सेवाओं पर होनेवाले खर्चों, उत्पादकता हानियों और श्रम विपथन से जुड़ी लागतों पर ध्यान दिया गया है। (आकृति– 2)

संसार के कुछ सबसे गरीब देशों में हानि सबसे अधिक होती है। सब सहारा अफ्रीका में सकल घरेलू उत्पादन का करीब पांच प्रतिशत या 18.4 अरब डॉलर वार्षिक की हानि होती है जो 2003 में इस क्षेत्र को मिली कुल सहायता राशि और कर्ज राहत से कहीं अधिक है। यह औसत अर्थिक लागतें एक बहुत महत्वपूर्ण मामले में पानी और स्वच्छता की कमी के वास्तविक संप्रभाव को धुधंला कर देती है–अधिकांश हानियां गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों द्वारा झेली जाती है। जिससे गरीबी से बाहर निकलने के गरीब देशों के प्रयास बाधित होते हैं।

कुशलता के किसी भी पैमाने पर मापा जाए, पानी और स्वच्छता में निवेश भारी लाभ देते हैं। इस क्षेत्र में खर्च किया गया हर डॉलर लागत में बचत और उत्पादकता में लाभ की सूरत में औसतन 8 डॉलर का लाभ देता है। आंकड़ों में दिखते इस लाभ के अतिरिक्त पानी और स्वच्छता तक पहुंच में सुधार दीर्घकालीन गतिशील प्रभाव पैदा करने में सक्षम हैं जो आर्थिक

आकृति – 2 डायरियाः बच्चों का दूसरा सबसे बड़ा हत्यारा

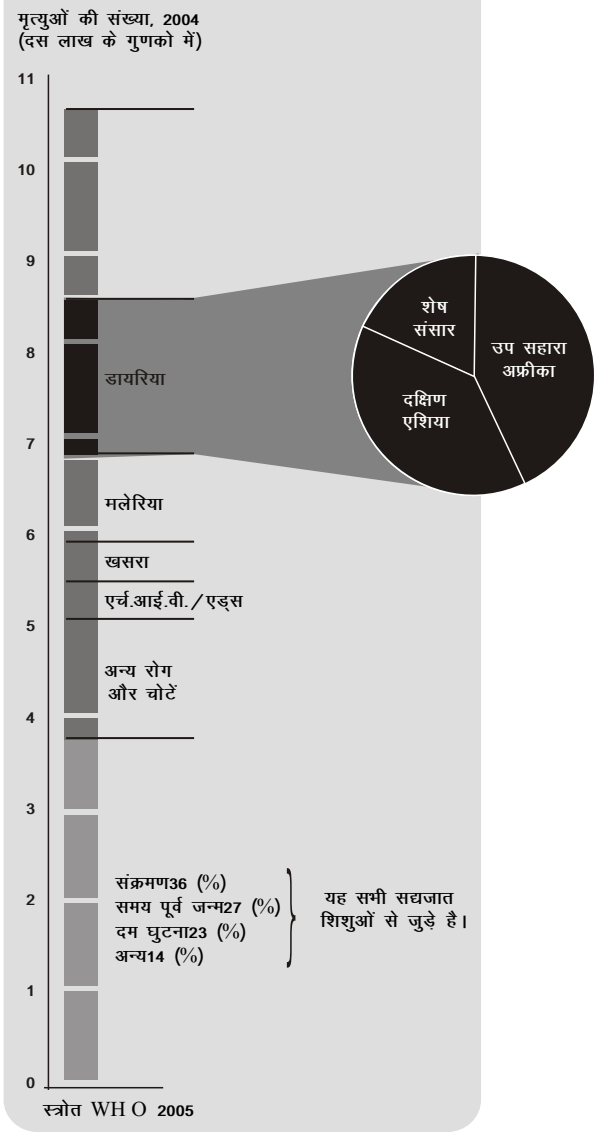

स्त्रोत WH O 2005

आकृति 3 सफ पानी और शौचालयों से शिशु मृत्यु की दरों में कमी

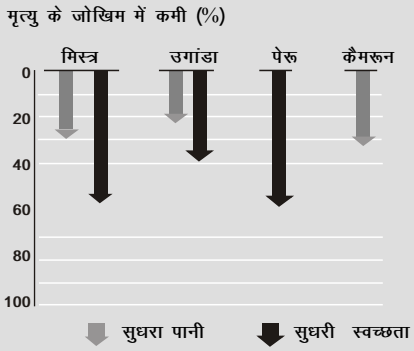

टिप्पणीः आंकड़े 1995 से 2004 के बीच किए गए सर्वेक्षणों पर आधारित हैं। अधिक विवरण के लिए पूरी रिपोर्ट का टैक्निकल नोट 3 देखें। आंकड़े उत्तर–सद्यजात(1–12 माह) मृत्युओं के बारे में हैं। सुधरे पानी या स्वच्छता का तात्पर्य उन एक या अधिक किस्म की पहुंचों से है जिन्हें सुधारा हुआ माना जा रहा है।

आकृति 4 पनी और स्वच्छता सुविधाओं में कमी का खामियाज़ा ज्यादातर गरीब झेलते हैं।

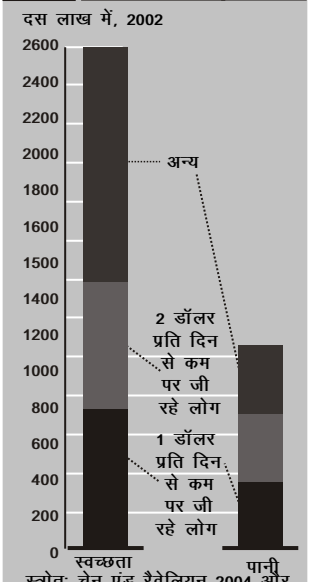

स्त्रोतः चेन एंड रैवेलियन 2004 और वि.स्वा.स. ओर यूनिसेफ 2004 b पर आधारित

कुशलता को बढ़ाते हैं।

चाहे मानवीय पीड़ा की कसौटी पर मापा जाए या आर्थिक बर्बादी या बेहद गरीबी की, पानी और स्वच्छता की कमी की भारी लागत चुकानी पड़ती है। इसी सिक्के का दूसरा पहलू है– इस कमी को कम करके इसे मानव विकास के साधन में बदल पाने की सम्भावना। पानी और स्वच्छता संक्रामक रोगों को कम करने के लिए सरकारों को उपलब्ध सबसे सशक्त दवाएं हैं। इस क्षेत्र में निवेश का डायरिया जैसे घातक रोगों पर वही प्रभाव होगा जो टीकाकरण का खसरे पर हुआ– लाखों जानें बचाई जा सकेंगी। इस रपट के लिए शोध से पता चलता है कि सुरक्षित पानी की उपलब्धता से कैमरून और युगान्डा में बालमृत्यु की दरों में 20 प्रतिशत की कमी आई।मिस्त्र और पेरू में घर में फ्लशयुक्त शौचालय के होने से शिशु–मृत्यु की दर में 30 प्रतिशत की कमी आई (आकृति 3)

सबसे बड़ा खतरा गरीबों के लिए

पानी और स्वच्छता का संकट गरीबों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। साफ पानी की उपलब्धता से वंचित लगभग 66 प्रतिशत लोगों का दैनिक खर्च दो डॉलर प्रतिदिन से कम है और 33 प्रतिशत लोगों का एक डॉलर से भी कम। स्वच्छता की व्यवस्था के बिना जीनेवाले 66 करोड़ लोग दो डॉलर प्रतिदिन से कम पर गुजारा करते हैं और 48.5 करोड़ लोग एक डॉलर प्रतिदिन से कम पर।(आकृति 4)

इन तथ्यों के सार्वजनिक नीति सम्बन्धी निहितार्थ महत्त्वपूर्णहैं। यह स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि निजी तौर पर पैसे खर्च करके पानी और स्वच्छता की सुविधाएं जुटा पाने की इन सुविधाओं से वंचित लोगों की क्षमता सीमित है। पानी पहुंचाने में निजी क्षेत्र की भूमिका हो सकती है लेकिन पानी और स्वच्छता की व्यवस्था की कमी को दूर करने की कुंजी तो सार्वजनिक वित्त–पोषण के हाथ में है।

कई देशों में पर्याप्त पानी और स्वच्छता व्यवस्था की उपलब्धि का वितरण सम्पत्ति के वितरण को प्रतिबिम्बित करता है। घर में पाइपों के जरिए मिलने वाला पानी जनसंख्या के सबसे समृद्ध 20 प्रतिशत ल

ोगों में से औसतन 85 प्रतिशत को मिल पाता है जबकि सबसे गरीब 20 प्रतिशत में से 25 प्रतिशत को यह सुविधा उपलब्ध है। (आकृति 5) असमानता पहुंच से आगे तक व्याप्त है। विकासशील संसार के अधिकांश हिस्से पर लागू होनेवाला विकृत सिद्धांत यह है कि सबसे गरीब लोगों को न केवल कम पानी, कम साफ पानी मिलता है बल्कि यह पानी उन्हें संसार की सबसे मंहगी दरों पर भी मिलता है–

- जकार्ता, इंडोनेशिया; मनीला, फिलीपीन्स; नैरोबी, केन्या के स्लमों में रहनेवाले लोग अपने ही शहरों उच्च आय क्षेत्रों के वासियों की अपेक्षा पानी का 5 से 10 गुना अधिक मूल्य चुकाते हैं, यह दर लंदन और न्यूयार्क की उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई जा रही दर से अधिक है।(आकृति 6)

- उच्च आयवर्ग के परिवार गरीब परिवारों की तुलना में बहुत अधिक पानी का उपभोग करते हैं। तंजानिया में दारेसलाम और भारत में मुम्बई में उच्च आयवर्ग की बस्तियों में स्लमों की तुलना में प्रति व्यक्ति पानी की खपत 15 गुना अधिक है।

- पानी के मूल्यों की असमानता का दुष्प्रभाव परिवारों की गरीबी पर पड़ता है। एलसाल्वाडोर, जमैका और निकारा गुआ के सबसे गरीब 20 प्रतिशत परिवार औसतन अपनी पारिवारिक आय का 10 प्रतिशत से अधिक पानी पर खर्च करते हैं। ब्रिटेन में पानी पर 3 प्रतिशत से अधिक खर्च को तंगी का सूचक माना जाता है।

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के पूर्वानुमान

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य सरकारों द्वारा अपनाए गए पहले महत्वाकांक्षी लक्ष्य नहीं

हैं। 1970 और 80 के दशकों में उच्चस्तरीय अधिवेशनों के बाद स्वीकृति लक्ष्यों में से एक था ''सभी के लिए पानी और स्वच्छता की व्यवस्था''। यह लक्ष्य पूरा हो ही नहीं पाया। क्या इस बार परिणाम कुछ अलग रहेंगे?

कुल मिलाकर संसार पानी के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है क्योंकि भारत और चीन ने इस मामले में खासी प्रगति की है, लेकिन स्वच्छता के मामले में प्रगति सिर्फ पूर्वी एशिया और लैटिन अमेरिका दो ही क्षेत्रों में हो रही है। वैश्विक तस्वीर दिखाने वाले आंकड़ों की आड़ में बड़े–बड़े क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्राचल छिप जाते हैं।

- मौजूदा प्रचलन के आधार पर उप–सहारा अफ्रीका पानी के लक्ष्य 2040 तक और सफाई के लक्ष्य 2076 तक प्राप्त कर सकेगा।(आकृति 7) दक्षिण एशिया स्वच्छता की व्यवस्था के मामले में 4 वर्ष पीछे है और पानी के मामले में 27 वर्ष।

- एक–एक देश के आधार पर देखा जाए तो 23.4 करोड़ लोग पानी के लक्ष्य को पाने से चूक जाएंगे, 55 देश अपनी समयसीमा से पीछे चल रहे हैं।

- स्वच्छता की व्यवस्था का लक्ष्य 43 करोड़ लोग नहीं पा सकेंगे, 74 देश अपनी समय सीमा से पीछे चल रहे हैं।

- समयसीमा के अंदर लक्ष्य पा लेने के लिए उप–सहारा अफ्रीका में पानी के कनेक्शनों की दर पिछले दशक में एक करोड़ प्रति वर्ष रही है, इसे अगले दशक में 2.3 करोड़ कनैक्शन प्रति वर्ष तक पहुंचाना होगा। स्वच्छता की व्यवस्था की दक्षिण एशिया की दर 2.5 करोड़ व्यक्ति प्रति वर्ष से बढ़ाकर 4.3 करोड़ व्यक्ति प्रति वर्ष तक पहुंचानी होगी।

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को सीमारेखा नहीं न्यूनतम उपलब्धि माना जाना चाहिए। इनकी प्राप्ति के बाद भी वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी संख्या में लोग फिर भी इन सुविधाओं से वंचित रहेंगे।

आकृति –5: पानी की विभाजक रेखा

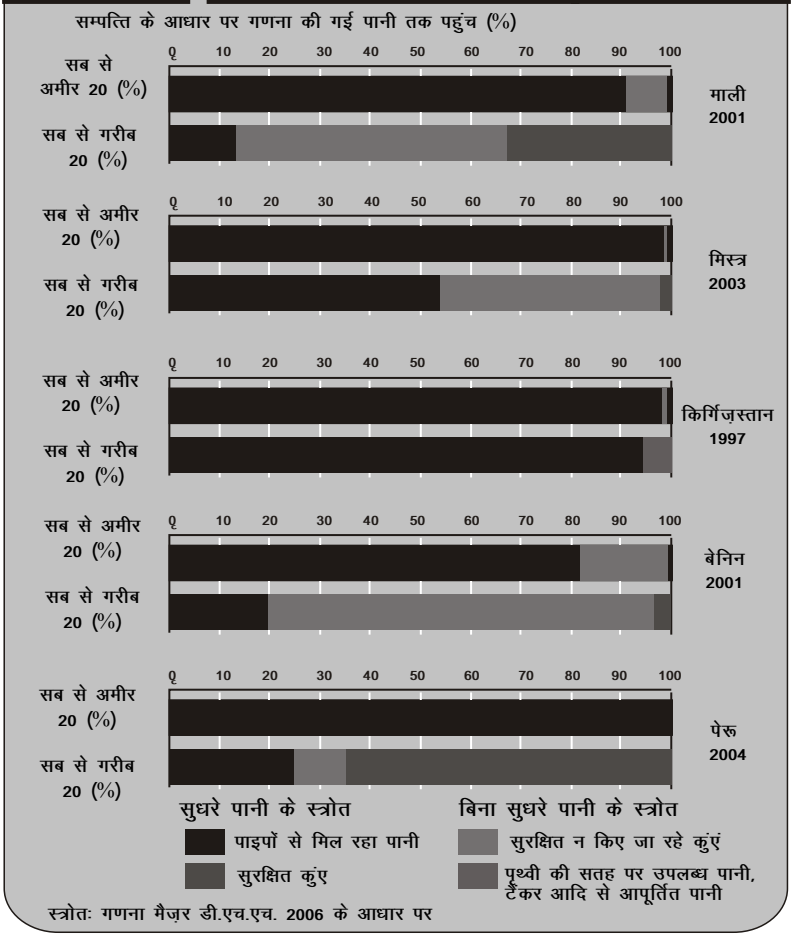

स्त्रोतः गणना मैज़र डी.एच.एच. 2006 के आधार पर

आकृति –6: पानी की कीमतें: गरीबों के लिए ज्यादा, अमीरों के लिए कम

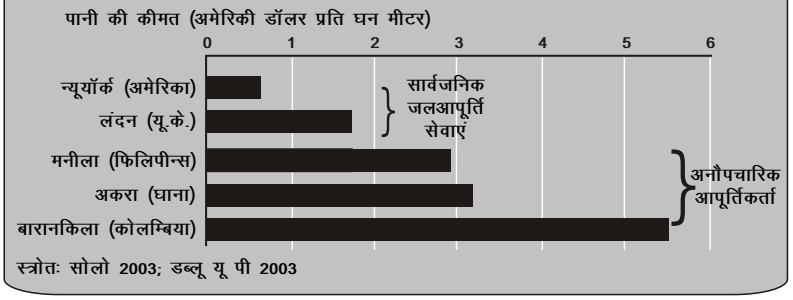

स्त्रोतः सोलो 2003; डब्लू यू पी 2003

मौजूदा वैश्विक प्रक्षेपपथ को देख कर यह चिन्ता लाजमी है कि हम सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों के संकल्प को पूरा कर पाने की दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं कर पा रहे।

मौजूदा प्रवृतियों और लक्ष्यों के बीच अंतर को पाटना

इस तस्वीर को बदलना सही बात ही नहीं बल्कि समझदारी की बात भी है।

यह किया ही जाना चाहिए क्योंकि पानी और स्वच्छता आधारभूत मानवाधिकार हैं और किसी भी सरकार को मानवाधिकार उल्लंघनों के मौजूदा स्तर या मनुष्यों की संम्भाव्यता की हानि की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। और इसे करना समझदारी की बात इसलिए है क्योंकि पानी और स्वच्छता की व्यवस्था तक पहुंच लोगों को खुद को गरीबी के दुश्चक्र से बाहर निकालने और राष्ट्रीय समृद्धि में योगदान करने के लिए तैयार करती है।

अंदाजे बताते हैं कि पानी और स्वच्छता के क्षेत्रों में हुई प्रगति से मानव विकास को होने वाला लाभ इनकी लागत की तुलना में बहुत अधिक है। सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को हासिल कर पाने की अतिरिक्त लागत करीब 10 अरब डॉलर वार्षिक बैठती है। पानी और स्वच्छता के सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य को पाने के लिए मौजूदा प्रवृत्तियों और लक्षित प्रवृत्तियों के बीच के अंतर को पाटने के परिणाम होंगेः

- 2015 में 'बाल मृत्यु' के आंकड़ों में 203000 की कमी आएगी और अगले दशक में 10 लाख से अधिक बच्चों के प्राण बच पाएंगे।
- केवल डायरिया के मामलों में कमी आने से स्कूल उपस्थिति में 27.2 करोड़ दिनों की वृद्धि।
- लगभग 48 अरब डॉलर वार्षिक का कुल आर्थिक लाभ।

उप सहारा अफ्रीका को करीब 15 बिलियन डॉलर का लाभ होगा जो 2003 में इस क्षेत्र को प्राप्त हुई सहायता का 60 प्रतिशत है। दक्षिण एशिया को लगभग 6 बिलियन डॉलर का लाभ होगा।

क्या संसार पानी और स्वच्छता उपलब्ध करवाने में तेजी लाने की लागत चुका पाएगा?असल में सवाल तो यह पूछा जाना चाहिए कि क्या यह निवेश न करना संसार के बूते की बात है?

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य की लागत 10 अरब डॉलर एक बड़ी रकम लगती है लेकिन इसे इसके समुचित संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह वैश्विक सैन्य खर्चे के पांच दिन के बजट से भी कम है और समृद्ध देश मिनरल वाटर खरीदने पर हर वर्ष इससे दो गुना पैसा खर्च करते हैं। लाखों–लाख बच्चों के जीवनों को बचाने, व्यर्थ हो रही शिक्षा संम्भावना को मुक्त करने, लोगों को अस्वस्थता की स्थिति में रखनेवाले रोगों से बचाने के लिए और समृद्धि को बढ़ानेवाले आर्थिक लाभ पैदा करने में सक्षम इस निवेश की यह कीमत बहुत कम है।

सफलता की चार आधार शिलाएं

अगर बयान देने और ऊंचे लक्ष्यों को प्रोत्साहन देनेवाले उच्चस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पानी और मूलभूत स्वच्छता उपलब्ध करवा पाते तो वैश्विक संकट कब का हल हो चुका होता। 1990 के दशक के मध्य से पानी के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों की भरमार हो चली है। उधर संयुक्त राष्ट्र की 23 एजेन्सियां पानी और स्वच्छता के मुद्दे पर काम कर रही हैं।

इतने सम्मेलन, इतनी गतिविधियां– और प्रगति के नाम पर कुछ खास नहीं! पिछले दशक पर दृष्टि डालने पर समझ में आता है कि शब्दों की भरमार और कार्यवाही की कमी से पानी और सफाई के काम में प्रगति नहीं हो पाई। अगले दशक में जरूरत होगी एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना की जिसमें एक वैश्विक कार्यवाही की योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतियां कार्यान्वित की जाएं।

सुधार के लिए कोई आज़मूदा नुस्खा तो नहीं है लेकिन 4 आधारशिलाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं।

- *पानी को मानवाधिकार बनाइए और इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं कीजिएः*

सभी सरकारों को आगे बढ़कर पानी के मानवाधिकार को सक्रियता से लागू करने के लिए कानून बनाने चाहिएं।

इसका अर्थ है कि सभी लोगों को पानी की सुरक्षित, वहनीय और सुलभ आपूर्ति का अधिकार होगा। समुचित अधिकार देश और घर की स्थितियों के अनुरूप भिन्न–भिन्न हो सकते हैं लेकिन हर नागरिक के लिए प्रतिदिन 20 लिटर साफ पानी का लक्ष्य स्पष्ट है– पानी की कीमत चुका पाने में असमर्थ बहुत गरीब लोगों को पानी मुफ्त मिलना चाहिए। लक्ष्य की दिशा में प्रगति के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिएं और प्रगति के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों और पानी उपलब्ध करवानेवालों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। पानी की आपूर्ति में निजी आपूर्तिकर्त्ताओं की भूमिका है तो सही लेकिन पानी का मानवाधिकार का उपलब्ध करवाना सरकारों का ही दायित्व है।

- *पानी और स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय रणनीतियां तैयार करें:*

  सभी सरकारें पानी और स्वच्छता उपलब्ध कराने में प्रगति बढ़ाने के लिए वित्तपोषित और असमानताओं से निबटने की स्पष्ट रणनीतियों द्वारा समर्थित महत्वाकांक्षी लक्ष्योंवाली राष्ट्रीय योजनाएं बनाए। पानी और उससे भी बढ़कर स्वच्छता, गरीबी में कमी लाने की योजनाओं के गरीब रिश्तेदार हैं। इन्हें सदा ही बहुत कम वित्तीय संसाधन मिल पाते हैं, अक्सर तो सकल घरेलू उत्पादन के 0.5 प्रतिशत से भी कम। सैन्य खर्चों की तुलना में जीवन रक्षक पानी और स्वच्छता के क्षेत्रों में किए जा रहे निवेश बहुत ही कम होते हैं। इथियोपिया में पानी और स्वच्छता के बजट से दस गुना अधिक धन सैन्य तैयारियों पर खर्च किया जाता है। पाकिस्तान में 47 गुना। (आकृति 8) सरकारें सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम एक प्रतिशत पानी और स्वच्छता पर खर्च करने का लक्ष्य रखें। असमानता से निपटने के लिए वित्तपोषण की नई रणनीतियां तैयार करनी पड़ेंगी, वित्तीय हस्तांतरणों, छूटों, अन्य उपायों के माध्यम से पानी और स्वच्छता को गरीबों

आकृति 7 कुछ क्षेत्र पानी और स्वच्छता के सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की पटरी से उतर गए हैं

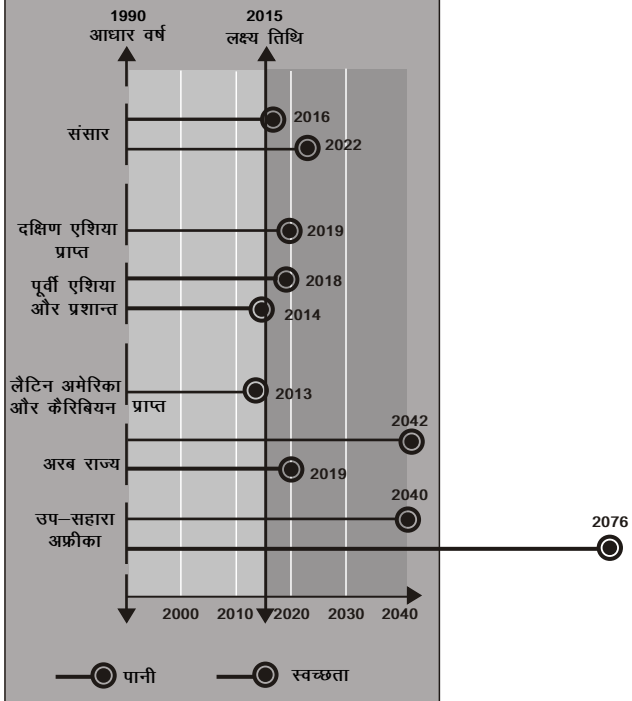

स्रोतः गणना यूनिसेफ 2006 b के आधार पर

आकृति 8 पानीः बजट में निम्न प्राथमिकता

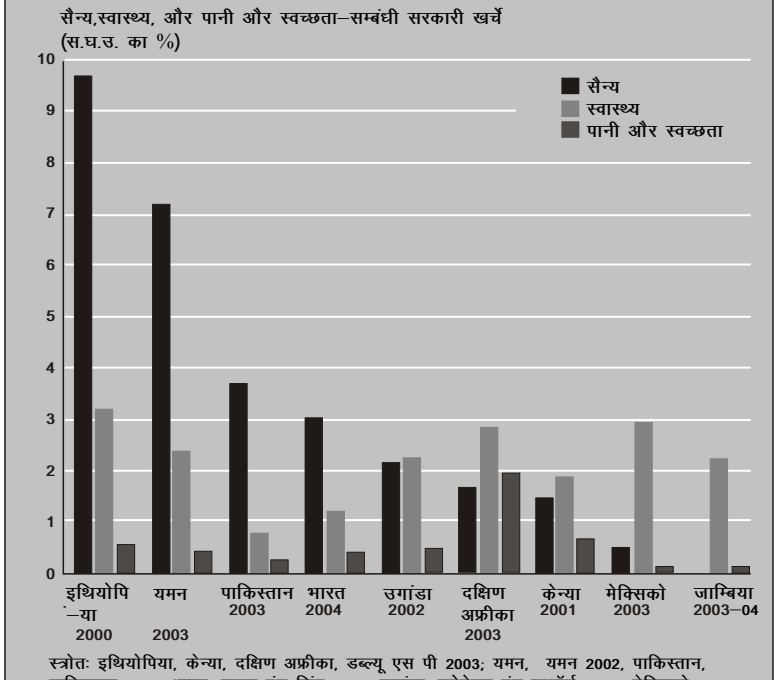

स्त्रोतः इथियोपिया, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, डब्ल्यू एस पी 2003; यमन, यमन 2002, पाकिस्तान, पाकिस्तान 2004, भारत, नय्यर एंड सिंह 2006; उगांडा, स्लेमेकर एंड न्यूबॉर्न 2004; मेक्सिको, आइ एन ई जी आइ 2006 a ; .जाम्बिया, जाम्बिया ..... 2004 b

जापान से यूरोपियन यूनियन और अमेरिका तक विकसित जगत के वासी साफ पानी और आधारभूत स्वच्छता को जीवन का सहज हिस्सा मानते हैं लेकिन संसार भर में अधिकांश लोग आज भी इन मूलभूत मानवाधिकारों से वंचित हैं। यह रिपोर्ट पानी और स्वच्छता के संकट की सामाजिक और आर्थिक लागतों को सशक्त रूप से दर्ज करती है।

पानी और स्वच्छता मनुष्य जीवन के लिए ही आवश्यक नहीं है, वे किसी भी देश में विकास का निर्माण करने वाली इकाइयां हैं। यही कारण है कि आठ सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों में से एक का सुनिश्चित लक्ष्य 2015 तक सुरक्षित पानी और स्वच्छता तक टिकाऊ पहुंच से वंचित लोगों के अनुपात को आधा कर देना है।

साफ पानी और स्वच्छता की कमी स्त्रियों और लड़कियों पर बहुत अधिक दुष्प्रभाव डालती है जो परम्परागत रूप से परिवार के लिए पानी लाती रही हैं। स्कूल जाने की उम्र की लड़कियां पानी के स्त्रोत तक आने–जाने में जितना समय लगाती हैं वह शिक्षा पाने में लगना चाहिये था, पानी ढोते हुए वह शिक्षा पाने, रोजगार पाने और अपने और अपने परिवार के जीवन और स्वास्थ्य के स्तरों को सुधारने के अवसरों को खो रही होती हैं। साफ पानी और स्वच्छता की व्यवस्था से विहीन स्कूल मानव विकास ओर सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की अर्न्तसम्बद्धता का सशक्त साक्ष्य हैं: जब बच्चे निरन्तर बीमार होकर स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं तो प्रभावी शिक्षा–तन्त्र तैयार करने कठिन हैं। जब तक लड़कों और लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालय न होने के कारण माता–पिता लड़कियों को घर बिठाये रखेंगे तब तक सभी को शिक्षा दिला पाना असम्भव ही बना रहेगा।

आज साफ पानी, सुधरे स्वास्थ्य और बढ़ती समृद्धि की अर्न्तसम्बद्धता को समझा जा रहा है। हमारे पास सबके लिए साफ पानी और स्वच्छता उपलब्ध करवा पाने लायक जानकारी, प्रौद्योगिकी और वित्तीय संसाधन मौजूद हैं। अब हमें कार्यवाही के लिए राजनैतिक इच्छा भी जुटानी होगी।

प्रभावी राष्ट्रव्यापी पानी और स्वच्छता प्रणाली के लिए जरूरी आधारभूत ढांचा–पानी के पाइपों से सीवर प्रणाली तक–के लिए जिस तरह का निवेश जरूरी है वह गरीब देशों के बूते से बाहर है। इसके अलावा उसके लिए पहले बड़ी रकम लगानी होगी और फिर वर्षों तक उसकी देखभाल की लागत भी देनी होगी। एक डॉलर प्रतिदिन से भी कम आय पर जी रहे, विकासशील देशों में रह रहे साफ पानी और स्वच्छता से वंचित लोगों की भारी संख्या को देखते हुए इन लागतों को उपयोगकर्ताओं से वसूलना व्यवहार्य नहीं है। 2005 में विकसित देशों की सरकारों ने विकास के लिए दी जा रही सहायता राशि को बढ़ाने का वचन दिया था। यूरोपियन यूनियन ने 2015 तक सहायता राशि को अपनी आय के 0.7 प्रतिशत तक पहुंचा देने का संकल्प किया है। जी–8 ने 2010 तक अफ्रीका को दी जा रही सहायता को दोगुना करने का संकल्प किया। यह वचन देते हुए जी–8 ने माना कि यह सहायता देने का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकासशील देशों के लोगों को साफ पानी और स्वच्छता की सुविधा मिल पाए। लेकिन दानदाताओं द्वारा अधिक दान देना ही निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अतिरिक्त संसाधन नहीं जुटा पाएगा सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को पाने के लिए आवश्यक वित्तीय साधन जुटाने के लिए नवाचारी वित्तीय उपाय अपनाने होने होंगे–पानी और स्वच्छता के मामले में तो यह और भी जरूरी है।

साफ–साफ शब्दों में कहें तो पानी और स्वच्छता के संकट से निबटने के लिए संसार धीरे–धीरे सहायता मिलने का इन्तजार नहीं कर सकता। यह संकट आज बच्चों को मार रहा है और विकास को बाधित कर रहा है–और हमें तुरंत कार्यवाही करनी होगी। इसीलिए विकास के लिए वित्तीय साधन जुटाने के लिए नवाचारी वित्तीय उपायों पर विचार करके उन्हें लागू किया गया है। इन्टरनेशनल फाइनेन्स फैसिलिटी(IFF) इसका एक उदाहरण है। IFF अतंर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों से संसाधन जुटाता है, इन दीर्घ अवधि ऋणों को दानदाता देश 20 से 30 वर्ष की अवधि में चुका देते हैं। इस प्रकार विकास में तुरंत निवेश के लिए अत्यावश्यक संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं, जबकि भुगतान धीरे–धीरे विकसित देशों के सहायता बजटों से होता रहता है।

इस सिद्धांत का पालन करते हुए IFF पहले भी टीकाकरण के लिए धन जुटा चुका है, रोकथाम किए जा सकने लायक रोगों के टीके खरीदने के लिए 4 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश करके 2015 तक 50 लाख जानें और बच जाएंगी।

यह सिद्धांत पानी के लिए भी बहुत संगत है। पानी और स्वच्छता में निवेश से होनेवाले लाभों की दर बांड मार्केटों से उधार लेने की लागत से कई गुना अधिक होगी,यहां तक कि व्याज लगा लेने के बाद भी। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन (**WHO**) ने अनुमान लगाया है कि कम आयवर्गीय देशों में पानी और स्वच्छता के लिए निवेश किए गये एक डॉलर पर औसतन 8 डॉलर का लाभ होता है। किसी भी पैमाने से मापने पर यह बढ़िया निवेश ही ठहरेगा।

पानी और स्वच्छता में निवेश के लिए पूंजी बाजार से संसाधन जुटाना कोई नई बात नहीं है। बीसवीं सदी के प्रारम्भ में औद्योगिक देशों ने पानी और स्वच्छता के लिए आधारभूत ढांचों में निवेश के लिए पैसा जुटाने के लिए बांड जारी किए और पूंजी बाजार का सहारा लिया। और एकदम हाल ही में दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने ऐसे ही निवेश के लिए अतिमहत्वपूर्ण संसाधन तेजी से जुटाने के लिए म्यूनिसपल बांड जारी किए हैं।

हमें स्वीकार करना ही होगा कि सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गठित नई सहायता साझेदारियां दोनो पक्षों को बांधनेवाले करार हैं– दोनों ही पक्षों की जिम्मेदारियां भी हैं और दायित्व भी हैं। विकासशील देशों को सहायता संसाधनों के कुशल और पारदर्शी उपयोग और साफ–पानी और स्वच्छता को सबसे गरीब लोगों तक पहुंचा पाने की उनकी योग्यता के आधार पर आंका जाना चाहिए। लेकिन उन्हें और उनके नागरिकों को सुसंगत सहायता वित्त की अनुमेय उपलब्धता द्वारा पुष्ट बढ़िया नीतियां पाने का अधिकार है।

विकसित देशों को केवल सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों के संकल्प के आधार पर ही नहीं, बल्कि उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने के आधार पर आंका जाना चाहिए। साफपानी और

आधारभूत स्वच्छता उपलब्ध कराने में सहायता दिखाएगी कि यह वचन सिर्फ कहने की बात नहीं है यह हमारी पीढ़ी का संकल्प है।

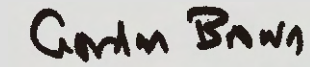

गौर्डन ब्राउन, सांसद,
एक्सचेकर के चांसलर, यूनाइटेड किंगडम

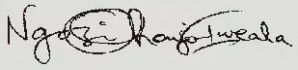

न्गोजी ओकोन्जो– आईवीला,
भूतपूर्व वित्तमंत्री,नाइजीरिया।

के लिए सुलभ बनाना होगा।

समानता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय रणनीतियों में निम्नलिखित निश्कर्ष शामिल होने चाहिएं:

- *सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य* पानी और स्वच्छता की सुविधाओं के बिना जी रहे लोगों की संख्या 2015 तक आधी कर देने के लक्ष्य की पूरक ऐसी नीतियां तैयार करना जो गरीबों और अमीरों को पानी की उपलब्धता के अनुपात के अंतर को आधा कर दें।

- *गरीबी कम करने की रणनीति के दस्तावेज़*-पानी और स्वच्छता को महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनाया जाए और इसके लिए माध्यम अवधि के वित्तीय प्रावधानों से जुड़े स्पष्ट लक्ष्य नियत किए जाएं।

- *पानी के आपूर्तिकर्त्ता* -सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक और निजी सेवाएं और नगर निगम समतापूर्ण हिस्सेदारी के स्पष्ट मानक नियत करें, उनका पालन न करने की स्थिति में दण्डों का प्रावधान रहे।

- *राष्ट्रीय योजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय सहायता का समर्थन मिले* -सबसे गरीब देशों के लिए विकास सहायता अतिमहत्वपूर्ण है।पानी और स्वच्छता में प्रगति के लिए एकमुश्त बड़े निवेश और ऋण चुकाने की लम्बी अवधि की जरूरत पड़ती है। सरकारी राजस्व की सीमाएं बहुत से गरीब देशों की वित्तपोषण क्षमता को सीमित कर देती हैं, दूसरी ओर बेहद गरीबी के कारण लागत वापसी की सम्भावना भी सीमित होती है। अधिकांश दानदाता पानी और स्वच्छता के महत्व को जानते हैं लेकिन फिर भी पिछले दशक में विकास सहायता में कमी आई है और इस क्षेत्र को प्राथमिकता माननेवाले दानदाता कम ही हैं; आज विकास सहायता राशि का 5 प्रतिशत से भी कम इस क्षेत्र के लिए प्राप्त होता है। सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को पहुंच के अंदर लाने के लिए जरूरी है कि सहायता राशि लगभग दोगुनी हो जाए, इसमें हर वर्ष 3.6 से 4 अरब डॉलर तक की वृद्धि होनी चाहिए– दानदाताओं को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार हुई और क्रियान्वित हो रही रणनीतियों को सहायता देनी चाहिए, उन्हें अनुमेय दीर्घावधि वित्त समर्थन उपलब्ध कराना चाहिए (गोर्डन ब्राउन और न्गोजी ओकोन्जी–आइवीला का विशेष लेख देखें)। स्थानीय प्रशासनों और नगर निगम सेवाओं द्वारा स्थानीय पूंजी बाज़ार से पैसा प्राप्त करने के प्रयासों की सहायता भी की जा सकती है।

- *एक वैश्विक कार्यवाही योजना* विकसित करें पानी और स्वच्छता के क्षेत्रों में प्रगति के तीव्र बनाने के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयास छिटपुट और अप्रभावी रहे हैं, उच्चस्तरीय अधिवेशनों की भरमार के बावजूद प्रायौगिक कार्यवाही हमेशा ही नदारत रही। एच.आई.वी/एड्स और शिक्षा के मुद्दों पर दिखी मजबूत अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के मुकाबले पानी और स्वच्छता के मुद्दे वैश्विक विकास कार्यसूची पर बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं। दो वर्ष पहल एक वैश्विक कार्यवाही योजना का संकल्प लेने के बाद से 8 देशों के समूह ने पानी और स्वच्छता को एक प्राथमिकता के तौर पर स्थापित नहीं किया है। वित्तीय सहायता जुटाने, विकासशील देशों की सरकारों को स्थानीय पूंजी बाजारों से पैसा जुटाने में मदद करने और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक कार्यवाही योजना का विकास पानी और स्वच्छता के मामलों में जन चेतना और राजनीतिक प्रयासों का केंद्र बिन्दु बन सकता है।

जीवन के लिए जल

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र की समिति की घोषणा है,'' पानी का मानवाधिकार सभी को निजी और घरेलू उपभोग के लिए

नीति के मूल्यांकन की कसौटी सार्वजनिक या निजी होना नहीं बल्कि गरीबों के लिए सुविधा उपलब्ध करा पाना या न करा पाना होनी चाहिए।

पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से प्राप्य और वहनीय पानी का अधिकार देता है।'' यह 5 केंद्रीय लक्षण जल सुरक्षा की आधारशिला का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन इनका व्यापक रूप से उल्लंघन होता रहता है।

ऐसा क्यों होता है कि गरीब लोगों को साफ पानी कम उपलब्ध होता है और वे उसका अधिक मूल्य भी चुकाते हैं?

शहरी क्षेत्रों में पानी का सबसे सस्ता और सबसे विश्वसनीय स्त्रोत अक्सर जल– आपूर्ति संजाल को संचालित करने वाली सेवा होती है। गरीब परिवारों के इस संजाल से जुड़े होने की संभावना कम होती है, ज्यादा संभावना यही है कि उन्हें अपनी जरूरत के लिए पानी कई तरह के स्त्रोतों से मिलता होगा। दारेसलाम, तंजानिया या ऊगाडूगू, बर्कीना फासो में 30 प्रतिशत से भी कम परिवार पानी के संजालों से जुड़े हैं।

जब परिवार जल– आपूर्ति के संजाल से जुड़े नहीं होते तो उनके विकल्प सीमित होते हैं। वे या तो अनुपचारित स्त्रोतों से पानी जमा करें या किसी सार्वजनिक स्त्रोत से, या फिर कई किस्म के पानी विक्रेताओं से पानी खरीदें। पानी के निजीकरण पर छिड़ी बहसों में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जाता कि ज्यादातर गरीब लोग तो आज भी निजी बाजारों से पानी खरीद रहे हैं। यह बाजार अनिश्चित गुणवत्ता वाले पानी के ऊंचे दाम वसूलते हैं।

आकृति– 9 जलआपूर्ति सेवाएं सबसे सस्ता पानी उपलब्ध करवाती हैं

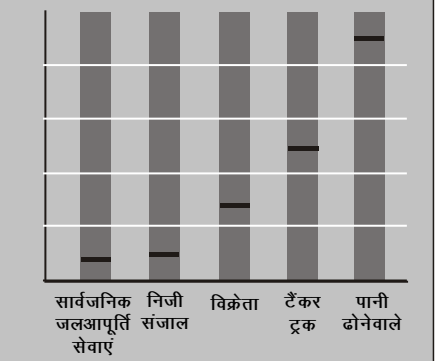

टिप्पणीः 47 देशों और 93 स्थानों से प्राप्त आंकड़ों की समीक्षा पर आधारित
स्त्रोतः कार्लड एंड श्वार्त्ज़ 2005

गरीब चुका रहे हैं ऊंचे दाम

वितरण केंद्र से दूरी कीमतें बढ़ा देती है, जैसे जैसे पानी बिचौलियों के हाथों से गुजरता है और परिवहन और विपणन की लागतें बढ़ती हैं, कीमतें बढ़ती चली जाती हैं। स्लमों में रहनेवाले गरीब लोग अक्सर उसी शहर में रह रहे सम्पन्न लोगों की तुलना में 5 से 10 गुना अधिक कीमत देकर पानी खरीदते हैं।

दाम नियत करनेवाली नीतियां समस्या को और भी बढ़ा देती है। अधिकांश जलसेवा प्रदाता अब अधिक पानी खर्च करने पर अधिक मूल्य वसूलते हैं। लेकिन असल में इसका परिणाम यह होता है कि सबसे गरीब परिवार सबसे अधिक मूल्य चुकाने को बाध्य हो जाते हैं। कारण यह है कि सबसे गरीब परिवारों को पानी उपलब्ध करानेवाले बिचौलिए सबसे अधिक दाम चुका कर भारी मात्रा में पानी खरीद रहे होते हैं।(आकृति 9) डाकार में सबसे गरीब परिवार पानी के लिए जल–आपूर्ति संजाल से जुड़े परिवारों की अपेक्षा तीन गुना अधिक मूल्य चुकाते हैं।

अगर जल प्रदाता सेवा के मूल्य इतने कम हैं तो गरीब परिवार उनसे क्यों नहीं जुड़ते?अक्सर इसका कारण यह होता है कि वह कनैक्शन की फीस नहीं चुका पातेः सबसे गरीब देशों में भी कनैक्शन फीस 100 डॉलर से अधिक हो सकती है। मनीला में सबसे गरीब 20 प्रतिशत परिवारों के लिए पानी का कनैक्शन लेने का मतलब है तीन महीने की आय फीस के तौर पर देना, केन्या के शहरी क्षेत्रों में छह महीने की आय भी देनी पड़ सकती है। एक और बाधा है घर की अवस्थिति, कई शहरों में जल आपूर्ति सेवाएं संपत्ति के औपचारिक कागजों की मांग करती हैं जिससे सबसे गरीब परिवार उनकी सेवा से वंचित रह जाते हैं।

ग्रामीण परिवारों की अपनी विशिष्ट समस्याएं हैं। औपचारिक संजालों से बहुत दूर अवस्थित ग्रामीण समुदाय अक्सर अपनी निजी जल प्रणालियों का प्रबंधन खुद ही करते हैं, हालांकि सेवा

प्रदान करने में सरकारी एजेन्सियां भी शामिल होती हैं। ज्यादातर एजेन्सियों की नीति ''आदेश दो और नियंत्रण कर लो'' की रही है, वे अक्सर बिना ज्यादा विचार–विमर्श किए अनुपयुक्त अवस्थितियों पर अनुपयुक्त प्रौद्योगिकियों की आपूर्ति करती रही हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि कम लोगों तक पानी पहुंच पाया, लागत वसूल नहीं हो पायी और ग्रामीण स्त्रियों को दूर–दूर से पानी ढोते रहने से निजात नहीं मिली।

सार्वजनिक सेवा आपूर्तिकर्त्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका

हाल के वर्षों में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की उपयुक्त भूमिकाओं का मुद्दा पानी के मानवाधिकार पर होने वाली बहस पर छाया रहा। बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये गये लेकिन गर्मागर्म बहस के भी खास परिणाम नहीं निकले।

निजीकरण के कुछ कार्यक्रमों के परिणाम सार्थक रहे हैं लेकिन पूरा परिदृश्य प्रोत्साहित करनेवाला नहीं है। आरहिनतिना से बोलिविया तक और फिलीपीन्स से अमेरिका तक का अनुभव बताता है कि यह विश्वास कि सभी को पानी उपलब्ध कराने की दिशा में हो रही प्रगति को तीव्र करने के लिए आवश्यक कार्य–कुशलता निजी क्षेत्र से ही आ सकेगी, गलत सिद्ध हुआ है। पानी के आपूर्तिकर्त्ताओं की यह असफलताएं भले ही यह प्रमाणित न करती हों कि निजी क्षेत्र की कोई भूमिका नहीं है लेकिन वे अधिक सावधानी, नियंत्रण और सार्वजनिक–निजी साझेदारियों में समानता के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता की ओर इंगित करती ही हैं।

जिन देशों में पानी की आपूर्ति के संजालों से कम लोग जुड़े हैं वहां पानी की आपूर्ति के दो खास पक्ष निजी क्षेत्रों पर अतिरिक्त निर्भरता के विरुद्ध चेताते हैं।

पहला, पानी के क्षेत्र में सहज एकाधिकार के बहुत से लक्षण है। मूल्य निर्धारण और निवेश संबंधी नियमों के माध्यम से सार्वजनिक हितों की रक्षा करनेवाली सशक्त नियंत्रक क्षमता की अनुपस्थिति में एकाधिकारवादी दुरुपयोग के खतरे बने रहते हैं। दूसरा, जल– आपूर्ति संजाल से न जुड़े लोगों की बेहद गरीबी की स्थिति में जलसेवा उपलब्ध करवानेवाली एजेन्सी सार्वजनिक हो या निजी, सेवा तक लोगों की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए सार्वजनिक वित्त की जरूरत पड़ती ही है।

निजीकरण पर छिड़ी बहस के कारण कभी–कभी सार्वजनिक वितरण सेवाओं में सुधार के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर से ध्यान हट जाता है। पानी उपलब्ध कराने के क्षेत्र में सार्वजनिक आपूर्तिकर्त्ताओं का वर्चस्व है, विकासशील देशों में तो 90 प्रतिशत से अधिक पानी वितरित होता है। सार्वजनिक स्वामित्ववाली बहुत सी वितरण सेवाएं प्रबंधन की अकुशलता और जवाबदेही न होने के साथ–साथ वित्त प्रबंधन मूल्य नियत करने में असमानता की शिकार हैं और इसलिए वह गरीबों की सेवा नहीं कर पा रहीं। लेकिन कुछ सार्वजनिक वितरण सेवाएं– ब्राजील का पोर्तो एलेग्रे एक शानदार उदाहरण है– पानी को सभी के लिए उपलब्ध और वहनीय बनाने में सफल रही हैं।

आज असफलताओं से सबक लेने और सफलताओं की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए वास्तविक अवसर उपलब्ध हैं। नीति के मूल्यांकन की कसौटी सार्वजनिक या निजी होना नहीं बल्कि गरीबों के लिए सुविधा उपलब्ध करा पाना या न करा पाना होनी चाहिए।

कुछ देशों ने पानी उपलब्ध कराने में बहुत तेजी से प्रगति की है– कोलम्बिया से सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका तक शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों तक पानी पहुंचाने के लिए नवाचारी रणनीतियां विकसित की गई हैं। वैश्विक स्तर पर पानी और स्वच्छता की सुविधाएं पाने में ग्रामीण लोग शहरी लोगों की तुलना में पीछे रह जाते हैं लेकिन फिर भी मोरक्को और युगांडा जैसे दो एकदम अलग देशों ने इन क्षेत्रों में अपनी तेज बढ़त को बनाये रखा है। सफलता की कुंजियां क्या हैं?

संस्थानगत विखंडन, कमजोर राष्ट्रीय योजना और नीची राजनीतिक स्थिति के संयोग से स्वच्छता का क्षेत्र पानी से भी अधिक पीड़ित है।

राजनीतिक नेतृत्व और प्राप्य लक्ष्य

जैसा कि हम पूरी रिपोर्ट में जोर देते रहे हैं, बने बनाये नुस्खों जैसी कोई चीज नहीं है। एक स्थिति में गरीबों के लिए सार्थक परिणाम देने वाली नीतियां किसी दूसरी स्थिति में असफल रह सकती हैं। लेकिन सफलता की कहानियों से कुछ मोटे–मोटे सबक लिए जा सकते हैं। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि राजनैतिक नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण है। दूसरा सबक यह है कि राष्ट्रीय योजनाओं में सफलता वित्तीय प्रावधानों और असमानता से निपटने की रणनीतियों द्वारा समर्पित प्राप्य लक्ष्यों को निर्धारित करने पर निर्भर है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि जमकर छूटें दी जाएं। चिली, कोलम्बिया और दक्षिण अफ्रीका में सुव्यवस्थित छूटें गरीबों तक पहुंचती हैं और उनका प्रभाव भी दिखाई देता है। (आकृति–10) लेकिन बहुत से मामलों में वितरण सेवा के मूल्य निर्धारण को न्यायसंगत बनाने के लिए दी जाने वाली छूटें अक्सर संपन्न लोगों के लिए ही फायदेमन्द साबित होती हैं जबकि वितरण प्रणाली से न जुड़े गरीब परिवारों को कोई लाभ नहीं मिल पाता। इसी तरह उप सहारा अफ्रीका के अधिकांश भागों में संचालन और व्यवस्था की लागत के लिए जरूरी दामों से भी कम दाम पर उपलब्ध पानी से सबसे अधिक लाभ वितरण सेवाओं से जुडे उच्च आय वर्ग के परिवारों को होता है।

आकृति 10 पानी के उपयोग पर मिलनेवाली छूटें कहां पहुंचती हैं?

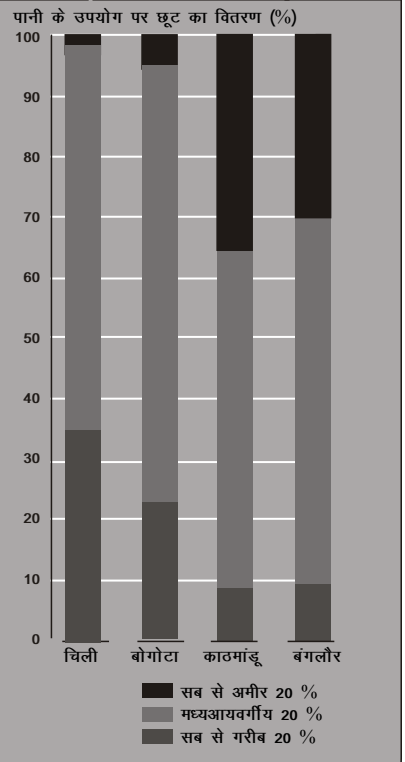

स्रोत: कोमाइल्स एंड अदर्स 2005

समता और कार्यकुशलता के लिए नियंत्रण विनियम और टिकाऊ लागत वसूली अत्यंत महत्वपूर्ण हैं

पानी के वितरण संजाल क्योंकि सहज एकाधिकार हैं इसलिए नियन्त्रण विनियमों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाना बहुत आवश्यक है कि सेवा आपूर्तिकर्त्ता कार्यकुशलता और समता की कसौटियों पर खरे उतरें, जिसका अर्थ है कि उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रहें। बहुत से विकासशील देशों में सशक्त, स्वतन्त्र, नियामक–निकायों की स्थापना करना कठिन रहा है जिसके कारण राजनीतिक हस्तक्षेप और जवाबदेही न होने की स्थितियां बनीं। लेकिन सेवा आपूर्तिकर्त्ता और नागरिकों के बीच संवाद से नियम–विनियम बनाने के प्रयासों के कारण कहीं –कहीं काफी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है– जैसाकि हैदराबाद, भारत में हुआ।

सरकार औपचारिक आपूर्ति संजाल उपलब्ध करवानेवालों के अलावा गरीब लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली अनौपचारिक बाजारों को भी नियामक छूटें उपलब्ध करवाये। विनियम का अर्थ गरीबों की सेवा उपलब्ध करा रहे निजी आपूर्तिकर्त्ताओं की गतिविधियों में कटौती ही नहीं समतापूर्ण कीमतें और पानी की गुणवत्ता के बारे में बने नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए इन आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिल कर काम करना भी है।

टिकाऊ और समतापूर्ण लागत–वसूली किसी भी सुधार कार्यक्रम का हिस्सा होती है। कई मामलों में पानी की कीमतों को व्यावहारिक स्तर पर लाने के लिए और जल प्रबंधन की कार्य क्षमता को सुधारने के लिए मूल्य बढ़ाना आवश्यक होता है–कई देशों में जल की हानि इतनी अधिक और राजस्व का संग्रह इतना कम है कि एक व्यवहार्य जल आपूर्ति प्रणाली चला पाना असंभव ही है।

टिकाऊ और समतापरक की परिभाषा अलग–अलग देशों, अलग–अलग परिस्थितियों में बदलती रहती है। कम आय वाले कई देशों में गरीबी और कम औसत आय के कारण लागत वसूली की गुंजाइश बहुत कम होती है। सहायता के कारण चल पानेवाले सार्वजनिक खर्चे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मध्य आय–वर्ग के देशों में अगर सरकार गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ को सीमित करने के उपाय अपनाए तो न्यायसम्मत लागत वसूली की गुंजाइश अधिक होती है।

मध्यम आयवाले और कुछ कम आयवाले देशों में स्थानीय पूंजी बाजार से अधिक धन ले पाने की सम्भाव्यता भी है। यहां क्रेडिट गारंटियों और ब्याज की दरों

और जोखिम की भावना को कम करने वाले अन्य उपायों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रभावी सिद्ध हो सकती है।

अध्याय 1 में बताए गए राष्ट्रीय और वैश्विक योजना रूपरेखा के आधार पर पानी तक पहुंच में राष्ट्रीय असमानताओं से निपटने की रणनीतियों के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु हैं–

- गरीबी में कमी लाने की राष्ट्रीय रणनीति और सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य रिपोर्टिंग प्रणाली के अंग के तौर पर असमानता कम करने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण, जिसमें सम्पन्न और गरीब वर्गों को सेवाओं की उपलब्धता में असमानता को आधा करना भी शामिल हो।
- मूलभूत आवश्यकताओं के लिए मुफ्त में या वहनीय दरों पर पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाना जैसाकि दक्षिण अफ्रीका में किया गया है।
- यह सुनिश्चित करना कि किसी भी परिवार को पानी की अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपनी आय के 3 प्रतिशत से अधिक खर्च न करना पड़े।
- चिली और कोलम्बिया की तरह कनेक्शन लेने और पानी के प्रयोग के लिए मिलनेवाली छूटों का अधिकतम लाभ गरीब परिवारों को मिल पाना सुनिश्चित करना।
- गरीबों को वहनीय मूल्य पर साफ पानी उपलब्ध करवाने की एक अर्न्तवर्ती रणनीति के तौर पर स्टैंडपाइप प्रावधानों में निवेश बढ़ाना।
- लोगों को सेवा आपूर्तिकर्ताओं से जवाब मांगने में समर्थ बनानेवाले कानूनों को लागू करना।
- सार्वजनिक–निजी भागीदारी करारों में गरीब परिवारों की सेवाएं उपलब्ध करवाने में समता के लिए स्पष्ट मानदण्डों को समाहित करना।
- प्रभावी और राजनीतिक रूप से स्वतंत्र नियामक तंत्रों का विकास और सेवा आपूर्ति संजालो से लेकर अनौपचारिक आपूर्तिकर्ताओं तक को उपलब्ध हो पानेवाली छूटें।

स्वच्छता की भारी कमी को पूरा करना

विक्टर ह्यूगो ने 'ल मिजरेबल्स' में लिखा 'सीवर शहर की अंतरात्मा है।' वह यह बात उन्नीसवीं सदी के पेरिस के सन्दर्भ में कह रहे थे लेकिन आज भी किसी भी समुदाय में स्वच्छता की स्थिति मानव–विकास का एक सशक्त संकेतक है।

लगभग आधा विकासशील संसार सफाई–स्वच्छता से वंचित है। स्वच्छता की ऊंची गुणवत्ता से तो और भी अधिक लोग वंचित हैं। यह कमी बहुत व्यापक रूप से वितरित है। संसार के सबसे गरीब देशों में इस सुविधा के प्रसार की दर बेहद कम है: उप–सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में तीन में से किसी एक व्यक्ति को यह सुविधा मिल पाती है और इथियोपिया में सात में से एक को। सुविधा प्रसार की दरें समस्या की भयावहता को पूरी तरह प्रस्तुत नहीं कर पातीं, खासतौर पर उच्चआयवर्गीय देशों में। जकार्ता और मनीला की पुरानी सीवरेज प्रणालियां बढ़ते शहरीकरण और सदा से कम निवेश की दोहरी मार झेल रहे हैं जिसके कारण गड्ढे वाले शौचालयों का चलन बहुत बढ़ गया है। अब यह शौचालय भूजल को संदूषित कर रहे हैं और नदियों, जलस्त्रोतों को प्रदूषित करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गए हैं।

स्वच्छता तक पहुंच के लाभ कई स्तरों पर होते हैं। अनेक देशों में किए गए अध्ययन बताते हैं कि विष्ठा के निपटान का तरीका बच्चों का जीवित रहना नियत करने के सबसे सशक्त कारकों में से एक है: स्वच्छता में सुधार से बालमृत्यु की दरों में 33 प्रतिशत तक की कमी आती देखी गई है। स्वच्छता में सुधार सार्वजनिक स्वास्थ्य, आजीविका और गरिमा को भी लाभ पहुंचाते

समुदाय की पहल महत्वपूर्ण और यहां तक कि परम आवश्यक भी है लेकिन वह सरकारी कार्रवाई की जगह नहीं ले सकती और गरीब परिवारों द्वारा निजी स्तर पर धन की व्यवस्था करना सार्वजनिक कोष और सेवा प्रावधानों का प्रतिस्थापन नहीं है।

आकृति 11 वियतनाम में गरीब बहुत पीछे छूट गए हैं

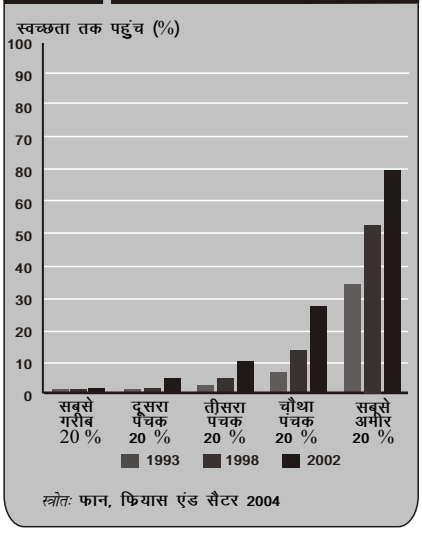

स्त्रोतः फान, फ्रियास एंड सैटर 2004

हैं– यह लाभ घरों से परे पूरे समुदाय तक फैलते हैं। शौचालयों का मानव प्रगति के सूचक होना एक अविश्वसनीय सच है।

कमी इतनी अधिक क्यों है?

सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए स्वच्छता अगर इतनी महत्वपूर्ण है तो इसकी कमी इतनी व्यापक क्यों है, संसार सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति से इतना दूर क्यों है?असल में यह स्थिति बहुत से कारकों का परिणाम है।

पहला है राजनीतिक नेतृत्व की अनुपस्थिति। किसी देश की स्थिति के लिए स्वच्छता से संबंधित नीतियां उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितने आर्थिक प्रबंधन, रक्षा या व्यापार हैं, लेकिन फिर भी स्वच्छता को प्राथमिकता कम ही मिलती है। संस्थानगत विखंडन, कमजोर राष्ट्रीय योजना और नीची राजनीतिक स्थिति के संयोग से स्वच्छता का क्षेत्र पानी से भी अधिक पीड़ित है।

प्रगति की राह में एक और रोड़ा है गरीबीः सबसे गरीब परिवारों में अक्सर स्वच्छता की सुविधाएं खरीद पाने की आर्थिक क्षमता नहीं होती (आकृति–11) लेकिन घरेलू मांग और स्त्री–पुरुष असमानता सहित अन्य घटक भी प्रगति में बाधक बनते हैं। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में स्वच्छता को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति देखी जाती है लेकिन घर में पैसे के हिसाब–किताब में स्त्रियों की प्राथमिकताओं को महत्व नहीं दिया जाता।

समुदाय–सरकार साझेदारियां प्रभावी सिद्ध होती हैं

स्वच्छता की भारी कमी और पूरा करने में हो रही देरी को कुछ लोग इस बात का प्रमाण मानते हैं कि सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सकेंगे। चिन्ता जायज तो है लेकिन उससे निकला निष्कर्ष दोषपूर्ण है। स्वच्छता में तेजी से हुई प्रगति के कई उदाहरण हैं जिनमें से कुछ में पहल स्थानीय समुदायों की ओर से हुई और कुछ में सरकारों ने राह दिखाई–

- भारत और पाकिस्तान में स्लमवासियों की समितियों ने आपसी सहयोग से लाखों लोगों को स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध करवाई है, उन्होंने अपने बूते ही संसाधन जुटाए। भारत में द नेशनल स्लम ड्वैलर्स फेडरेशन और पाकिस्तान में ओरांगी पायलट प्रॉजेक्ट ने दिखा दिया है कि प्रायौगिक कार्रवाई से क्या–क्या संभव है।

- बांगलादेश का टोटल सैनिटेशन कैम्पेन समुदाय–आधारित परियोजना से आगे बढ़कर बहुत तेजी से स्वच्छता तक पहुंच बढ़ानेवाला राष्ट्रीय कार्यक्रम बन चुका है। इस परियोजना को कम्बोडिया, चीन, भारत और जाम्बिया भी अपना रहे हैं।

- कोलम्बिया, लेसोथो, मोरक्को और थाइलैंड में सरकारी कार्यक्रमों ने सभी आयवर्गों तक स्वच्छता की पहुंच को विस्तृत किया है। भारत में पश्चिम बंगाल ने भी इस क्षेत्र में जबर्दस्त प्रगति की है।

- ब्राजील में सीवरेज के निपटान की एक नई रचनात्मक विधि के कारण न केवल लागत में कभी आई है कि बल्कि लोगों को स्वच्छता संबंधी सुविधाएं भी मिल पाई हैं– अब यह विधि अन्य जगहों पर भी अपनाई जा रही है।

सफलता की इन सभी कहानियों के पीछे अलग–अलग कारण हैं। स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए विविध प्रकार की नीतियां विकसित की गई हैं। लेकिन हर मामले में जोर आपूर्ति द्वारा प्रेरित, ऊपर से थोपे गए प्रारूपों के बजाय स्वच्छता की मांग विकसित करने पर रहा। समुदाय की पहल और उसका जुड़ाव परम आवश्यक रहे हैं। लेकिन उतनी ही परम आवश्यक सरकारी एजेंसियों और स्थानीय समुदायों के बीच अंर्तक्रिया थी।

स्थानीय समस्याओं के हल स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्थितियों के अनुरूप ढूंढना बदलाव का शुरुआती बिन्दु हो सकता है लेकिन वित्तीय संसाधन जुटाने

और बाजारों द्वारा वहनीय मूल्य पर उचित प्रौद्योगिकियां उपलब्ध करवा पाने की स्थितियों के सृजन के माध्यम से स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए स्थितियां तैयार करना सरकारों पर निर्भर है। समुदाय की पहल महत्वपूर्ण और यहां तक कि परम आवश्यक भी हैं लेकिन वह सरकारी कार्रवाई की जगह नहीं ले सकती और गरीब परिवारों द्वारा निजी स्तर पर धन की व्यवस्था करना सार्वजनिक कोष और सेवा प्रावधानों का प्रतिस्थापन नहीं है।

मानवीय अपशिष्ट के कलंक से छुटकारा

स्वच्छता के क्षेत्र में सफलता के उदाहरणों के सबसे महत्वपूर्ण सबकों में से एक यह है कि तेजी से प्रगति संभव है। दानदाताओं की सहायता से सबसे गरीब देश भी बदलाव लाने के लिए जरूरी संसाधन जुटाने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। इस राह में सबसे बड़ी बाधा है– कलंक

स्वच्छता और एचआईवी/एड्स के बीच कुछ परेशान करनेवाली समानताएं हैं। हाल ही तक एचआईवी/एड्स से जुड़े सांस्कृतिक और सामाजिक निषेध प्रभावी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाइयों के विकास में बाधा बनते रहे हैं। यह निषेध कमजोर पड़ा है तो कुछ हद तक इसका कारण है भारी विनाश– लेकिन और भी बड़ा कारण शायद यह है कि एचआईवी/एड्स समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करता है।

लेकिन स्वच्छता के मामले में निषेध जस का तस बना है। यही कारण है कि यह विषय कभी राजनीतिक नेतृत्व को आकर्षित नहीं कर पाता और चुनाव प्रचार और सार्वजनिक बहस का मुद्दा नहीं बन पाता। इसके कमजोर पड़ने में इतनी देरी का एक कारण यह है कि एचआईवी/एड्स के संकट के विपरीत यह भेदभाव करता है: यह गरीबों का संकट है, अमीरों का नहीं। इस संकट से निपटने के लिए स्वच्छता की कमी के कारण चुकाई जा रही भारी लागतों को लेकर चेतना और साथ ही इस तथ्य को स्वीकार करने की जरूरत होगी कि स्वच्छता एक मौलिक अधिकार है।

स्वच्छता के क्षेत्र में अति– महत्वपूर्ण नीतिगत चुनौतिया हैं–

- सामाजिक और आर्थिक प्रगति में स्वच्छता के महत्व को प्रतिबिम्बित करनेवाले राष्ट्रीय और स्थानीय राजनीतिक संस्थानों का विकास।
- आदर्श प्रचलनों का पैमाना बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित सरकारी हस्तक्षेपों के माध्यम से सामुदायिक पहलों के परिणामों का लाभ उठाना।
- समुदाय की मांग पर सेवा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सहायता के लिए आगे आने की पद्धति पर आधारित उन परियोजनाओं में अधिक निवेश जिनमें समुदाय की आवश्यकताओं की प्राथमिकताएं नियत करने में स्त्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
- सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर यह

आकृति 12 पानी की घटती उपलब्धता

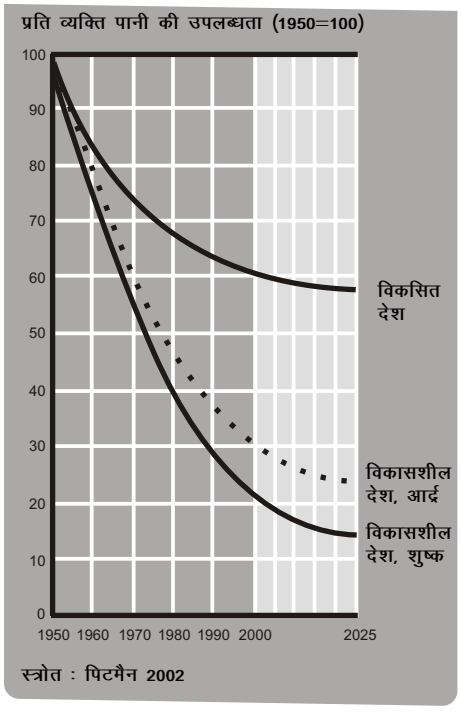

स्त्रोत : पिटमैन 2002

लेकिन कमी आई नीतियों की असफलता से। जब जल प्रबन्धन की बात आती है तो संसार क्रेडिट कार्ड के सहारे आगा–पीछा देखे बिना खरीददारी करता सा दिखता है।

सुनिश्चित करना कि स्वच्छता एक वहनीय विकल्प है।

जल की कमी का प्रबंधन, जोखिम और अतिसंवेदशीलता

इक्कीसवीं सदी की शुरुआत में पानी पर हो रही बहसों में समस्या का निदान माल्थसवादी दृष्टिकोण से होता दिख रहा है। बढ़ती जनसंख्या और पानी की घटती उपलब्धता की चेतावनी देते हुए गंभीर परिणामों का हौव्वा खड़ा किया जा रहा है। क्या संसार में पानी खत्म हो रहा है?

किन्ही अर्थपूर्ण मायनों में तो ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन पानी सम्बन्धी असुरक्षा काफी मनुष्यों के लिए खतरा तो बन ही रही है– यह मानव विकास को बाधित कर रही है। वैश्विक जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के लिए प्रतिस्पर्धा तनाव, और एक उत्पादक संसाधन के रूप में पानी तक पहुंच की अननुमेयता, पानी से जुड़ी असुरक्षा को बढ़ानेवाले सशक्त उत्प्रेरक हैं।

वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो सभी मनुष्यों की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी मात्रा से कहीं अधिक मात्रा में पानी उपलब्ध है। तो फिर पानी की कमी की समस्या क्यों है?कुछ हद तक तो इसका कारण यह है कि सम्पत्ति की ही तरह पानी भी असमान रूप से फैला है (आकृति 12)। मध्यपूर्व एशिया के देशों को इस बात से कतइ राहत नहीं मिलती कि ब्राज़ील और कनाडा में इतना पानी मौजूद है कि वह उसे किसी भी तरह खत्म नहीं कर पाएंगे। न ही ब्राज़ील के सूखाप्रवण उत्तरपूर्वी क्षेत्रों की स्थिति में इस बात से अंतर पड़ता है कि देश में पानी की औसत उपलब्धता का आंकड़ा संसार में सबसे अधिक है। एक और समस्या यह है कि एक उत्पादक संसाधन के तौर पर पानी तक पहुंच आधारभूत ढांचे तक पहुंच की मांग करती है। और आधारभूत ढांचे तक पहुंच भी सभी देशों में समान रूप से वितरित नहीं है।

परम्परागत सूचकों से मापा जाए तो पानी सम्बन्धी दवाब बढ़ रहा है। आज 43 देशों के 70 करोड़ लोग पानी की कमी की 1700 घनमीटर प्रति व्यक्ति की सीमा से नीचे जा रहे हैं। 2025 तक चीन, भारत और उप सहारा अफ्रीका में पानी की कमी और बढ़ेगी और पीड़ितों का आंकड़ा 3 अरब तक पहुंच जाएगा। राष्ट्रीय औसतों पर आधारित यह अनुमान मौजूदा समस्या को काफी कम करके दिखाता है। उत्तरी चीन में 53.8 करोड़ लोग पानी की भारी कमी से जूझ रहे क्षेत्रों में रह रहे हैं। वैश्विक स्तर पर करीब 1.4 अरब लोग नदी –बेसिन क्षेत्रों में रहते हैं जहां पानी का प्रयोग टिकाऊ स्तरों से बहुत अधिक है।

पानी की कमी पर्यावरण के ह्रास में बदलती है। समुद्र तक न पहुंच पानेवाली नदी प्रणालियां, सिकुड़ती झीलें और नीचे जाता भूजल का स्तर पानी के आवश्यकता से अधिक उपयोग के सबसे स्पष्ट दिखनेवाले लक्षण हैं। अमेरिका में कोलोरेडो नदी से चीन में पीली नदी तक नदी–प्रणालियों का अवसान पानी के आवश्यकता से अधिक उपयोग का बहुत स्पष्ट दिखनेवाला परिणाम है। कम दिखनेवाला लेकिन मानव विकास के लिए उतना ही बाधक है दक्षिण एशिया में भूजल का तेजी से कम होना। भारत के कुछ हिस्सों में भूजल का स्तर एक मीटर प्रतिवर्ष से भी अधिक की दर से गिर रहा है जिससे भविष्य में कृषि उत्पादन को खतरा होगा। यह कमी के वास्तविक लक्षण हैं, लेकिन कमी आई नीतियों की असफलता से। जब जल प्रबन्धन की बात आती है तो संसार क्रेडिट कार्ड के सहारे आगा–पीछा देखे बिना खरीददारी करता सा दिखता है।

आकृति 13 हमारा संसारः अधिक समृद्ध, अधिक प्यासा

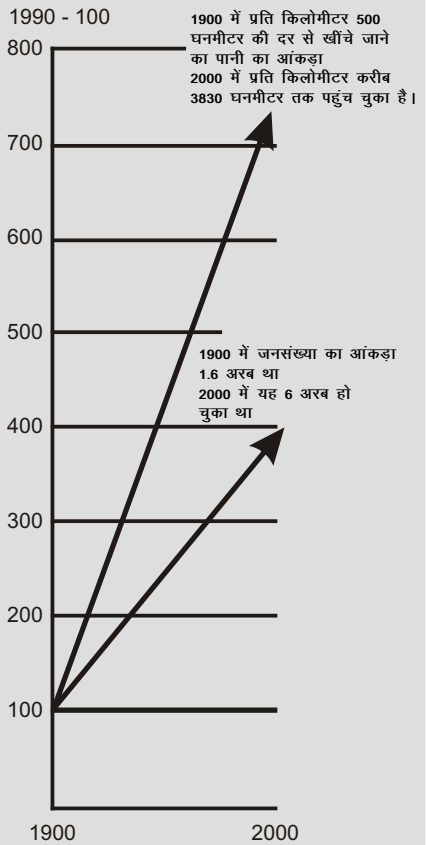

स्रोतः एस आइ डब्ल्यू आइ एंड अदर्स 2006

आकृति 14 संसार पानी का इस्तेमाल कैसे करता है

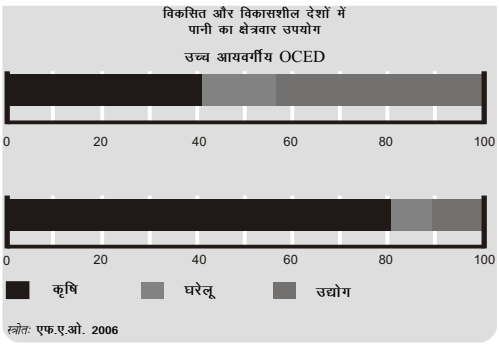

स्रोतः एफ.ए.ओ. 2006

सादा ढंग से कहा जाए तो ज्यादातर देश उनके पास जितना है उससे ज्यादा पानी इस्तेमाल करते रहे हैं। इसका परिणाम है पानी के मामले में इतना बड़ा पारिस्थितिकीय कर्ज जिसे हमारी भावी पीढ़ियां भी चुकाती रह जाएंगी। यह कर्ज उन राष्ट्रीय लेखा–जोखा प्रणालियों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है जो बहुमूल्य प्राकृतिक पूंजी के ह्रास को मापने में असफल रहते हैं– यह पीढ़ियों तक चलनेवाले कर्जो और पूंजी के बारे में भी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। कम दाम पर पानी देने (और कुछ मामलों में मुफ्त में देने) से आवश्यकता से अधिक उपयोग की आदत पक गई है– अगर बाजार में मंहगी कारें लूट की दामों पर बिकने लगे तो उनकी भी भारी कमी हो जायेगी।

भविष्य में पानी के उपयोग का परिदृश्य गम्भीर रूप से चिंतित करने वाला है। लगभग एक सदी से पानी का उपयोग जनसंख्या वृद्धि की दर से दो गुनी रफ्तार से बढ़ता रहा है। यह प्रवृति बनी रहेगी। (आकृति–13)

सिंचाई से पोषित कृषि पानी का सबसे बडा उपयोगकर्त्ता बनी रहेगी– फिलहाल विकाशील देशों में हो रहे पानी के कुल उपयोग का 80 प्रतिशत से अधिक उपयोग इसी क्षेत्र में हो रहा है। (आकृति–14) लेकिन उद्योग और शहरी उपभोक्ताओं की मांगें तेजी से बढ़ रही हैं। 2050 तक संसार के पानी पर 2.7 अरब अतिरिक्त लोगों का भरणपोषण करनेवाले और उन्हें रोजगार देने वाले कृषि–तंत्रो को संभाले रखने का बोझ आ पड़ेगा; दूसरी ओर 2050 तक पानी के उपयोग में अनुमानित अधिकांश वृद्धि के लिए कृषि के बजाए उद्योग का क्षेत्र जिम्मेदार होगा।

आपूर्ति में वृद्धि

अतीत में पानी की कमी होने पर सरकारें आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास करती रही हैं। नदियों के प्रवाह मोड़ने के भारत व पाकिस्तान के बड़े–बड़े कार्यक्रमों से इस विधि की लोकप्रियता का पता चलता है। आपूर्ति पर आधारित अन्य विकल्पों का महत्व भी बढ़ा है। समुद्र के पानी को लवण–मुक्त करने की प्रविधि की लोकप्रियता भी बढ़ी है। हालांकि इसकी ऊंची ऊर्जा लागत इसे मुख्यतः

समृद्ध देशों और समुद्र के पास के नगरों के लिए एक विकल्प बनाती है। आयातित आहार के उत्पादन में इस्तेमाल ''आभासी पानी'' का आयात एक और विकल्प है। लेकिन यहां भी कम आय वर्ग के देशों के विकल्प सीमित ही हैं– आत्मनिर्भता की सम्भावित कमी से आहार सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी।

मांगों को निरुत्साहित करना

मांग–अभिमुख नीतियां ज्यादा असरदार हो सकती हैं। नई उत्पादकता बढ़ाने वाली तकनीक जिसके अन्तर्गत 'प्रति बूंद फसल' अनुपात बढ़ाया जाता है, में जल प्रणालियों पर दबाव घटाने की सामर्थ्य है। जल की मूल्य–निर्धारण नीतियों द्वारा व्यापक रूप जल के अभावमूल्य को बेहतर प्रदर्शित करने की जरूरत है। आवश्यकता से अधिक उपयोग को बढ़ावा देनेवाली विकृत सब्सिडी को जल्दी वापस लेना, भारत एवं मेक्सिको जैसे देशों के लिए सही दिशा में उठाया गया कदम साबित होगा। यह सब्सिडियां अनजाने ही बड़े फार्मों के लिए बिजली उपयोग के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में भूजल के ह्रास के लिए दी जाती हैं। वास्तव में सरकारें इस अमूल्य प्राकृतिक संसाधन के ह्रास के लिए सब्सिडी दे रही हैं– इसकी कीमत पर्यावरण और अन्ततः भावी पीढ़ी को हस्तान्तरित की जा रही है।

अनिश्चितता का प्रबंधन

विकासशील दुनिया की अनेक सरकारें जल के जरूरी समाधानों के समायोजन की आवश्यकता से रूबरू हैं। पारिस्थितिकीय टिकाऊपन और पानी की उपलब्धता की सीमाओं के अन्तर्गत मांग और आपूर्ति को पुनः व्यवस्थित करना– जो स्वीकृत जल संसाधन प्रबंधन की नई महत्वपूर्ण नीतियों का मुख्य उद्देश्य है– लोगों को हानि भी पहुंचा सकता है और लाभ भी। हर हाल में लाभ देने वाली स्थितियां भी है। लेकिन

मौसम के बदलाव के कारण दुनिया में जल–असुरक्षा की प्रकृति में बदलाव हो रहा है।

खतरा यह है कि गरीबों के हितों की उपेक्षा हो जायेगी क्योंकि बड़े कृषि उत्पादक और उद्योग, सशक्त राजनीतिक आवाज रखने वाले दोनों घटक, अपने–अपने दावे प्रस्तुत करेंगे। अनेक समाजों में जल ही शक्ति है और शक्ति की असमानता के कारण जल की प्राप्ति में गहरी असमानताएं पैदा हो जायेंगी।

अनिश्चितता कम करने तथा जोखिम घटाने में पानी से जुड़ी आधारभूत संरचनाए महत्वपूर्ण हैं जो जल भण्डारण के क्षमता के सहज संकेतकों में दिखाई देती हैं–अमरीका लगभग 6000 घन मीटर प्रति व्यक्ति जल भण्डारण करता है; इथियोपिया, 43 ; यहां तक कि अमीर देशों में भी जल–संबंधी विघटन देखे जा सकते हैं। जैसाकि न्यू आर्लियान में कैटरीना तूफान के असर के रूप में देखा गया। लेकिन गरीब देशों के लिए जोखिम बहुत भारी है।

जल असुरक्षा के चरम स्वरूपों सूखा और बाढ़ के मानव विकास पर विनाशकारी परिणाम होते हैं। सन् 2005 में हार्न ऑफ अफ्रीका के दो करोड़ से अधिक लोग सूखे से प्रभावित हुए। उधर मोजाम्बीक में बाढ़ के फलस्वरूप वहां सकल राष्ट्रीय आय लगभग 20 प्रतिशत कम हो गयी। वर्षा की अस्थिरता और पानी के बहाव में अत्यधिक बदलाव के कारण संपत्तियां नष्ट हो सकती हैं, जीविका के साधन समाप्त हो सकते हैं, अर्थव्यवस्थाओं की विकास–क्षमता घट सकती है। विश्वबैंक के अनुसार अस्थिरता के कारण इथियोपिया की विकास क्षमता एक तिहाई घटी है। असर पूरे समाज पर होता है। लेकिन जल संबंधी आघात के असर गरीबों को सबसे अधिक झेलने पड़ते हैं।

मौसम के बदलाव से निपटने के लिए अनुकूलन हेतु बहुपक्षीय ढांचे की आधारशिला अन्तर्राष्ट्रीय सहायता होनी चाहिए।

मौसम के बदलाव से निपटना

मौसम के बदलाव के कारण दुनिया में जल–असुरक्षा की प्रकृति में बदलाव हो रहा है। हालांकि अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत बढ़ते तापमान के जोखिम मजबूती से स्थापित हो चुके हैं, विकासशील देशों में संवेदनशील कृषि उत्पादकों पर इसके प्रभाव की ओर अपर्याप्त ध्यान दिया गया है। सन् 1992 में अपनाये गए जलवायु परिवर्तन के फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ने सरकारों को चेतावनी दी थी कि ''गंभीर और अपरिवर्तनीय जोखिमों के बावजूद कार्य–योजनाओं को टालने के लिए इन्हें कारण नहीं बनाया जाना चाहिए।'' कुछ चेतावनियों की और भी खतरनाक ढंग से उपेक्षा हुई है।

- भूमंडलीय तापवृद्धि के कारण जल की उपलब्धता निश्चित करने वाले जलीय पैटर्न में बदलाव होगा । मॉडल अभ्यास जटिल परिणामों की ओर इशारा करते हैं जो सूक्ष्म–जलवायु द्वारा मूर्तरूप लेंगे। एक साधारण सूत्र हैः दुनिया के अधिकांश पानी का दबाव झेल रहे क्षेत्रों को और कम पानी मिलेगा और पानी का बहाव कम अनुमेय होने के साथ चरम घटनाओं के वशीभूत हो जायेगा। कुछ अनुमानित परिणाम हैं–

- वर्षा कम होने और तापमान बढ़ने के साथ पूर्वी अफ्रीका, सहेल और दक्षिणी अफ्रीका में जल उपलब्धता में विशेष कमी होने के कारण मूल खाद्य तत्वों की उत्पादकता की बड़ी हानि होगी। पूर्वी अफ्रीका में वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए अनुमान इंगित करते हैं कि मक्का की उपज में 33 प्रतिशत, ज्वार में 20 प्रतिशत से अधिक और मोटे अनाजों में 18 प्रतिशत की हानि होगी।

- खाद्य उत्पादन प्रणाली में विघटन के कारण 7.5–12.5 करोड और लोग भूख का संकट झेलेंगे।

- गलेश्यिरों के अधिक पिघलने के कारण पूर्वी एशिया, लैटिन अमेरिका और दक्षिण एशिया के देशों के बड़े समूह में जल उपलब्धता में मध्यम अवधि की कमी हो जाएगी।

- दक्षिणी एशिया में मानसून के पैटर्न में उलट–पलट के कारण, अधिक वर्षा क्षमता के साथ वर्षा–दिवसों के कम होने से, सूखे के कारण अधिक लोग

प्रभावित होंगे।

- समुद्र का स्तर ऊपर उठने से बांग्लादेश, मिस्र और थाईलैंड जैसे देशों में नदी डेल्टा प्रणाली में पेयजल में कमी हो जाएगी।

मौसम के बदलाव के कारण जल सुरक्षा के खतरे के प्रति अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया नाकाफी रही है। बहुपक्षीय प्रयास भविष्य में मौसमी बदलाव में कमी करने पर केन्द्रित रहे हैं। प्रयास करना बहुत जरूरी है– और 2012 में वर्तमान क्योटो प्रोटोकाल की समाप्ति पर, गहरे कार्बन उत्सर्जनों में कटौती करने हेतु समझौतावार्ता एक प्राथमिकता है। भविष्य में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक क्रांति के स्तर से 2 सेल्सियस की बढ़त पर रोकना प्राथमिकता होनी चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए औद्योगिक और विकासशील दोनों देशों की ऊर्जानीतियों में महत्वपूर्ण समायोजन के साथ स्वच्छ तकनीकों के हस्तान्तरण के लिए धन की आवश्यकता होगी।

प्रशमन नहीं – अधिक अनुकूलन

कार्बन उत्सर्जन में प्रबल कमी करने के बावजूद पहले हो चुके उत्सर्जनों के कारण दुनिया में खतरनाक मौसमी बदलाव होगा। मौसम का बदलाव भविष्य का संकट नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जिसके अनुसार देशों और लोगों को अपने को ढालना होगा। वर्षा आधारित कृषिवाले क्षेत्रों में असरदार अनुकूलन नीतियां विकसित करने की चुनौती सबसे अधिक होगी जहां दुनिया के सबसे गरीब लोगों की आजीविका अनिश्चित हो जायेगी। वर्षा पैटर्न अधिक परिवर्तनशील हो जाएंगे और कुछ मामलों में जल उपलब्धता घट जाएगी।

मौसम के बदलाव से निपटने के लिए अनुकूलन हेतु बहुपक्षीय ढांचे की आधारशिला अन्तर्राष्ट्रीय सहायता होनी चाहिए। लेकिन वित्तीय हस्तांतरण दुखद रूप से नाकाफी रहा है। वर्तमान अनुमान के मुताबिक क्योटो प्रोटोकाल से संबद्ध 'अनुकूलन निधि' सन् 2012 तक लगभग 2 करोड़ डालर की व्यवस्था करेगी जबकि अनुकूलन हेतु मुख्य बहुपक्षीय तंत्र ग्लोबल एनवायरमेंटल फेसिलिटी ने सन् 2005 से 2007 तक की अवधि में अनुकूलन गतिविधियों की सहायता के लिए 5 करोड़ डालर आवंटित किये हैं।

बहुपक्षीय ढांचे के अलावा, कृषि हेतु विकास सहायता में कमी के कारण अनुकूलन के लिए उपलब्ध धन की कमी हो गयी है। पिछले दशक में पूर्ण एवं सापेक्ष रूप से सहायता में तेजी से गिरावट आई है। विकासशील देशों को सामूहिक सहायता असली मायने में 4.9 अरब डॉलर प्रति वर्ष से घट कर 3.2 अरब डॉलर हो गयी है यानी 1990 के आरंभ से दी गयी कुल सहायता के 12 प्रतिशत से घटकर 3.5 प्रतिशत। सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। उप सहारा अफ्रीका मे वित्तीय सहायता एक अरब डॉलर मात्र है, जो 1990 के स्तर से आधी है। इस प्रवृत्ति को उलटना अति आवश्यक है।

आगे क्या किया जाए

जल प्रबंधन के क्षेत्र में देशों के सामने अलग–अलग चुनौतियां हैं लेकिन सफल नीतियों के लिए अपरिहार्य शर्तो के साथ–साथ कुछ व्यापक मुद्दे उभरते हैं–

- एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन नीतियां विकसित करना जो राष्ट्रीय जल उपयोग के स्तर को पर्यावरणीय दीर्घकालिकता की सीमाओं के अन्तर्गत निर्धारित करें और सभी जल संसाधनों के लिए एक सुसंगत योजना ढांचा मुहैया कराएं।

- एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के केन्द्र मे समानता और गरीबों का हित सर्वोपरि रखें।

- जल प्रबंधन को राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन नीतियों का अनिवार्य अंग बनाएं।

- उचित मूल्य निर्धारण नीतियों, संशोधित राष्ट्रीय लेखा प्रक्रिया और आवश्यकता से अधिक उपयोग को बढ़ावा देने वाली विकृत सब्सिडी की समाप्ति के माध्यम

समाज के सबसे गरीब और संवेदनशील लोगों के लिए जल की उपलब्धता संस्थानों द्वारा विरोधी दावों की मध्यस्थता और प्रबंधन के आधार पर तय की जाएगी– जिसमें यह भी महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकारें राष्ट्रीय नीतियों के केन्द्र में समानता के मुद्दे को रखती हैं?

आकृति 15 लाखों लाख लोग भूखे हैं, इन में छोटे किसान भी शामिल हैं

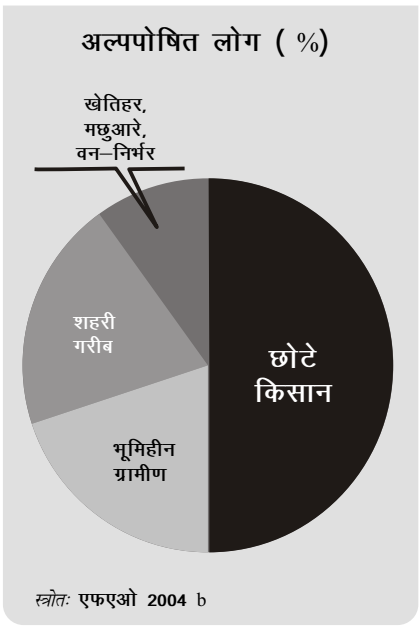

स्रोतः एफएओ 2004 b

से जल के वास्तविक मूल्य को पहचानना।

- बेकार जल के सुरक्षित उपयोग के प्रावधान के अन्तर्गत औद्योगिक और घरेलू कचरे को अलग करना और स्वास्थ्य जोखिम घटाने के लिए,किसानों के साथ काम करके, गरीबोंकी पक्षधर जल आपूर्ति में वृद्धि करना।

- भण्डारण और बाढ़ नियंत्रण सहित, जल संरचना के लिए राष्ट्रीय निवेश और अन्तर्राष्ट्रीय सहायता निवेश बढ़ाना।

- राष्ट्रीय जल प्रबंधन नीतियों और सहायता प्रयासों हेतु अनुकूलन नीतियों पर अधिक बल देकर वैश्विक तापमान के प्रति जवाबदेही में पुर्नशोधन करना।

- सन् 2010 तक कृषि क्षेत्र की वित्तीय सहायता तीन गुना करना जिससे राष्ट्रीय अंशदान 3 अरब डॉलर से बढ़कर 10 अरब डॉलर हो जाय। इस व्यापक प्रावधान के अन्तर्गत अफ्रीका को वित्तीय सहायता 0.9 अरब डालर से बढ़ाकर लगभग 2.1 अरब डॉलर प्रतिवर्ष करनी होगी जैसाकि अफ्रीकी संघ के विस्तृत अफ्रीकी कृषि विकास कार्यक्रम तथा अफ्रीका के विकास हेतु नयी भागीदारी के अन्तर्गत कृषि कार्यों के लिए प्रस्तावित था।

कृषि में जल के लिए प्रतिस्पर्धा का प्रबंधन

एक सौ बरस पहले लास एन्जिलिस जल विभाग के अधीक्षक विलियम मलहालेंड, ने शहर की जल की कमी की समस्या का समाधान एक असरदार निर्दयतापूर्ण नई प्रक्रिया ''जल हथियाना'' द्वारा किया था। 200 मील से अधिक दूर, ओवेन्स घाटी के किसानों द्वारा उपयोग किए जा रहे जल को जबर्दस्ती शहर में स्थानान्तरित कर उन्होंने लास एन्जिलीस को अमेरिका के सबसे तेजी से विकसित होनेवाले शहर के रूप में स्थापित किया था।

जमाना बदल गया है। आज केलिफोर्निया के लोग जलसम्बन्धी झगड़ों को अदालतों में निपटाते हैं। लेकिन अधिकांश विकासशील देशों में जल के लिए प्रतिस्पर्द्धा चौकाने वाली गति से बढ़ रही है– हिंसक संघर्ष हो रहे हैं। इस बात की बहुत आंशका है कि गरीबी और मानव विकास के प्रति चिंता किये बिना मलहालेंड जैसा प्रयोग नये रूप में दोहराया जाएगा।

देशों में प्रतिस्पर्धा पैटर्न अलग–अलग तरह के होते हैं। लेकिन मुख्यतः दो प्रवृत्तियां देखी जाती हैं। पहली, जैसे–जैसे शहरी केंद्रों और उद्योगों में जल की मांग बढ़ती है, कृषि क्षेत्र को कम पानी मिलने लगता है। दूसरे, कृषि के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा तीव्र होती जाती है। दोनों ही मोर्चों पर, इस बात की आंशका है कि कृषि, और विशेष रूप से ग्रामीण परिवार इस समायोजन के फलस्वरूप कष्ट झेलेंगे।

इस के वैश्विक गरीबी उन्मूलन पर गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। तेजी से शहरीकरण होने के बावजूद, विश्व के अधिकांश बहुत गरीब लोग अभी भी देहाती क्षेत्रों में निवास करते हैं– और छोटे किसान तथा खेतिहर मजदूर वैश्विक कुपोषण के अधिक संख्या में शिकार होते हैं। अधिकांश देशों में पानी का एकमात्र सबसे बडा उपयोगकर्त्ता होने के कारण, सिंचित खेती गहरे दबाव में आ जाएगी। कृषि उत्पादकता बढ़ाने, बढ़ती हुई आबादी को भोजन मुहैय्या कराने और गरीबी घटाने में इन प्रणालियों की भूमिका देखते हुए यह मानव विकास के लिए बड़ी चुनौती है।

आर्थिक और राजनीतिक ढांचों के माध्यम से मध्यस्थता

जल संसाधन की मांग बढ़ने के साथ, उपभोगकर्ताओं और क्षेत्रों के बीच पुनः आंवटन अनिवार्य होता है घटते हुए संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा की किसी प्रक्रिया के अन्तर्गत विरोधी दावे आर्थिक और राजनीतिक ढांचों और अधिकारों और हक की प्रणालियों के माध्यम से

निपटाये जाते हैं। जैसे–जैसे जल के लिए

प्रतिस्पर्धा क्रीव होती जायेगी, इसकी प्राप्ति विभिन्न दावेदारों के दावों की ताकत के आधार पर तय की जायेगी। समाज के सबसे गरीब और संवेदनशील लोगों के लिए जल की उपलब्धता संस्थानों द्वारा विरोधी दावों की मध्यस्थता और प्रबंधन के आधार पर तय की जाएगी– जिसमें यह भी महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकारें राष्ट्रीय नीतियों के केन्द्र में समानता के मुद्दे को रखती हैं?

कार्यकुशलता और समता के बीच संतुलन

समायोजन प्रक्रियाएं लगातार चल रही हैं। शहर और उद्योग अपनी जलीय पहुंच देहाती क्षेत्रों में फैला रहे हैं जिसके फलस्वरूप झगड़े और हिंसक विवाद पैदा हो रहे हैं। देश के भीतर विभिन्न भागों में और विभिन्न उपयोगकर्ताओं के मध्य समानान्तर संघर्ष प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं।

निजी जल बाजार एक प्रणालीगत समस्या का संदेहास्पद समाधान प्रस्तुत करते हैं। अमेरिका में भी, जहां उन्हे सुविकसित कानून और संस्थाओं का समर्थन प्राप्त है, गरीबों के हितों की रक्षा करना अक्सर मुश्किल हो जाता है। 1970 के दशक में चिली में जल बाजारों के उभरने से कार्यकुशलता बढ़ी लेकिन शक्ति के केंद्रीयकरण और अधूरी सूचना के कारण असमानता और बाजार विघटन का स्तर काफी बढ़ गया। विकासशील देशों में कमजोर संस्थानगत क्षमता के कारण, बाजार की स्पष्ट सीमाएं हैं।

आवंटन और लाइसेंस प्रणाली का प्रबंधन

जल–बाज़ारों के अलावा, अनेक सरकारें संख्यात्मक आंवटन और लाइसेन्स प्रणाली द्वारा समायोजन दवाबों का प्रबंधन करना चाह रही हैं। यह विधि अधिक संभावनापूर्ण है। हालांकि यहां भी औपचारिक और अनौपचारिक शक्ति असंतुलन अक्सर गरीबों की स्थिति को कमजोर कर देते हैं। पश्चिमी जावा और इंडोनेशिया में कपड़ा कारखानों ने छोटे किसानों के जल

आकृति 16 एशिया में वैश्विक सिंचित भूमि का आधे से अधिक है

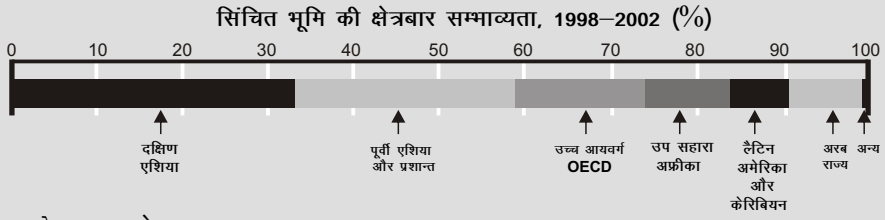

स्रोतः एफ.ए.ओ. 2006

आकृति 17 अनेक विकासशील देशों में कम गरीबी सिंचाई से जुड़ी हुई है।

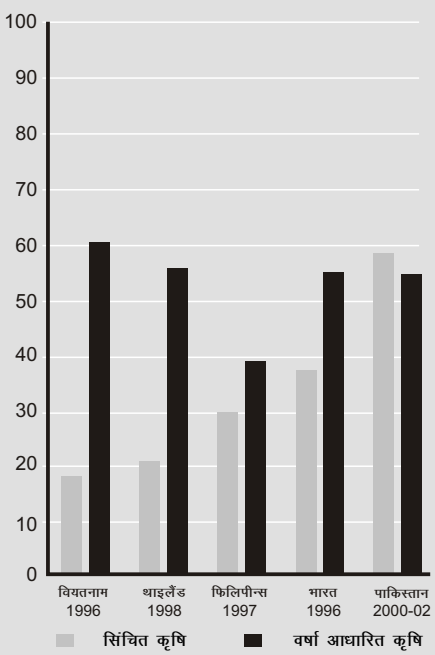

टिप्पणी: हर देश के चुने स्थलो से एकत्र डैटा के आधार पर

स्रोतः हुसैन एंड हांजरा 2003

अधिकार हथिया लिए हैं और फिलिपीन्स में सिंचाई योजनाओं में किसान नगरीय उपयोगकर्ताओं से हार गए हैं। नियमों को लागू न कर पाना या उनका अभाव एक सशक्त संकट है। भारत में भवानी नदी से अनियमित जल दोहन के फलस्वरूप सिंचाई प्रणालियों में जल की कमी बढ़ी है।

कृषि क्षेत्रों में मानव सुरक्षा के लिए जल अधिकार बहुत जरूरी हैं। जल के हक अचानक समाप्त होने या कम होने से आजीविका घट जाती है, असुरक्षा और बड़े पैमाने पर गरीबी बढ़ जाती है। अमीरों की अपेक्षा गरीबों के लिए जल अधिकार

अहम होते हैं– ग़रीब लोगों के पास वित्तीय संसाधनों और कानून आधारित प्रणाली में अपने हितों की रक्षा हेतु राजनीतिक आवाज़ का अभाव होता है। यदि उनके कार्यान्वयन से शक्ति सम्पन्न लोगों को लाभ पहुंचता है तो जल अधिकार महत्वहीन हो जाते हैं।

औपचारिक और रिवाजी अधिकारों में संतुलन

उप सहारा अफ्रीका के सम्मुख प्रत्यक्ष चुनौतियां हैं। दानदाताओं के सहयोग से सरकारें, सिचाई क्षेत्रों का विस्तार कर रही हैं तथा रिवाजी अधिकारों के पूरक या प्रतिस्थापन के रूप में अधिकारों की औपचारिक प्रणालियां स्थापित कर रही हैं। मानव विकास पर इसका क्या प्रभाव होगा ?

नतीजे जन–नीतियों पर निर्भर होंगे। सिंचाई क्षमता का विस्तार महत्वपूर्ण होता क्योंकि इसमें उत्पादकता बढ़ाने और जोखिम घटाने की क्षमता होती है। यह क्षेत्र वर्षा सिंचित कृषि पर अत्यधिक निर्भर है। लेकिन सिंचाई के आधारभूत ढांचे एक नाकाफी और विवादित संसाधन हैं। (आकृति 15) पश्चिमी एशिया के सहेल क्षेत्र के प्रमाण दर्शाते हैं कि सिंचाई की प्रतिस्पर्धा में छोटे कृषक बड़े व्यवसायिक उत्पादकों से हार जाते हैं।

रिवाजी अधिकारों का प्रबंधन और ही समस्याएं पैदा करता है। कुछ मान्यताओं के विपरीत जल के रिवाजी अधिकारों में विस्तृत प्रबंधन सन्निहित होता है और वे पर्यावरणीय दीर्घकालिकता के प्रावधानों का उपयोग करते हैं। लेकिन वे अक्सर गरीब परिवारों तथा स्त्रियों के लिए नुकसानदेह होते है। औपचारिक नियमों और कानूनों को लागू करने से तस्वीर स्वतः नहीं बदल जाती। सेनेगल नदी घाटी में रिवाजी अधिकारधारकों ने जल के सामाजिक बहिष्कार को बनाए रखने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। इसी बीच, तन्जानिया में औपचारिक जल अधिकारों के लागू होने से पंगानी नदी पर बसनेवाले व्यवसायिक कृषकों को फायदा पहुंचा और नदी के नीचे की ओर बसनेवाले छोटे कृषकों को नुकसान हुआ।

समता पर अधिक ध्यान देना

जल सुधारों से एक सबक मिलता है कि समता पर अधिक जोर देना चाहिए। उदाहरण के लिए भूमिसुधारों के विपरीत वितरण सम्बन्धी मुद्दे एकीकृत जल संसाधन एजेण्डा में प्रमुख रूप से नहीं उभरे। कुछ अपवाद हैं– जैसेकि दक्षिण अफ्रीका में– लेकिन यहां भी पुर्नवितरण करनेवाले परिणाम प्राप्त करना कठिन साबित हुआ है।

सिंचाई प्रणालियां समायोजन के केन्द्र में रहती हैं। सिचाई के आधारभूत ढांचों का गरीबी पर खास असर पड़ता है। अ

न्तःदेशीय अनुसंधान दर्शाते हैं कि गरीबी का प्रसार सिंचाई नेटवर्क के भीतर, बाहर की तुलना में 20 प्रतिशत–40 प्रतिशत, कम होता है, परन्तु अन्तर काफी रहता है (आकृति–16) सिंचाई कुछ देशों की तुलना में अन्य देशों में गरीबी घटाने का अधिक सशक्त प्रेरक होती है। भूमि असमानता एक प्रधानकारक होता है। अधिक असमान देश (भारत, पाकिस्तान और फिलिपीन्स) कार्यकुशलता और समता की दृष्टि से अधिक समान देशों (चीन और वियतनाम) की अपेक्षा खराब प्रदर्शन करते हैं। (आकृति–17)

यह नतीजा दर्शाता है कि बढ़ते उत्पादन और गरीबी कम करने से सिंचाई का अंर्तजात व्यापारिक सम्बन्ध नहीं है। कृषि में, उन उपायों के माध्यम से समायोजन दबावों के प्रबंधन में बड़ी भूमिका रहती है जो आपसी मजबूत सुचक्र में कार्यकुशलता, कार्यकुशलता और समता में वृद्धि करते हैं। समान मूल–भागीदारी, गरीबों का पक्षधर जलनिवेश और प्रबन्धन में उत्पादकों की भागीदारी सकल सुधारों की कुंजी हैं।

गहरी लिंग असमानता पर ध्यान देना

सिंचाई प्रणाली में वास्तविक

मजबूती के लिए गहरी लिंग असमानताओं पर ध्यान देने के उपाय जरूरी हैं। सिंचाई प्रणाली में स्त्रियों को दोहरी मार झेलनी पड़ती है।

अनेक देशों में भूमि के औपचारिक अधिकारों का अभाव होने के कारण, उन्हें सिंचाई प्रणाली प्रबंधन से बहिष्कृत कर दिया गया है। साथ ही, अनौपचारिक असमानताएं –जिनमें श्रम का घरेलू विभाजन, जनता के बीच बोलने के औरतों के मानदण्ड और अन्य कारक शामिल हैं–औरतों की निर्णय करने में कारगर आवाज के विरूद्ध विरोध प्रकट करते है।

यहां तक कि प्रबंधन प्राधिकरण को सरकारी एजेन्सियों से उपयोगकर्ताओं को स्थानांतरित करने की महत्वकांक्षी योजनाओं में भी इन संरचनाओं को तोड़ना मुश्किल साबित हुआ है। भारत मेंआन्ध्र–प्रदेश में प्रबंधन में गरीबों की भागीदारी काफी है– लेकिन गरीब खेतिहर स्त्रियां अभी भी चुप हैं। फिर भी, बदलाव संभव है। युगान्डा में जल उपभोगकर्ता संस्थाओं में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व का कानून बनने से फर्क पड़ा है।

गरीबों तक पहुंचना

भविष्य की ओर देखें तो बडी चुनौतियों में से एक है बढ़ी हुई जल उत्पादकता को गरीब तक पहुंचाना। तकनीक अपने वितरण प्रभाव में निष्पक्ष नहीं होती–और आंशका रहती है कि प्रति बूंद अधिक फसल के प्रयास जल संसाधनों के मामले में गरीब परिवारों की उपेक्षा करेंगे।

ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत में भूजल संकट के प्रत्युत्तर में लघु पैमाने पर जल–संग्रह के कार्यकमों को पुर्नजीवित करने से निवेश के अच्छे परिणामों की क्षमता बड़े प्रतिफल के रूप में प्रदर्शित हुई है। और साथ ही साथ जोखिम और संवेदनशीलता में कमी हुयी है। इसी प्रकार सूक्ष्म–सिंचाई तकनीक केवल बड़े पूंजीबहुल उत्पादकों के हित के लिए नहीं होना चाहिए। बूंद सिंचाई के लिए नवीन डिजायन और कम मूल्य वाली तकनीकें व्यापक रूप से अपनायी गयी हैं। यहां भी सामाजिक और आर्थिक प्रतिफल बहुत अधिक है। एक अनुमान के मुताबिक दस करोड़ छोटे किसानों को मुहैय्या करायी गयी कम कीमतवाली सिंचाई तकनीकों से 100 अरब डॉलर का शुद्ध लाभ हुआ, साथ ही आय और रोजगार पैदा होने की दर कई गुना अधिक बढ़ी।

जिस तरह विकासशील देशों की सरकारें जल प्रबंधन में समता और कार्यक्षमता के लक्ष्य में सन्तुलन की चुनौती पर ध्यान देती हैं उसका मानव विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। गरीब के हितों को एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन नीतियों के केन्द्र में रखना एक संगठनात्मक सिद्धान्त है। लेकिन सिद्धान्त को व्यावहारिक गरीबों की पक्षधर नीतियों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इनमे से सबसे महत्वपूर्ण हैं

- गरीब परिवारों के जल और भूमि अधिकारों को सशक्त बनाना।
- रिवाजी अधिकारों का आदर करना और इन अधिकारों की औपचारिक कानूनी प्रणाली में एकीकृत करना।

सीमापार जल प्रबन्धन एक मानव विकास मुद्दा

सहयोग द्वारा संघर्ष क्षमता को घटाया जा सकता है। और जल बंटवारे की गुणवत्ता में सुधार; समृद्धता पैदा कर और अधिक सुरक्षित जीविका द्वारा लाभान्वित हुआ जा सकता है।

- गरीब लोगों के जल अधिकारों की रक्षा कानून शक्त बनाकर और जिम्मेदार संस्थाओं के माध्यम से करके उनकी क्षमता में वृद्धि करना।
- सिंचाई में राष्ट्रीय निवेशों को बढ़ाना और सिंचाई क्षेत्र में की गयी आर्थिक कटौतियों को वापस चालू रखना, उन्हें अगले 20 वर्षो में प्रतिवर्ष लगभग 4 बिलियन डालर तक दो गुना करना।

जलीय अन्योन्याश्रितता के साथ गहरी अन्योन्याश्रितता का भाव पैदा होता है। उत्पादक संसाधन के रूप में, जल अद्वितीय है क्योंकि इसका प्रबंधन किसी एक उपयोग के लिए कभी नहीं किया जा सकताः यह उपयोगकर्ताओं और क्षेत्रों के मध्य बहता है।

- सिंचाई प्रणालियों के अन्तर्गत क्षमता बढ़ाना जिससे दीर्घकालिक और समतापरक मूल्य– विभाजन तन्त्रों के माध्यम से गरीबी घटाने और कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायता मिल सके।
- प्रबंधन का विकेन्द्रीकरण करना और सिंचाई प्रणाली को सशक्त बनाना जिससे उपभोक्ता सशक्त हों।
- व्यापक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में सिंचाई विकास एकीकृत करना जिससे कृषि छोटे किसानों के लिए अधिक लाभदायक हो जाए।
- छोटे पैमाने से बड़े पैमाने तक की आधारभूत संरचनावाली एकीकृत जलसंग्रह और भू–जल नीतियां विकसित करना।
- गरीबों की पक्षधर तकनीकों के विकास, वितरण और अपनाने को बढ़ावा देना।

मानव विकास के लिए सीमापार जल प्रबंधन

जल मानव अन्योन्याश्रितता का एक स्त्रोत है। किसी भी देश में जल एक साझा संसाधन होता है जो अनेक क्षेत्रों में काम आता है– पर्यावरण से लेकर कृषि तक, उद्योग और घर में। लेकिन जल एक चरम पलायक स्त्रोत भी होता है। यह राष्ट्रीय सीमाएं लांघता है, उपभोगकर्त्ताओं को जलीय अन्योन्याश्रितता प्रणाली में सीमापार जोड़ता है।

जैसे–जैसे देशों में पानी के लिए प्रतिस्पर्धा तीव्र होगी, अनुगामी दवाब राष्ट्रीय सीमाओं के पार फैलेगा। कुछ आलोचक आंशकित हैं कि सीमापार प्रतिस्पर्धा संघर्ष और भावी मुद्दों का स्त्रोत बन जायेगा। यह भय अतिरंजित हैः संघर्ष की अपेक्षा सहयोग जीवन का व्यापक तथ्य है। हालांकि अधिकांश देशों में जल बंटवारे और देशों के भीतर विवाद सुलझाने के संस्थानगत तंत्र मौजूद हं लेकिन सीमापार संस्थागत तंत्र काफी कमजोर है। जल के तनाव की अंर्तक्रिया और कमजोर संस्थान विवाद के असली जोखिम के कारण हो सकते हैं।

जलीय अन्योन्याश्रितता

जलीय अन्योन्याश्रितता कोई अमूर्त धारणा नहीं है। दुनिया के पांच में से दो लोग अंतर्राष्ट्रीय जल मुहानों पर रहते हैं जिनमें एक से अधिक देशों की साझेदारी होती है (तालिका 1) अंतर्राष्ट्रीय नदियां एक सूत्र होती हैं जो देशों को जोड़ती हैंः

तालिका 1: 39 देश अधिकांश जल अपनी सीमाओं के बाहर से प्राप्त करते है।

क्षेत्र	देश जो बाह्य स्त्रोतों से 50 प्रतिशत और 75 प्रतिशत जल प्राप्त करते हैं।	देश जो बाह्य स्त्रोतों से 75 प्रतिशत से अधिक जल प्राप्त करते है।
अरब राज्य	ईराक, सोमालिया, सूडान, सीरियाई अरब गणराज्य	बहरीन, मिस्त्र, कुवैत
पूर्वी एशिया और प्रशान्त	कम्बोडिया, वियतनाम	
लैटिन अमरीका और कैरीबियन	अर्हेन्तिना, बोलीविया, पेरूग्वे, उरूग्वे	
दक्षिण एशिया		बांग्लादेश, पाकिस्तान
उप सहारा अफ्रीका	बेनिन, चाड, कांगो एरिट्रिया, जाम्बिया, मोजाम्बीक, नामीबिया	बोत्सवाना, मौरीटानिया, नाइजर
मध्य एंव पूर्वीयूरोप और सी.आई.एस.	अजखैजान, क्रोशिया, लेटीविया, यूक्रेन, उजबेकिस्तान,	हंगरी, मोल्डोवा, रूमानिया, और मोन्टेनेग्रो+ , तुर्कमेनिस्तान
उच्च आय ओ.ई.सी.डी.	लक्जम्बर्ग	नीदरलैन्ड
अन्य	इजरायल	

+जून 2006 में, सर्बिया और मोन्टेनेग्रो अलग होकर स्वतन्त्र हो गये, इन देशों के संबंध में बाध्य जल संसाधनो के पृथक आंकड़े मुद्रण के समय उपलब्ध नहीं थे।

स्त्रोतः FAO 2006

मानचित्र 1 | सिकुड़ता अराल सागरः कपास की पर्यावरणी लागते

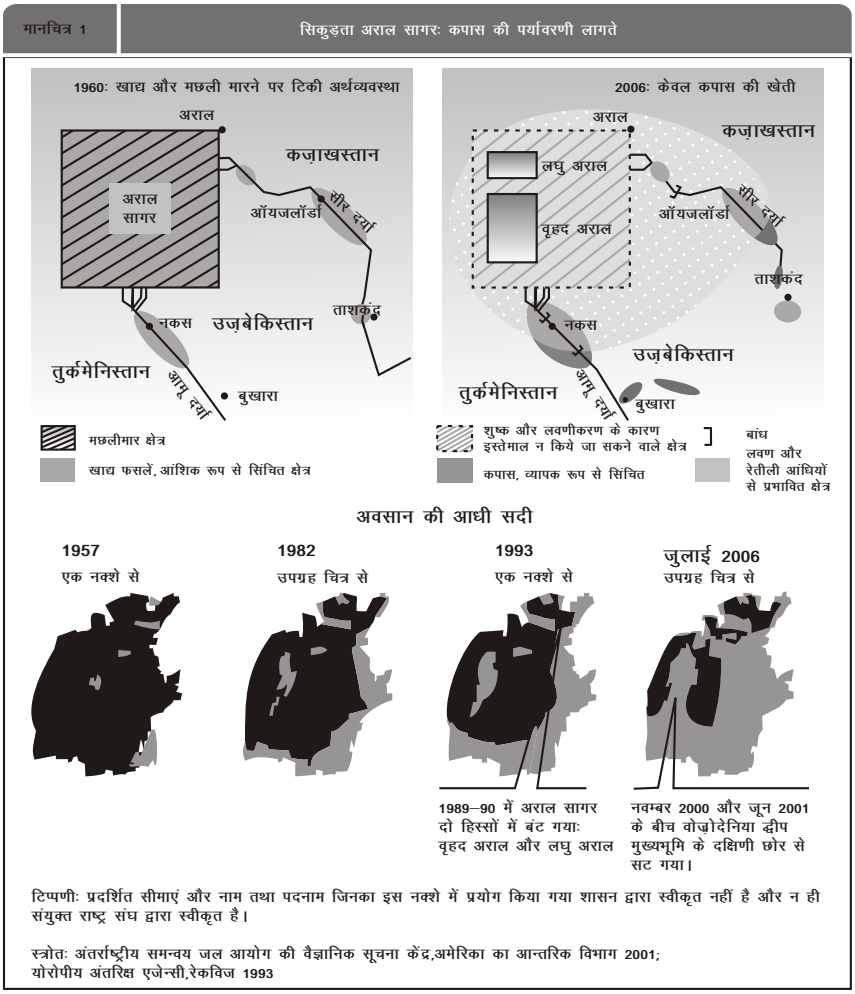

टिप्पणीः प्रदर्शित सीमाएं और नाम तथा पदनाम जिनका इस नक्शे में प्रयोग किया गया शासन द्वारा स्वीकृत नहीं है और न ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत है।

स्त्रोतः अंतर्राष्ट्रीय समन्वय जल आयोग की वैज्ञानिक सूचना केंद्र,अमेरिका का आन्तरिक विभाग 2001; योरोपीय अंतरिक्ष एजेन्सी,रैकविज 1993

उदाहरणार्थ अमेजन में 9 देशों की साझेदारी है और नील में 11 देशों की। नदियां लोगों के जीवनयापन को भी जोड़ती है। मेकोंग की एक विशाल जल प्रणाली चीन में ऊपरी क्षेत्र में विद्युत पैदा करती है और धान उत्पादन तथा मत्स्य पालन प्रणाली का पालन करती है जिससे इसके निचले मुहानों के क्षेत्र में 6 करोड़ से अधिक लोगों का जीवन यापन होता है।

जलीय अन्योन्याश्रितता के साथ गहरी अन्योन्याश्रितता का भाव पैदा होता है। उत्पादक संसाधन के रूप में, जल अद्वितीय है क्योंकि इसका प्रबंधन किसी एक उपयोग के लिए कभी नहीं किया जा सकताः यह उपयोगकर्ताओं और क्षेत्रों के मध्य बहता है। नदी के ऊपरी छोर पर स्थित देश द्वारा नदी का उपयोग नदी के नीचे स्थित उपयोगकर्ताओं को मिलनेवाले जल के परिमाण, समय, और गुणवत्ता को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। यही बात अन्योन्याश्रित जलभृतों और झीलों पर भी लागू होती है।

सीमापार जल प्रबंधन एक मानव विकास का मुद्दा क्यों है?क्योंकि इस क्षेत्र में असफल रहने पर ऐसे नतीजे पैदा होंगे जिनसे असमता, पर्यावरणीय अस्थिरता और व्यापक सामाजिक और आर्थिक हानियां जन्म लेंगी। पश्चिमी किनारे पर बसे इजरायली लोगों द्वारा औसत प्रति व्यक्ति जल उपयोग फिलिस्तीनियों की तुलना में 9 गुना अधिक है जबकि दोनों का जल स्त्रोत एक ही है।

उदाहरणों की कमी नहीं है। अराल सागर, जिसे कुछ लोगों द्वारा दुनिया की सबसे दुखदायी मानव निर्मित पर्यावरणीय आपदा माना जाता है इस विषय पर एक सटीक उदाहरण है (नक्शा 1)। आवश्यकता से अधिक जल प्रणालियों और झीलों का

अस्वच्छ जल तथा खराब सफाई व्यवस्था के कारण पिछली शताब्दी में अनेक जानें गई हैं– और अधिकांश विकासशील देशों में आज भी ऐसा हो रहा है।

उपयोग से होने वाली हानि को कम व्यापक रूप से आंका गया है। उप सहारा अफ्रीका में चाड झील का सिकुड़ना एक उदाहरण है।

असमान जल प्रबंधन के कारण असमानताओं और जल असुरक्षा में वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए कब्जाई गई फिलीस्तीन भूमि पर रहनेवाले लोग तीव्र जल अभाव का सामना कर रहे हैं। सतही जल सीमित रूप में प्राप्त होना एक कारक है लेकिन अधिक महत्वपूर्ण है पश्चिमी किनारे पर इज़राइल और फिलीस्तीन के बीच जलभृतों का असमान बंटवारा।

मानव विकास के लिए सहकारिता के लाभ

साझे जल के प्रबंधन में सफल सहयोग से मानव विकास के लिए अनेक स्तरों पर लाभ हो सकते हैं। सहयोग से विवाद की क्षमता घटाने के अतिरिक्त साझे जल की गुणवत्ता में सुधार के लाभ,समृद्धि पैदा होना, जीवनयापन का अधिक सुरक्षित होना, तथा व्यापक सहयोग का सृजन संभव हो सकता है।

अनुभव सहयोग के सशक्त लाभ तथा असहयोग की कीमत दोनों बताता है। योरोपीय संघ के देशों ने सहयोग से नदी जल के मानकों में नाटकीय ढंग से सुधार किया है। दक्षिणी अफ्रीका में संयुक्त आधारभूत ढांचा योजना के फलस्वरूप लेसोथो के लिए राजस्व पैदा किया जा रहा है और दक्षिण अफ्रीका के लिए पानी में सुधार हुआ है। ब्राजील और पेरूग्वे नेसाझे नदी प्रबंधन के माध्यम से विद्युत पैदा कर लाभ कमाया है। इसके विपरीत मध्य एशिया के देश असहयोग की बड़ी कीमत चुका रहे हैं; सिंचाई और जलविद्युत की भारी हानि उठानी पड़ रही है।

जल युद्ध निराशावादियों के दावों के विपरीत जल विवाद अपवाद ही हैं,नियम नहीं। पिछले 50 वर्षों का इतिहास देखें तो राज्यों के बीच हिंसा की कोई 37 घटनाएं जल संबधी विवादों कारण हुई हैं। इसी दौरान ,200 से अधिक जल–संधियां की गई हैं। इनमें से कुछ संधियां– जैसे सिंधु मुहाने की सन्धि जो भारत–पाकिस्तान के मध्य हुई–युद्ध के दौरान भी चालू रहीं।

सशस्त्र युद्ध न होने के बावजूद, सहयोग अक्सर सीमित रहा है। अधिकांशतः यह जल प्रवाह के तकनीकी प्रंबधन और अनुमापी आवंटन पर केंद्रित रहा है। कुछ नदी मुहानों में पहल– मुख्यतः नील मुहाने की पहल के कारण तस्वीर बदल रही है। हांलाकि सीमित जन समर्थन, कमजोर संस्थानगत क्षमता और धन के अभाव के कारण प्रगति बाधित हुई है। इन सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भागीदारी से अन्तर पड़ सकता है।

जल जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रवाहित होता है। पूरे इतिहास में जल प्रंबधन ने लोगों और सरकारों के सामने दूरगामी तकनीकी और राजनैतिक चुनौतियां प्रस्तुत की हैं। जल प्रबन्धन की कहानी मानवीय कौशल तथा कमजोरी की कहानी है। नवीन तकनीकों के माध्यम प्राचीन रोम के जल सेतु से लेकर 19 वीं शताब्दी के यूरोप और अमेरिका के महान जल संसाधनों तक जीवन के लिए स्वच्छ जल का प्रावधान से किया गया है। इसके साथ ही अस्वच्छ जल तथा खराब सफाई व्यवस्था के कारण पिछली शताब्दी में अनेक जानें गई हैं– और अधिकांश विकासशील देशों में आज भी ऐसा हो रहा है।

जीविका के लिए जल के प्रंबधन का इतिहास और भी लम्बा है। सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया में सभ्यता के अभ्युदय के समय से जल प्रबंधन को कुशल आधारभूत ढांचा प्रणाली के उत्पादक संसाधन के रूप में जाना गया जिसके कारण जल की उत्पादक क्षमता का उपयोग किया गया और विनाशकारी क्षमता को सीमित । इन प्रयासों में असफलता की स्थिति में मानवीय संवेदनशीलता या जलीय चक्र में बदलाव के परिणाम स्वरूप सभ्यताएं नष्ट हुईं, कृषि प्रणाली ढह गई और पर्यावरण का विनाश हुआ। मौसम के बदलाव के संकट तथा दुनिया पर ताजे स्वच्छ जल संसाधन पर बढ़ते दवाब के कारण 21 वीं शताब्दी की जल प्रबंधन चुनौती मानव इतिहास में सबसे भयावह सिद्ध हो सकती है।

जल और स्वच्छता पर विश्व द्वारा कार्य करने के लिए आठ कारण–सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों से सम्बन्ध

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य संसार के निपट गरीबी के उन्मूलन और मानवीय स्वतंत्रता के विस्तार के समयबद्ध लक्ष्य हैं। सन् 2015 तक संख्यात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रतिनिधित्व करने के अलावा, वे साझा विकास प्राथमिकताओं की व्यापक अभिकल्पना को संजोए हुए हैं। इस दृष्टि का मूल यह सहज विचार है कि अत्यधिक गरीबी और अवसरों में बड़ी असमानताएं मानवीय स्थिति का अपरिहार्य लक्षण नहीं –बल्कि एक उपचार योग्य कष्ट है जिसके जारी रहने से हम सब कमजोर कमजोर पड़ जाते हैं और जो हमारी सामूहिक सुरक्षा और समृद्धि के लिए खतरा है।शताब्दी विकास लक्ष्य के बहुपक्षीय उद्देश्य, निपट गरीबी उन्मूलन से लेकर लिंग समानता, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पर्यावरण तक विकास के अंर्तसम्बद्ध आयामों की व्यूहरचना को भेदते हैं। प्रत्येक आयाम अंर्तक्रियाओं के जटिल संजाल से जुड़ा हुआ है। किसी क्षेत्र की दीर्घकालिक प्रगति आवश्यक रूप से अन्य क्षेत्रों में प्रगति पर निर्भर है। किसी एक क्षेत्र में प्रगति का अभाव होने से एक विशाल मुद्दे पर सुधार होने में बाधा उपस्थित हो सकती है। जल और स्वच्छता के बीच सशक्त गठजोड़ दिखाई देता है। इन क्षेत्रों में तेज प्रगति नहीं होने पर अनेक देश सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकेंगे। दुनिया के लाखों सबसे गरीब लोगों को परिहार्य गरीबी के हवाले करने के अलावा खराब स्वास्थ्य और घटते अवसर देशों के भीतर और बाहर गहरी असमानताएं बनाएं रखेंगे। हालांकि मानव विकास के अंतर्गत और भी बहुत कुछ आता है जो सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों के अंतर्गत प्रस्तावित है, लक्ष्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के बीच की कड़ियों को समझने और जल तथा स्वच्छता की प्रगति के जरूरी महत्व के लिए एक उपयोगी ढांचा उपलब्ध किया गया है।

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य	सरकारों को कार्यवाही क्यों करनी चाहिए	सरकारों को किस प्रकार कार्यवाही करनी चाहिए

लक्ष्य–1 गरीबी और भूख समाप्त करना	• स्वच्छ जल और पर्याप्त सफाई का अभाव गरीबी और कुषोपण का प्रमुख कारण होता है।
	  • विकासशील देशों में 5 में से एक व्यक्ति–कुल 1.1 अरब – उन्नत जल स्त्रोत तक पहुंच से वंचित है।
	  • दो में से एक व्यक्ति–कुछ 2.6 अरब लोग–पर्याप्त सफाई से वंचित है।
	  • विकासशील देशों में बीमारियां और उत्पादकता हानियां जो जल और सफाई से जुड़ी है सकंल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत हैं, उप सहारा अफ्रीका में बढ़कर 5 प्रतिशत हो गई हैं– जो क्षेत्र को मिलनेवाली आर्थिक सहायता से अधिक है।
	  • अधिकांश सबसे गरीब देशों में केवल गरीब 25 प्रतिशत सबसे गरीब परिवारों को घर में नल से पानी मिलता है जबकि अमीर देशों में यह 85 प्रतिशत है।
	  • गरीब परिवारों को अमीर परिवारों तुलना में 10 गुना अधिक भुगतान करना पड़ता है।
	• एक डॉलर प्रतिदिन से कम पर गुजर कर रही दुनिया की आबादी का पचास प्रतिशत छोटे कृषक है जिनके लिए जल एक अत्यावश्यक उत्पादक निवेश है ।
	• कृषि के लिए जल को उद्योग की ओर पुनः आवंटित करने के बढ़ते दवाब के कारण गांवों में गरीबी का संकट पैदा हो गया है।
		• स्हस्त्राब्दि विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जल और सफाई को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की मुख्यधारा में लाने के लिए नीतियों के उद्देश्य होने चाहिएः
		  • पानी की प्राप्ति को मानव अधिकार का दर्जा दिया जाये और उस अधिकार के उत्तरोत्तर क्रियान्वयन के लिए कानून लाया जाय जिसके अनुसार यह सुनिश्चित हो कि सभी व्यक्तियों को कम से कम 20 लिटर स्वच्छ जल प्रतिदिन प्राप्त हो सके।
		  • शहरी क्षेत्रों में जल के संजाल के विस्तार के लिए जल निवेश को बढ़ाया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रावधानों का विस्तार किया जाए।
		  • "जीवन रेखा कर" और छूटें लागू कर सुनिश्चित किया जाए कि किसी को जल से वंचित न रहना पड़े, जिसमें जल पर घरेलू आय के 3 प्रतिशत का व्यय लक्ष्य रखा जाए।
		  • कार्यक्षमता में सुधार कर समता बढ़ाने के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जल सेवाओं को नियंत्रित करना।
		• ऐसी जन नीतियों को लागू करना जिनके द्वारा कृषि हेतु जल संसाधन के विकास में टिकाऊपन और समता का मिश्रण हो।
		• गरीबों की पक्षधर सिंचाई तकनीकों का विकास और उन्हें अपनाने में सहायता करना।

जल और स्वच्छता पर विश्व द्वारा कार्य करने के लिए आठ कारण–सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों से सम्बन्ध

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य	सरकारों को कार्यवाही क्यों करनी चाहिए	सरकारों को किस प्रकार कार्यवाही करनी चाहिए
लक्ष्य–2 सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा	• दूर से पानी ढो कर लाने के कारण लाखों लड़कियां स्कूल नहीं जा पातीं और निरक्षरता तथा सीमित विकल्पों के कुचक्र मे फंस जाती है। • जल–संबंधी बीमारियां जैसे डायरिया और परजीवी संक्रमण की कीमत प्रतिवर्ष 4.43 करोड़ स्कूल दिनों की हानि के रूप में चुकानी पड़ती है– जो इथियोपिया के सभी 7 वर्ष के बच्चों के पूरे वर्ष के बराबर है– और उससे पढ़ने की सामर्थ्य समाप्त हो जाती है • अनेक देशों में स्कूलों में जल और सफाई के अपर्याप्त प्रावधान बाल स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करते हैं। • स्कूलों में जल और सफाई का अभाव लड़कियों के स्कूल छोड़ने का एक प्रधान कारण होता है। • खराब जल एवं सफाई व्यवस्था के कारण फैले परजीवी संक्रमण से 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों की सीखने की क्षमता घट जाती है	• नितियों और लक्ष्यों को सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य से जोड़ना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक विद्यालय में जल और सफाई के पर्याप्त प्रावधान हों; लड़कियों के लिए अलग सुविधाएं हों। • विद्यालय पाठ्यक्रम में स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान को शामिल किया जाए, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य जोखिम कम हों तथा वे अपने समाज में परिवर्तन के दूत बन सकें। • विद्यालयों और समाज में जनस्वास्थ्य कार्यक्रम स्थापित करके जल संबंधी संक्रामक रोगों की रोकथाम और उपचार।
लक्ष्य–3 लिंग समानता तथा नारी शक्ति को बढ़ावा देना	• जल और सफाई से वंचित रहने पर लिंग असमानता बनी रहती है और स्त्रियां अशक्त होती हैं। • स्त्रियां पानी भरने और ढोने में 4 घंटे प्रतिदिन तक खर्च करती हैं। यह गरीबी का मुख्य स्त्रोत हैं। • जल–संक्रमण से बीमार बच्चों की देखरेख में स्त्रियों द्वारा लगाए गए समय के कारण उत्पादक कार्यों में लगने के उनके अवसर कम हो जाते हैं। • अपर्याप्त स्वच्छता को लाखों स्त्रियां अपना सम्मान खोने और असुरक्षा का स्त्रोत मानती हैं। • अनेक देशों में स्त्रियां खाद्य उत्पादन में प्रमुख भूमिका अदा करती हैं लेकिन अपने पानी के अधिकारों को सीमित पाती हैं।	• राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन नीतियों के केंद्र में लिंग समता और जल एवं सिंचाई को रखना • ऐसे कानून बनाना जिनके द्वारा जल समितियों और अन्य निकायों में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व जरूरी हो। • स्त्रियों को जन निवेश निर्णयों और घरेलू खर्च निर्धारित करने में अधिक जोर से आवाज़ उठाने में समर्थ बनानेवाले स्वच्छता अभियानों का समर्थन करना। • संपत्ति अधिकारों, सिंचाई संबधी नियमों तथा अन्य जल उपयोगकर्त्ता समितियों में सुधार करना जिससे स्त्रियों को समान अधिकार मिलना सुनिश्चत किया जा सके।
लक्ष्य– 4 बालमृत्यु की दर मे कमी	• गंदे पानी और खराब सफाई व्यवस्था के कारण 18 लाख बच्चों की मौत प्रतिवर्ष डायरिया से हो जाती है–लगभग 5000 प्रतिदिन–बच्चों की मौत का यह दूसरा सबसे बड़ा कारण है। • स्वच्छ जल और सफाई उपलब्ध करवाकर बच्चों की मौत के खतरे में 50 प्रतिशत तक की कमी की जा सकती है। • गंदे जल के कारण डायरिया होना दुनिया के सबसे बड़े हत्यारों में से एक है, जिससे एच.आई.वी./एड्स के कारण होनेवाली मौतों से पांच गुना मौतें हो जाती हैं।	• जल एंव स्वच्छता से बच्चों की मौत के उपचार को राष्ट्रीय आपातकाल के समान महत्व देना और उसे मानव अधिकारों के उल्लंघन के रूप में मानना। • डायरिया की रोकथाम और इलाज में मूलभूत स्वास्थ्य की देखरेख के प्रावधान को सशक्त बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता उपयोग करना। • बच्चों की मौत कम करने और जल तथा स्वच्छता की सुलभता में विस्तार के लक्ष्य में स्पष्ट रूप से संबंध स्थापित करना।

जल और स्वच्छता पर विश्व द्वारा कार्य करने के लिए आठ कारण–सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों से सम्बन्ध

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य	सरकारों को कार्यवाही क्यों करनी चाहिए	सरकारों को किस प्रकार कार्यवाही करनी चाहिए
	• बच्चों की मौत रोकने का सबसे सशक्त उपाय स्वच्छता और सफाई है: जल और सफाई के मूलभूत स्तर की प्राप्ति सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य प्राप्ति से अगले दशक में 10 लाख से अधिक जानें बचाई जा सकती हैं, पूरे विश्व में प्रावधान किए जाने पर यह संख्या बढ़कर 20 लाख हो जाएगी। • जल से फैलनेवाले रोग सामाजिक अन्याय और विषमताओं को मजबूत करते हैं जिससे गरीब परिवारों के बच्चे अमीर परिवारों के बच्चों की तुलना में 4–5 गुना अधिक मौत का जोखिम उठाते हैं।	• जल और स्वच्छता के लिए जन निवेश और सेवा प्रावधान नीतियों में सबसे गरीब परिवारों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना। • सुनिश्चित करना कि गरीबी उन्मूलन नीतियों के दस्तावेज़ जल, सफाई और बालमृत्यु के बीच संबंधों को पहचानते हैं। • जल और सफाई समस्याओं के कारण हुई बाल–मृत्यु का वार्षिक लेखाजोखा प्रकाशित करना।
लक्ष्य– 5 मां के स्वास्थ्य में सुधार करना	• जल एवं सफाई के प्रावधान से– एनीमिया, विटामिनों की कमी और ट्रैकोमा–जैसे मां के स्वास्थ्य को बिगाड़ने और मां की मौत में योगदान देने वाले कष्ट घटते हैं।	• जल और सफाई प्रावधान को लिंग समानता हेतु नीतियों का मुख्य घटक मानना। • जल और सफाई पर घर में, स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तरों पर निर्णय लेने हेतु नारी को सशक्त बनाना।
लक्ष्य–6 एच.आई.वी/एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से लड़ना	• जल और स्वास्थ्य की अपर्याप्त सुलभता से स्वास्थ्य के अवसर कम होते हैं और लोगों को एच.आई.वी./एड्स से संक्रमण का जोखिम बढ़ जाता है। • एच.आई.वी. संक्रमित मांओं को फार्मूला दूध बनाने के लिए स्वच्छ जल की जरूरत होती है। • जल और स्वच्छता के सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य की प्रप्ति से जल संबधज के संसाधनों में वृद्धि होगी। • खराब सफाई और नाली व्यवस्था के कारण मलेरिया होता है, जिसके कारण प्रतिवर्ष 13 लाख मौतें होती हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं।	• जल और स्वच्छता की राष्ट्रीय और विश्व स्तर की नीतियों को एकीकृत कर मलेरिया से निपटना और एच.आई.वी./एड्स के मरीजों की जीवन स्थितियों में सुधार करना। • सुनिश्चित करना कि एच.आई.वी./एड्स के मरीजों की घरेलू देखभाल के लिए कम से कम 50 लिटर पानी मुफ़्त उपलब्ध हो। • नाली तथा सफाई व्यवस्था में निवेश किया जाए जिससे मक्खियों और मच्छरों की संख्या में कमी हो।
लक्ष्य 7 पर्यावरणीय दीर्घकालिकता सुनिश्चित करना।	• वर्तमान प्रवृत्ति देखते हुए 23.40 करोड़ लोग जल और स्वच्छता के लक्ष्य तथा 43 करोड़ लोग स्वच्छता के लक्ष्य का लाभ पाने से चूक जाएंगे।	• व्यवहारिक उपायों को अपनाना ताकि सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य की प्रतिबद्धता व्यवहारिक रूप से पूर्ण की जा सके। • जल और स्वच्छता की कमियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक नेतृत्व प्रदान करना।
पीने के सुरक्षित पानी और आधारभूत स्वच्छता से वंचित लोगों के अनुपात को आधा करना	• उप–सहारा अफ्रीका में स्वच्छता के नये कनेक्शनों की पिछले दशकों के 70 लाख प्रतिवर्ष की दर को 2015 तक 2.8 करोड़ प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य आवश्यक होगा। • जल और स्वच्छता के क्षेत्र में गति कम होने से अन्य देशों की प्रगति प्रभावित होगी।	• 20 प्रतिशत सबसे गरीब और सबसे अमीरों के बीच जल और स्वच्छता संबंधी विषमताओं को खत्म करने के लिए सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य में प्रावधान जोड़ना। • स्वतन्त्र नियामकों को सशक्त बना कर गरीबों को कुशल सेवाएं मुहैय्या कराने में सेवा प्रदानकर्ताओं की जवाबदेही तय करना।

जल और स्वच्छता पर विश्व द्वारा कार्य करने के लिए आठ कारण–सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों से सम्बन्ध

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य	सरकारों को कार्यवाही क्यों करनी चाहिए	सरकारों को किस प्रकार कार्यवाही करनी चाहिए
पर्यावरणीय संसाधनों की हानि का चक्र उलटना	• जल संसाधनों का अदीर्घकालिक दोहन मानव विकास के लिए बढ़ते हुए संकट की ओर इशारा करता है, जिसके कारण अदीर्घकालिक पर्यावरणीय कर्ज पैदा होता है जो भावी पीढ़ी को हस्तान्तरित होगा। • जल के संकट से ग्रस्त देशों के लोगों की सख्या आज 70 करोड़ से बढकर 2025 में 3 अरब हो जायेगी। • 1.4 अरब लोग वर्तमान समय में नदी के मुहानों पर निवास करते है जहां पानी का उपयोग न्यूनतम रिचार्ज स्तर से अधिक होता है। जिसके फलस्वरूप नदियां सूख रहीं हैं और भूजल का ह्रास होता है। • जल असुरक्षा जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी है के कारण सन 2080 तक 7.5–12.5 करोड़ लोगों में कुषोपण बढ़ने का संकट पैदा होगा जिससे उप सहारा अफ्रीकी देशों में भोजन उत्पादक तत्वों में 25 प्रतिशत की कमी हो जायेगी। • भूजल का ह्रास एशिया और मध्य पूर्व में कृषि प्रणालियों, खाद्य सुरक्षा और जीविका के लिए गंभीर संकट प्रस्तुत करता है।	• जल को कीमती प्राकृतिक संसाधन मानते हुए, पर्यावरणीय दीर्घकालिकता के संदर्भ में दोहन करने की वस्तु न समझा जाए। • राष्ट्रीय लेखाजोखा सुधारा जाय जिससे जल संसाधनों के ह्रास से संबद्ध सही आर्थिक नुकसान प्रदर्शित किये जाएं। • एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन नीतियां लागू की जाए जो पर्यावरणीय दीर्घकालिकता की सीमाओं के अन्तर्गत जल के उपयोग को नियन्त्रित करें जिससे पर्यावरण की जरूरतें पूरी हों। • नीतियों को संस्थानगत बनाया जाय जिसमें पानी के संरक्षण के लिए प्रेरक पुरस्कार राशि का सृजन किया जाय और अदीर्घकालिक जल –पैटर्न को बढ़ावा देनेवाली विकृत सब्सिडी को समाप्त किया जाए । • क्योटो प्रोटोकोल के प्रावधानों को सशक्त बनाकर कार्बन उत्सर्जनों को 450 अंश प्रति मिलियन पर स्थिर करने के लक्ष्य के अनुसार सीमित करना, स्वच्छ तकनीक हस्तान्तरण तन्त्र को बढ़ावा और 2012 तक सभी देशों को उत्सर्जकों मे कमी करने के उद्देश्य से एक अधिक सशक्त बहुपक्षीय ढांचे के अन्तर्गत लाना। • मौसम के बदलाव के प्रभावों से निपटने के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाई जाए।
लक्ष्यः 8 विकास के लिए वैश्विक भागीदारी का गठन ।	• जल और स्वच्छता के क्षेत्र में विश्व स्तर पर कोई असरदार भागीदारी मौजूद नहीं है और उच्च स्तरीय सम्मेलन जल और सफाई को अंतर्राष्ट्रीय एजेन्डा बनाने के लिए आवश्यक गति प्रदान करने में असफल रहे हैं। • अनेक राष्ट्रीय सरकारें प्रगति में वृद्धि करने के लिए नीतियां और वित्त उपलब्ध कराने में असफल हो रही हैं। • गरीबी उन्मूलन नीतियों के दस्तावेजों में जल और सफाई के मुद्दे पर्याप्त रूप से सशक्त नहीं हैं। • अनेक देशों में डायरिया के कारण बढ़ी बाल–मृत्यु दर के प्रमुख कारण जल और स्वच्छता पर उनके सफल घरेलू उत्पाद का 0.5 प्रतिशत से भी कम खर्च किया जा रहा है, जो उनके रक्षा बजटों का एक छोटा से अंश है। • अमीर देश जल और स्वच्छता को अंतर्राष्ट्रीय सहायता भागीदारी में प्राथमिकता दिलाने और इस क्षेत्र में विकास सहायता दिलाने में असली मायनों में असफल रहे है। सहायताराशि में इस क्षेत्र का अंश कुल वित्तीय सहायता की राशि का मात्र 4 प्रतिशत है। • कृषि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता 1990 से एक तिहाई कम हो गयी है जो 12 प्रतिशत से घटकर 3.5 प्रतिशत रह गयी है।	• राजनैतिक कार्यवाही को प्रेरित करने हेतु आठ के समूह की कार्यसूची में जल और सफाई को स्थान देने, संसाधनों को संगठित करने और राष्ट्रीय पोषित योजना प्रक्रियाओं को समर्थन देने के लिए विश्वस्तर पर कार्य योजना में स्थान देना। • ऐसी राष्ट्रीय योजनाएं जो जल और सफाई के सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को मध्यअवधि के वित्तीय प्रावधानों से जोड़ती हैं। • स्थानीय सरकारों और स्थानीय समुदाय को विकेन्द्रीकरण, क्षमता विकास और जल और सफाई हेतु पर्याप्त वित्त (जो कम से कम स.घ. उ. का 1 प्रतिशत हो) के द्वारा सशक्त बनाना। • जल के लिए आर्थिक सहायता को 3.6 अरब डॉलर से 2010 तक 4 अरब डॉलर प्रतिवर्ष तक बढ़ाना जिससे जल सुरक्षा पर मजबूती से ध्यान केंद्रित किया जाए। • 2010 तक कृषि के लिए वार्षिक सहायता को 3 अरब से 10 अरब डॉलर तक पहुंचा देना, जल सुरक्षा पर मजबूती से ध्यान केंद्रित करना।

मानव विकास की स्थिति

महबूब–उल–हक ने सन् 1990 में पहली '' मानव विकास की रिपोर्ट'' में लिखा था ''विकास का मूल उद्देश्य एक सशक्त वातावरण का सृजन करना है जिसमें व्यक्ति दीर्घ, स्वस्थ और रचनात्मक जीवन व्यतीत कर सके।'' 16 वर्ष बाद भी यह स्वप्न पूरा होना बाकी है।

लोग राष्ट्र की असली संपत्ति होते हैंः कभी–कभी इस सहज सच्चाई को भुला दिया जाता है। राष्ट्रीय आय (जैसाकि सकल घरेलू उत्पाद द्वारा निर्धारित किया जाता है) के उतार–चढ़ाव से सम्मोहित होकर हम मानव कल्याण को भौतिक सम्पदा के समकक्ष मानने लगते हैं। सकल घरेलू उत्पाद और आर्थिक स्वामित्व के महत्व को कम नहीं आंका जाना चाहिएः अनेक देशों में इनके अभाव से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ही दीर्घ मानवीय प्रगति के लिए मूलरूप से जरूरी हैं। परन्तु प्रगति के मूल्यांकन का अन्तिम मानदण्ड लोगों के जीवन की गुणवत्ता होता है। जैसाकि अरस्तू ने कहा था,'' संपत्ति स्पष्टतः वह कल्याण नहीं है जिसे हम पाना चाहते हैं; क्योंकि यह केवल उपयोगी होती है और इसका उपयोग किसी और उद्देश्य के लिए होता है।'' वह उद्देश्य मानव की सामर्थ्य की पहचान का अवसर होता है। वास्तविक अवसर लोगों की असली रूचियों से सम्बद्ध होते हैं– यह अभिरूचियां राष्ट्र की समुचित आय, शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और रहन–सहन के रूप में दिखाई देती है। ऐसे राष्ट्र का शासन अत्याचारी द्वारा नहीं किया जाता। जैसा कि अमर्त्य सेन ने लिखा,'' विकास को वास्तविक लोगों द्वारा उपभोग की जा रही आजादी के विस्तार की प्रक्रिया के रूप में में देखा जा सकता हैं।''

पिछले दशकों में विश्व में भौतिक सम्पदा एंव समृद्धि में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। लेकिन यह वृद्धियां बहुत ही असमान रहीं, इस प्रगति में अधिकांश लोगों की भागीदारी नहीं है। निर्धनता, गहरी व्याप्त असमानता और राजनैतिक सार्मथ्य के अभाव के कारण विश्व की विशाल जनसंख्या वास्तविक विकल्प चुनने की स्वतंत्रता से वंचित रहती है। इसके अतिरिक्त सकल घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन अभी भी इस ढंग से किया जाता है जिसमें पर्यावरण की विकृति और घट रहे प्राकृतिक संसाधनों पर ध्यान नहीं दिया जाता।

मानव विकास सूचकांक(मा0वि0सू0)

सन् 1999 से प्रतिवर्ष इस रिपोर्ट के माध्यम से एक मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किया जाता है जो सकल घरेलू उत्पाद से और आगे बढ़कर कल्याण की व्यापक परिभाषा का अवलोकन भी करता है। मा0वि0सू0 मानवीय विकास के तीन संयुक्त पैमाने उपलब्ध कराती हैः दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत करना (जिसे आयुवृद्धि से नापा जाता है) शिक्षा उपलब्ध कराना (जिसका मूल्यांकन प्रौढ–शिक्षा एंव प्राथमिक, द्वितीयक एंव तृतीयक स्तर पर नामांकन द्वारा किया जाता है) एक अच्छा जीवन–स्तर बनाना(जिसका आकलन क्रयशक्ति समतुल्यता, पीपीपी, आय द्वारा किया जाता है) यह सूची मानव विकास का विशद पैमाना नहीं है। उदाहरण के लिए इसमें महत्वपूर्ण सूचक जैसे मानव अधिकार के प्रति आदर, लोकतंत्र और असमानता शामिल नहीं हैं। हां, यह मानव प्रगति और आय तथा कल्याण के बीच जटिल सम्बन्धों को देखने का व्यापक संक्षेत्र उपलब्ध कराती है।

इस वर्ष का मानव विकास सूचकांक जिसका सम्बन्ध सन् 2004 से है, कल्याण और जीवन–अवसरों के बीच की गहरी खाई को उजागर करता है जो हमारे उत्तरोत्तर अंर्तसंबद्ध विश्व को विभाजित करती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जान.एफ.केनेडी ने एक बात कही थी–''उठता हुआ ज्वार सभी नावों को उछाल देता है।'' लेकिन मानव विकास की बात की जाए तो वैश्विक समृद्धि के उठते हुए ज्वार ने

आकृति 1

आय से मा.वि.सू. तक – कुछ देशों का प्रदर्शन दूसरों से बेहतर

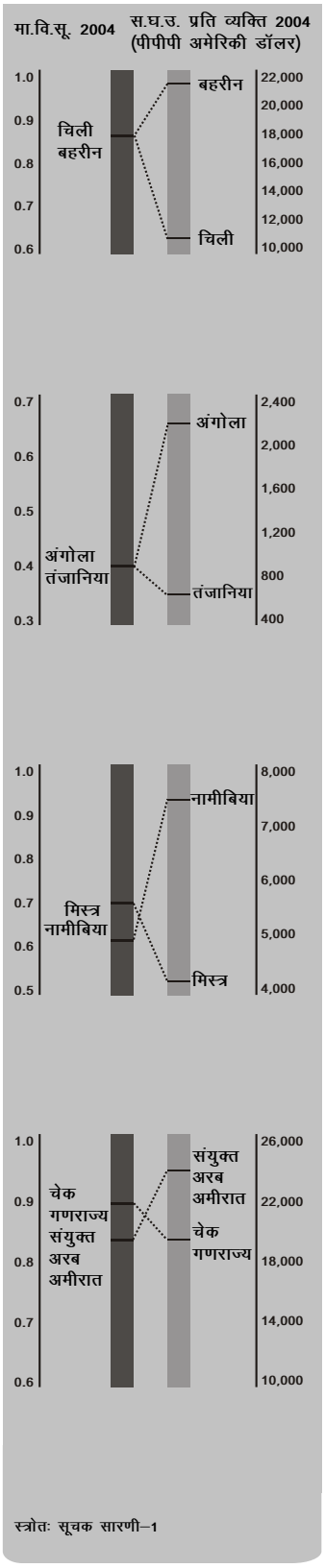

स्त्रोतः सूचक सारणी–1

कुछ नावों को दूसरों की अपेक्षा अधिक उछाल दिया है–और कुछ नावें तेजी से डूब रही हैं। वैश्वीकरण के सकारात्मक पहलुओं पर जोर देने वाले उत्साही लोग कभी–कभी उत्तेजित हो जाते हैं। वे नई व्यवस्था का वर्णन करने के लिए वैश्विक गांव की भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं, लेकिन जन मानवीय विकास की दृष्टि से देखा जाए तो वैश्विक गांव को हम धनवान और निर्धनों की बस्तियों में बंटा हुआ पाते हैं। नार्वे का औसत व्यक्ति(भा0वि0सू0 में सबसे ऊपर) और नाइजर जैसे देशों का औसत व्यक्ति (सबसे नीचे) निश्चय ही वैश्विक गांव के भिन्न–भिन्न मानव विकास मुहल्लों में निवास करते हैं। नार्वे के लोग नाइजर के लोगों की अपेक्षा चालीस गुना समृद्ध हैं। वे उन से लगभग दोगुना जीते हैं और नाइजर के लोगों के 21 प्रतिशत नामांकन दर की तुलना में वह प्राथमिक, द्वितीयक एंव तृतीयक शिक्षा में लगभग सार्वभौम नामांकन का लाभ उठाते है। निम्न मानव विकास श्रेणी के 31 देशों–जो विश्व जनसंख्या का 9 प्रतिशत हैं–में जन्म के समय प्रत्याशित आयु 46 वर्ष है अर्थात उच्च मानव विकास वाले देशों से 32 वर्ष कम।

मा0वि0सू0 एक अन्य प्रमुख विषय को रेखांकित करता है जिसका वर्णन मानव विकास रिपोर्ट में इसकी शुरूआत से ही किया जाता है। औसत मानव विकास के संकेतक आय के साथ–साथ उठते और गिरते हैं। यह खोज आश्चर्यजनक नहीं है। विश्व की वास्तविक स्वतंत्रताओं का अभाव, समुचित पोषण प्राप्त करने और शिक्षा–प्राप्ति की योग्यता से लोगों को वंचित रखने में अति निम्न औसत आय और आय के न होने के कारण गरीबी का योगदान रहता है। भा0वि0सू0 एक तरफ आय और दूसरी तरफ स्वास्थ्य और शिक्षा के बीच सकारात्मक सम्बन्धों को दर्शाता है। अमीर देशों में रहनेवाले लोग अधिक स्वस्थ होते हैं और उन्हें शिक्षा की अधिक सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। यह इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकृष्ट करता है कि कुछ देश अपनी सम्पदा को स्वास्थ्य एंव शिक्षा के अवसरों में परिवर्तत करने में काफी बेहतर हैं।

कुछ देशों का मा0वि0सू0 क्रम उनकी आय के क्रम से काफी नीचे है, जबकि दूसरे इसके विपरीत स्थिति में हैं। उदाहरण के लिए वियतनाम काफी गरीब देश है लेकिन मा0वि0सू0 में उसका क्रम उन अन्य देशों की अपेक्षा जिनकी प्रति व्यक्ति आय काफी अधिक है ऊपर है। इसके विपरीत, बहरीन की औसत आय चिली से लगभग दोगुनी है लेकिन हाल की प्रगति के बावजूद शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्रों में पीछे होने के कारण मा0वि0सू0 क्रम में यह चिली से नीचे है। उप–सहारा अफ्रीका में तन्जानिया की औसत आय अंगोला की आय की एक तिहाई है, लेकिन मा0वि0सू0 में उनका क्रम समान है। यह अंगोला संघर्ष के फलस्वरूप उच्च मानव लागत को दर्शाता है।(आकृति 1)

मा0वि0सू0 को सरकारें अक्सर पड़ोसी देशों की तुलना में अपने कार्य के मूल्यांकन के एक उपकरण के रूप में देखती हैं। कहा जा सकता है मानव विकास में प्रतिस्पर्धा एक अच्छी स्पर्धा है–सकल घरेलू उत्पाद की स्पर्धा के मुकाबले अधिक स्वस्थ–फिर भी, आवश्यक मुद्दों की उपेक्षा करना सरकारों की प्रवृत्ति बन गई है। जिसके कारण वैश्विक आय तालिका में राष्ट्रीय क्रम और मा0वि0सू0 क्रम में भारी अन्तर हो जाता है। कुछ मामलों में जैसेकि दक्षिणी अफ्रीका में इन विसंगतियों का कारण विशेष समस्याओं(जैसे कि एच.आई.वी./एड्स) को माना जा सकता है। दूसरे मामलों में, स्वास्थ्य एंव शिक्षा के अवसर मुहय्या न कराना, घरेलू नीतियों की असफलता को इसका कारण माना जा सकता है।

लीग तालिका के शीर्ष पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के मापन हेतु मा0वि0सू0 कम असरदार पैमाना है। सार्वभौम साक्षरता और शैक्षिक नामांकन जो जीवन प्रत्याशा की ऊपरी सीमाओं से जुड़े हैं, राष्ट्रों के अंक को बराबर कर देते हैं। लेकिन यहां भी सूचकांक आय और भा0वि0सू0 क्रम के बीच कुछ विसंगतियों को उजागर करता है। उदाहरण के लिए अमेरिका जिसके नागरिक औसतन लक्समबर्ग के बाद विश्व के दूसरे सबसे अमीरों की श्रेणी में आते हैं अपने आय के क्रम के मुकाबले मा0वि0सू0 में 6 क्रम नीचे खिसक जाता है। इसका एक कारण है कि वहां औसत जीवन प्रत्याशा स्वीडन की अपेक्षा लगभग 3 वर्ष कम है– स्वीडन की औसत आय उससे लगभग 1/4 कम है। उच्च मानव विकास समूह के अन्तर्गत चिली और क्यूबा अपनी आय श्रेणी की अपेक्षा मा0वि0सू0

में काफी ऊंचा स्थान रखते हैं।

जैसाकि उपलब्धियों के अनेक क्षेत्रों के आंकड़े संकलित करनेवाले किसी भी सूचकांक में सामान्य रूप से देखा जाता है मा0वि0सू0 भी अपने आंकड़ों की रिपोर्ट प्रणाली में लगातार बदलाव किसी देश के क्रम के प्रदर्शन पर ध्यान दिए बिना सकारात्मक या नकारात्मक दिशा में परिवर्तित कर सकता है। इस वर्ष की मा0वि0सू0 इस समस्या को प्रदर्शित करती है। कई देशों के मा0वि0सू0 अंकों में गिरावट आई है जिसका कारण उनके प्रदर्शन का बदलाव नहीं है,बल्कि शिक्षा की रिर्पोटिंग प्रणाली में किया गया बदलाव है। परिभाषा के अनुसार विद्यालय नामांकन आंकड़ों में प्रौढ़ शिक्षा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी लगभग 32 देशों ने पिछले वर्षों में विद्यालय नामांकन रिपोर्ट में प्रौढ़ शिक्षा को शामिल किया था। इस वर्ष इन देशों ने विसंगति को दूर करने के लिए आंकड़ों की रिर्पोटिंग में बदलाव किया है। आंकड़ों की नई प्रणाली अब अधिक समरूप एंव सटीक हो गई है। लेकिन इस परिवर्तन का एक बुरा प्रभाव अनेक देशों के मा0वि0सू0 क्रम पर पड़ा है, जिनमें अर्हेन्तिना, बेल्जियम, ब्राजील, पेराग्वे, पेरू और ब्रिटेन शामिल हैं। ब्राजील के मामले में उसका उसकामा0वि0सू0 पर 63 से 69 वें स्थान पर सरकना पूर्णतः आंकड़ों की रिर्पोटिंग प्रणाली में बदलाव के कारण हुआ है। शिक्षा के प्रदर्शन में वास्तविक गिरावट नहीं हुई है। इस समूह में इसी भांति के नतीजे देखे जा सकते हैं।

मानवीय विकास की दिशाएं–मा0वि0सू0 और उसके परे

मानव विकास की प्रवृत्तियां एक महत्वपूर्ण बात उजागर करती है। सन् 1970 के दशक के मध्य से सभी देशों के मा0वि0सू0 के अंकों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। सन् 1990 से पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया ने अपने विकास को गति दी है। सन् 1990 के दशक के मध्य में आयी भारी गिरावट के बाद मध्य और पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र राज्यों के कामनवेल्थ ने तेजी से वापसी की और पुनः उस पूर्वस्तर को प्राप्त किया। उप–सहारा अफ्रीका एकमात्र अपवाद रहा। सन् 1990 से इसकी स्थित जस की तस है, अंशतः आर्थिक झटकों के कारण और मुख्यतः जीवन की प्रत्याशा पर एच.आई. वी./एड्स के भंयकर प्रभाव के कारण। सन् 1990 की तुलना में आज 18 देशों का मा0वि0सू0 अंक कम हुआ है–यह उप सहारा के अफ्रीकी देश हैं। निम्न मानव विकासवाले 31 में से 28 देश उप–सहारा अफ्रीका में हैं। यह अफ्रीका द्वारा झेली जा रही विरासत में मिली हानि पर विजय प्राप्त करने में सहस्त्राब्दी के विकास लक्ष्यों के राष्ट्रीय प्रयासों तथा वैश्विक भागीदारी के महत्व को रेखांकित करता है।

मानवीय विकास की प्रगति को कभी–कभी विकसित एंव विकासशील देशों के बीच अभिसरण का प्रमाण मान लिया जाता है। मोटे तौर पर यह तस्वीर सही हैः पिछले कई दशकों में पूरे विश्व के विकासशील देशों में मानवीय विकास के संकेतकों में ठोस सुधार हुआ है। लेकिन भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न दर से भिन्न मुद्दों पर अभिसरण हो रहा है। मानव विकास में गहरी असमानताएं हैं और देशों के एक बड़े समूह में अभिसरण चल ही रहा है। मा0वि0सू0 के सहायक मुख्य संकेतकों के संदर्भ में इसका उदाहरण देखा जा सकता है।

जीवन प्रत्याशा

पिछले तीन दशकों में एक समूह के रूप में विकासशील देशों और विकसित देशों की जीवन प्रत्याशा वृद्धि में समानता आने लगी है। विकासशील देशों में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 9 वर्ष बढ़ी है उच्च आय देशों में 7 वर्ष बढ़ी है। उप–सहारा अफ्रीका फिर इस मामले में अपवाद है। इस पूरे क्षेत्र में जीवन प्रत्याशा 3 दशक पहले की अपेक्षा आज कम हो गई है। यह आंकड़े समस्या का पूरा बयान नहीं कर रहे –दक्षिणी अफ्रीका के अनेक देशों में जीवन प्रत्याशा में भंयकर कमी आई है 20 वर्ष बोत्सावाना में, 16 वर्ष स्वाजीलैंड में, और लेसोथो और जाम्बिया में 13 वर्ष। जनसंख्या सम्बन्धी यह उथलपुथल प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस में हुई उथलपुथल से भी भंयकर है(मानव विकास रिपोर्ट,2005 देखें) जीवन प्रत्याशा का लिंग पैटर्न भी उलटा है। उप–सहारा अफ्रीका में एच.आई.वी./एड्स के फैलते संक्रमण से स्त्रियां अधिक प्रभावित हैं–

आकृति 2 | बालमृत्यु दरों में वैश्विक विभिन्नताएं

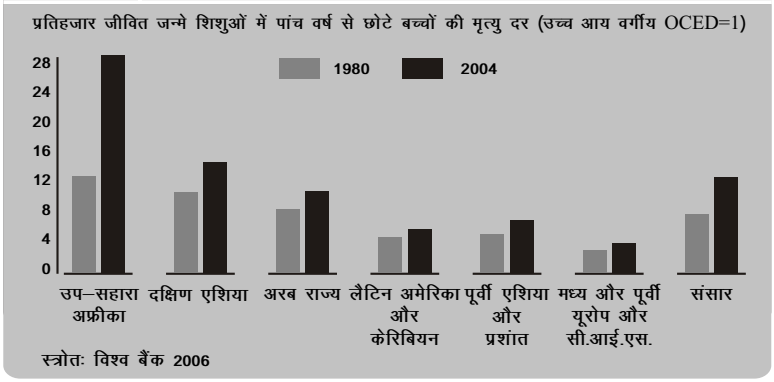

स्त्रोतः विश्व बैंक 2006

इस प्रवृत्ति के कारण स्त्रियों की जीवन प्रत्याशा पुरूषों के मुकाबले अधिक घट रही है। एच. आई.वी./एड्स से बचाव और उसका इलाज इस पूरे ही क्षेत्र में सकारात्मक विकास प्रवृत्ति के पुनरारंभ की महत्वपूर्ण शर्त है।

बाल मृत्यु

शिशुओं के जीवित रहने की दर मानवीय स्वस्ति की सबसे संवेदनशील सूचक होती है। इसमें भी कुछ उत्साहजनक प्रवृत्तियां देखी गई हैं। शिशुओं की मृत्यु दर घट रही है। सन् 1990 की तुलना में सन् 2004 में 21 लाख कम मौतें हुई हैं। सभी क्षेत्रों में जीवन दर में सुधार हो रहा है।(आकृति 2) तो भी सन् 2004 में 1.08 करोड़ बच्चों की मौत होना सबसे मूलभूत जीवन संभावना– जीवित रहने की संभावना में असमानता का साक्ष्य है। वैश्विक गांव के गलत मुहल्ले में जन्म लेना जीवन की संभावना के लिए बड़ा जोखिम पैदा कर देता है

अधिकांश विकासशील देशों में बच्चों के लिए जोखिम बढ़ रहे हैं। विकासशील देशों में बाल मृत्युदर उच्च आय वर्ग के देशों के मुकाबले कई गुना है।

इसके अलावा देशों के एक बड़े समूह में बाल मृत्युदर में कमी की विकास दर धीमी हो गई है। यदि सन् 1980 की विकास दर जारी रहती तो सन् 2004 में विश्व में 15 लाख बच्चों की मौतें कम हुई होतीं। बाल मृत्युदर में कमी के धीमा पड़ने के प्रभाव सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों पर पड़ेंगे। वर्तमान गति के अनुसार 44 लाख मौतों के कारण 2015 तक मृत्यु दर में दो तिहाई कमी लाने के उद्देश्य में चूक हो जाएगी। केवल 3 उप सहारा अफ्रीकी देश इस उद्देश्य की प्राप्ति में सही दिशा में चल रहे हैं।

अन्य सूचकों की अपेक्षा बाल मृत्यु दर सशक्त रूप से दर्शाती है कि आय में वृद्धि मानव विकास में सुधार के समतुल्य नहीं हुई है। अमीरी बढ़ने की दृष्टि से आकलन करें तो भारत विश्व का एक सफल देश हैः सन् 1990 से इसकी सकल घरेलू उत्पाद की औसत विकास दर 4 प्रतिशत प्रति वर्ष रही है। परन्तु बाल मृत्युदर में कमी 1980 में 2.9 प्रतिशत से लेकर सन् 1990 में 2.2 प्रतिशत धीमी रही है। भारत हालांकि आर्थिक प्रगति और औसत आय के मामले में बांग्लादेश से आगे निकल गया है, बाल मृत्युदर घटाने के मामले में बांग्लादेश भारत से आगे है। सन् 1990 से इसमें 3.45 प्रतिशत की कमी की दर बनी हुई है। भारत और बांग्लादेश में बच्चों की विरोधात्मक दशा का जीवन प्रत्याशा की दृष्टि से मूल्यांकन करने पर मानव विकास मापन के लिए धन के सीमित महत्व की बात समझ में आती है।

शिक्षा

मानव विकास के लिए शिक्षा में प्रगति महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसका सम्बन्ध स्वास्थ्य; समानता और सशक्तीकरण से होता है। यहां भी आधा गिलास खाली और आधा भरा दिखता है। काफी प्रगति हुई–लेकिन बहुत कुछ कमी रह गई है।

निरक्षरता पैटर्न अतीत की शिक्षा की कमियों की विरासत के रूप में आज हमारे सामने हैं। सन् 1990 से प्रौढ़ शिक्षा में 75 प्रतिशत से लेकर 82 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, और विश्व में 10 करोड़ अशिक्षित व्यक्ति कम हुए हैं। लिंग समानता की प्रगति कम हुई है। प्रौढ़ निरक्षरता में दो तिहाई संख्या स्त्रियों की है– सन् 1990 में भी प्रतिशत इतना ही था। विकासशील देशों में प्राथमिक नामांकन दर में वृद्धि हुई है और लिंग असमानता सभी क्षेत्रों में घट रही है। इस अच्छी खबर के बाद बुरी खबर यह है कि 11.50 करोड़ बच्चे विद्यालयों में नहीं पढ़ रहे हैं जिनमें से 6.2 करोड़ लड़कियां हैं।

प्राथमिक स्तर पर नामांकन की असमानता शिक्षा की प्रगति को एक महत्वपूर्ण आयाम प्रदान करती है–लेकिन केवल एक आयाम।

आकृति 3 | कुछ देशों में शिक्षा के क्षेत्र में लिंगभेद लड़कियों का पीछा करता है

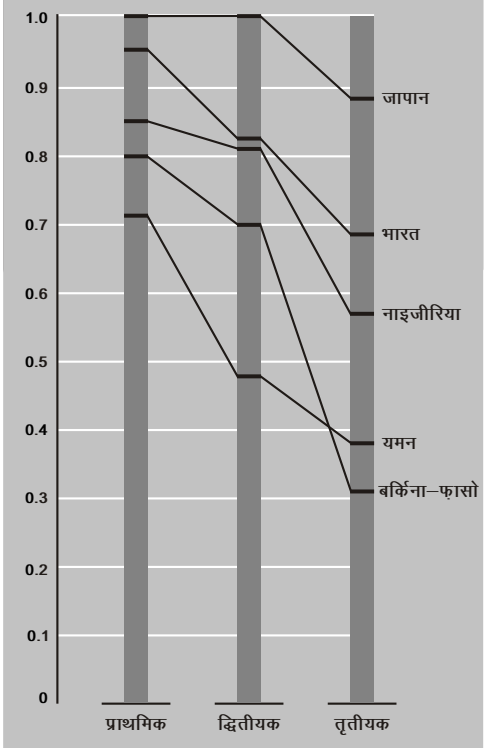

स्त्रोतः सूचक सारणी 12

ज्ञान पर आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत अच्छी गुणवत्तावाली प्राथमिक शिक्षा सीढ़ी का पहला पायदान है, लक्ष्य नहीं। इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में, वैश्विक शिक्षा अवसरों के वितरण में असमानता एक चुनौती बनी हुई है। बर्किना फासो में एक बच्चा औसतन 4 वर्ष की शिक्षा की आशा रखता है जबकि अधिकांश उच्च आयवाले देशों में बच्चे 15 वर्ष पढ़ने की आशा रखते हैं। आज की यह बड़ी शैक्षणिक असमानताएं कल आय और स्वास्थ्य की असमानताओं का रूप लेंगी। मुख्य चुनौतियां इस प्रकार हैः–

- *नामांकन और शिक्षा पूरी करने में अन्तरः* विकासशील देशों में लगभग पांच में से एक बच्चा प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले ही विद्यालय छोड़ देता है। कुछ मामलों में, उच्च नामांकन दर मूल साक्षरता एंव संख्या विषयक कौशल अर्जित करने की दिशा में सीमित प्रगति को छिपा लेती है। चाड, मालावी, रवान्डा जैसे देशों में विद्यालयों में नामांकन करवानेवालों में से 40 प्रतिशत से भी कम बच्चे प्राथमिक शिक्षा चक्र को पूरा करते हैं।

- *सेकेण्डरी विद्यालय में पहुंचने की कम दर* अमीर देशों में प्राथमिक विद्यालय में अन्त तक रहनेवाले 80 प्रतिशत बच्चे निम्न सेकेण्डरी स्तर तक अध्ययन जारी रखते हैं। उनमें से आधे से अधिक तृतीयक शिक्षा भी पूरी करते हैं। उप–सहारा अफ्रीका में आधे से भी कम बच्चे प्राथमिक से सेकेण्डरी विद्यालयों में जाते हैं। 37 ऐसे देश हैं जहां शुद्ध सेकेण्डरी स्तर पर नामांकन की दर 40 प्रतिशत से भी कम हैः इनमें से 26 देश उप–सहारा अफ्रीका में हैं।

- *प्राथमिक शिक्षा के बाद लिंग असमानता* के उच्च स्तर लड़कियों और लड़कों के बीच नामांकन का अन्तर घट रहा है, लेकिन सेकेण्डरी और तृतीयक स्तर पर भारी अन्तर बना हुआ है। (आकृति3) असमानताएं संस्थानगत लिंगभेद प्रदर्शित करती हैं जिनके कारण स्त्रियों के लिए विकल्प कम हो जाते हैं; आय और रोजगार के अवसर कम होते हैं। मातृ शिक्षा और बाल–स्वास्थ्य के बीच सम्बन्ध होने के कारण लिंग भेद की वजह से बाल मृत्युदर में कमी की दिशा में प्रगति में रूकावट पैदा होती है।

आय की गरीबी और वितरण

सन् 1990 के बाद उप–सहारा अफ्रीका को छोड़कर सभी क्षेत्रों में आय की गरीबी घटी है। एक डॉलर प्रतिदिन से कम आय वाले विश्व के लोगों का आंकड़ा 28 प्रतिशत से गिरकर 21 प्रतिशत हो गया, अब मात्र एक अरब से अधिक लोग इस सीमा पर अटके पड़े हैं। चीन और भारत में उच्च आर्थिक विकास आय की गरीबी घटाने का सबसे सशक्त प्रेरक रहा है। उप सहारा अफ्रीका एक मात्र ऐसा क्षेत्र है जहां गरीबी और गरीबों की संख्या दोनों में बढोत्तरी हुई है। लगभग तीन करोड़ लोग–क्षेत्र की आबादी का लगभग आधा हिस्सा– एक डॉलर प्रतिदिन से कम की आय पर गुजर–बसर करते हैं।

सम्पूर्ण विश्व 2015 तक गरीबी आय आधा करने के उद्देश्य की ओर ठीक से बढ़ रहा

बाक्स 1 उप–सहारा अफ्रीका में एच.आई.वी./एड्स का स्त्रीकरण

राष्ट्रों के बड़े समूह के मानव विकास को एच.आई.वी./एड्स ने पीछे धकेल दिया है। 3.90 करोड़ लोग एच.आई.वी. से संक्रमित हैं और 30 लाख लोग सन् 2005 में एड्स फैलाने वाले वायरस के संक्रमण से काल कवलित हो गए। जीवन प्रत्याशा घटने का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष कारण एच.आई.वी./एड्स रहा जिसका प्रभाव मानव विकास सूची(मा0वि0सू0) पर पड़ा। इस रोग के महिलाओं में प्रसार और लिंग समानता पर प्रभाव को कम परिलक्षित किया गया।

इस संकट के अधिकेन्द्र उप–सहारा अफ्रीका में संक्रमण दर पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों में बढ़ी(आकृति 1) इस क्षेत्र में स्त्रियां एच.आई.वी. संक्रमण के 57 प्रतिशत शिकार रहीं और कम उम्र(15–24) की अफ्रीकी महिलाओं में संक्रमण की आशंका पुरूषों की अपेक्षा तीन गुना है।

इस विश्वव्यापी महामारी के कारण अफ्रीकी देशों का जनसंख्या–सम्बन्धी ढांचा बदल रहा है। स्त्रियों के संक्रमित होने की अधिक आशंका होती है और जीवन के प्रारम्भिक काल में इस से उनकी मृत्यु की आशंका अधिक रहती है। दक्षिणी अफ्रीका में इसके कारण पुरूषों और स्त्रियों की जीवन प्रत्याशा की दर पलट गई है। (आकृति 2) वर्तमान झुकाव को देखते हुए सन् 2005–10 तक बोत्सवाना, लेसोथो, दक्षिणी अफ्रीका और स्वाज़ीलैड में औसत जीवन प्रत्याशा दर पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों में दो वर्ष कम हो जाएगी जो सन् 1990–95 में 7 वर्ष अधिक होती थी। एच.आई.वी./एड्स मृत्युदर की लिंग विसंगति का एक कारण कम उम्र में शादी या संभोग है जिसके कारण कम उम्र की स्त्रियों और लड़कियों में संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है।

इसके बावजूद एच.आई.वी./एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए 11 देशों के विस्तृत अध्ययन से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि 8 देशों में 15 वर्ष से कम आयु में संभोग के मामले घटे हैं और कन्डोम का प्रयोग बढ़ा है। इलाज के आंकड़े भी सही दिशा में बढ़ रहे हैं: वायरल–विरोधी दवा का प्रयोग सन् 2003 में 100,000 लोगों को उपलब्ध था जो सन् 2005 के अंत में बढ़कर 8,10,000 तक पहुंच गया। लेकिन अब भी 47 लाख लोगों में से जरूरतमंद प्रति 6 लोगों में से केवल एक व्यक्ति को यह इलाज मिल पाता है। बोत्सवाना में 80 प्रतिशत से अधिक तथा अंगोला में 4 प्रतिशत पीड़ितों को इलाज मिलता है। इलाज पा रहे एक चौथाई लोग दक्षिणी अफ्रीका में है।

क्या लिंग पूर्वाग्रह इसकी रोकथाम और इलाज को दिग्भ्रमित करता है?इस बात के मिश्रित प्रमाण हैं। असमान शक्तिसंबधों के कारण रोकथाम में स्त्रियों और लड़कियों को घाटा हो सकता है क्योंकि वे निर्णय लेने में कम समर्थ होती हैं। शैक्षणिक असमानता भी एक कारण है। लिंग–विषमता के कारण विद्यालय में उपस्थिति के मामले में लड़कियां घाटे में रहती हैं क्योंकि विद्यालय एच.आई.वी./एड्स की शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थल होता है। वर्तमान प्रमाण इलाज के मामले में इलाज में क्रमबद्ध विषमता की ओर इशारा नहीं करते। इथियोपिया और घाना में संक्रमण दर के आधार पर की गई भविष्यवाणी के विपरीत स्त्रियों में संक्रमण में कमी हुई जबकि दक्षिणी अफ्रीका तथा तन्जानिया में वृद्धि हुई।

उप–सहारा देशों में पुरूषों की भांति, स्त्रियां भी लांछन के भय और कमजोर नेतृत्व और अपर्याप्त राजनैतिक भागीदारी से त्रस्त रहती हैं जिसके कारण अनेक देशों में एच.आई.वी./एड्स के विरूद्ध असरदार प्रतिक्रिया के विकास में बाधा पड़ी। यदि सन् 2010 तक वैश्विक निधि के एड्स, मलेरिया और क्षयरोग के विरूद्ध उपचार को एक करोड़ लोगों तक मुहय्या कराने का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उन्हें लाभ होगा। सात प्रमुख औद्योगिक देशों के समूह का सन् 2010 तक सार्वभौम इलाज का संकल्प एक महत्वपूर्ण बात है। साथ ही राष्ट्रीय सरकारों को चाहिए कि रोकथाम और इलाज की नीतियां बनाते समय लिंग असमानता को दूर करने की ओर पूरा ध्यान दें।

आकृति 1 उप–सहारा अफ्रीका–स्त्रियों के लिए बढ़ता संकट

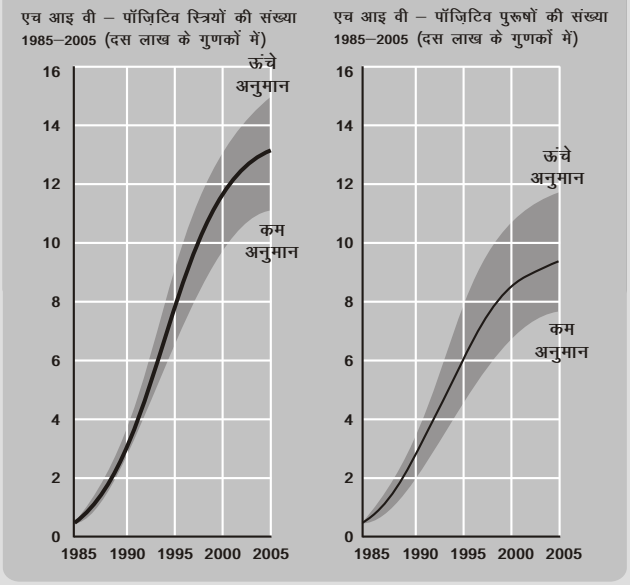

टिप्पणी: 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों के बारे में
स्त्रोतः यूएनएड्स 2006

आकृति 2 जीवन प्रत्याशा – दक्षिण अफ्रीका में स्त्री–पुरूष अनुपात बदला

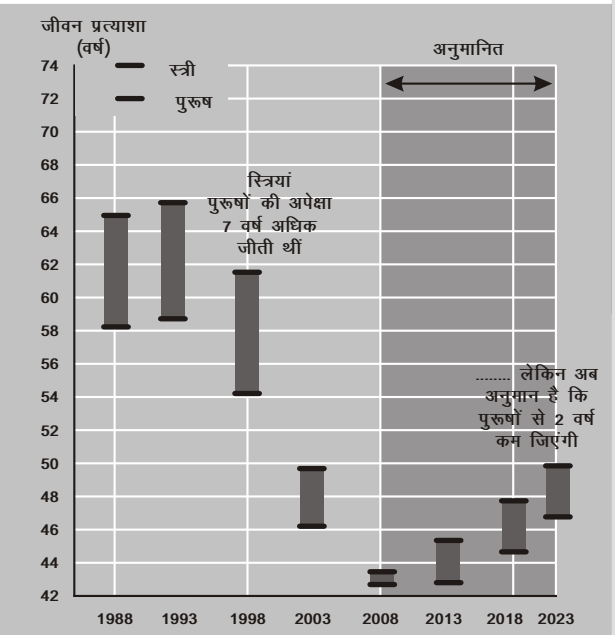

स्त्रोतः यू एन 2005 b

है, लेकिन उप सहारा अफ्रीका पटरी से उतर गया है, इस क्षेत्र में कई अन्य देशों की भी यही स्थिति है। समृद्ध विश्व अर्थव्यवस्था में इतने उच्च स्तर की गरीबी धन की अति विषमता और विश्व आय में गरीबों का बहुत छोटा सा हिस्सा प्रदर्शित करती है:

- विश्व आय में एक डालर प्रतिदिन से कम पर गुजर–बसर कर रहे विश्व के 20 प्रतिशत सबसे गरीब लोगों का योगदान 1.5 प्रतिशत के बराबर है। 40 प्रतिशत सबसे गरीब जिनकी आय 2 डालर प्रतिदिन है उनका योगदान विश्व आय के 5 प्रतिशत के बराबर है।
- उच्च आय वाले आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के सदस्य देशों के 10 में से 9 व्यक्ति वैश्विक आय वितरण के शीर्ष 20 प्रतिशत के अन्तर्गत आते हैं। पैमाने के दूसरी ओर उप सहारा अफ्रीका में 2 में से 1 व्यक्ति 20 प्रतिशत सबसे गरीब व्यक्तियों में गिना जाता है। लोगों में इस क्षेत्र की निम्नतम स्तर पर जी रहे 20 प्रतिशत हिस्सेदारी 1980 की तुलना में दोगुने से अधिक हो चुकी है। (यानि कुल का 36 प्रतिशत)!
- विश्व की औसत आय 5,533 डालर है–लेकिन 80 प्रतिशत दुनिया की आबादी इस औसत से नीचे जीवनयापन करती है। वैश्विक असमानता औसत और मध्य आय के बीच विशाल अन्तर के बीच जकड़ी हुई है (सन् 2000 में 1700डॉलर)
- दुनिया के 500 सबसे अमीर व्यक्तियों की आय 100 अरब डॉलर से अधिक है जिसमें परिसम्पत्तियां शामिल नहीं है। यह सबसे गरीब 41.60 करोड़ लोगों की संयुक्त आय से अधिक है। वैश्विक आय वितरण के शीर्ष पर धन का एकत्रित होना निम्नतम स्तर पर गरीबी घटाने से अधिक प्रभावशाली रहा है। मेरिल लिन्च द्वारा तैयार की गई विश्व धन रिपोर्ट 2004 दर्शाती है कि 77 लाख 'उच्च शुद्ध व्यक्ति आयवाले' लोगों की आर्थिक परिसम्पत्ति धनसंपदा जो सन् 2003 में 28 ट्रिलियन डॉलर तक होती थी सन् 2008 तक 41 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जायेगी।

वैश्वीकरण ने वैश्विक आय वितरण की प्रवृत्ति की दिशा में लम्बी बहस छेड़ी है। लेकिन एक बात जो कभी–कभी अनदेखी रह जाती है वह है असमानता की गहराई–और गरीबी उन्मूलन में तेजी लाने के लिए अधिक समता की सम्भाव्यता। सन् 2000 में क्रयशक्ति अनुरूपता(पीपीपी) शर्तों का आकलन करने पर दुनिया की 20 प्रतिशत सबसे गरीब आबादी की आय और एक डॉलर प्रतिदिन की गरीबी रेखा का अन्तर 300 अरब डॉलर था। यह संख्या लगती बहुत बड़ी है, लेकिन दुनिया के 10 प्रतिशत सबसे अमीरों की आय के 2 प्रतिशत से भी कम है। सबके सहयोग से व्यापक राष्ट्रीय विकास नीति बनाकर– जिसे अंर्तराष्ट्रीय समुदाय का सहायता, व्यापार तथा तकनीक अन्तरण के माध्यम से समर्थन प्राप्त हो– विश्व आय वितरण में और अधिक समानता प्राप्त करना आय गरीबी के 2015 के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम होगा।

असमानता और मानव विकास

भा0वि0सू0 मानव विकास के औसत राष्ट्रीय प्रदर्शन की एक झलक प्रस्तुत करती है। हांलाकि, औसतों की आड़ में देशों की बड़ी विषमताएं छिपी रह सकती है। आय, धन, लिंग, जाति और अन्य प्रकार के विरासत में मिले दोष और स्थिति पर आधारित असमानताएं राष्ट्रीय औसतों को मानव कल्याण का एक गलत सूचक बना सकती हैं।

क्या भा0वि0सू0 का उपयोग राष्ट्रों के भीतर असमानताओं को प्रकट करने के लिए हो सकता है?इस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में अनुसंधान द्वारा इस प्रश्न का समाधान खोजा गया। इसके लिए आय द्वारा राष्ट्रीय भा0वि0सू0 के अंकों को अलग रख कर प्रयास किया गया। इस अध्ययन में 13

आकृति 4 | एक ही देश में अलग–अलग दुनियाएं–आयवर्गवार मा.वि.सू.

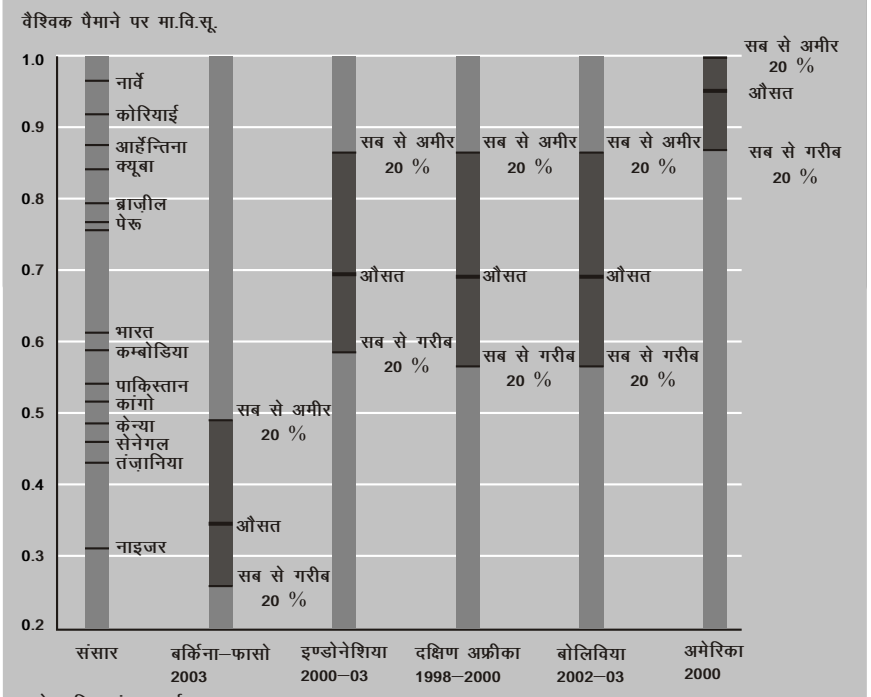

स्त्रोतः ग्रिम एंड अदर्स 2006

विकासशील देशों और दो विकसित देशों– फिनलैंड और अमेरिका को (पर्याप्त उपलब्ध आंकड़ों समेत) शामिल किया गया।

राष्ट्रों में भिन्न–भिन्न आय समूहों की मा0वि0सू0 अंकतालिका के तैयारी में तकनीकी चुनौतियां सामने आती हैं(पूरी रिपोर्ट पर तकनीकी टिप्पणी 2 देखें) मानकीकृत घरेलू आय सर्वेक्षण और जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा आय वितरण के भिन्न बिन्दुओं पर सूची के लिए आंकड़े उपलब्ध कराना संभव है। लेकिन आंकड़ों की उपलब्धता और तुलनात्मकता में पैदा समस्याएं ऐसी सूची तैयार करना मुश्किल बना देती हैं जो देशों के बीच तुलना कर पाने में समर्थ हो। एक अतिरिक्त समस्या यह है कि आय समूहों के आधार पर भा0वि0सू0 अंक तालिका तैयार करने के लिए आवश्यक आंकड़े अनक उच्च आयवाले देशों के संदर्भ में उपलब्ध नहीं हैं। इन समस्याओं के बावजूद राष्ट्रीय आय समूहों पर आधारित अंर्तराष्ट्रीय तुलनात्मक मा0वि0सू0 अंक तालिका तैयार करना क्षमता से वंचित रखे जाने के आयामों को समझने के सशक्त उपकरण उपब्ध कराने की सामर्थ्य रखता है।

आय समूह के आधार पर मानव विकास की नंगी असमानताएं इंगित करता है।(आकृति 4)। बर्कीना फासो, मैडागास्कर तथा जाम्बिया में सबसे अमीर 20 प्रतिशत की मा0वि0सू0 अंकतालिका सबसे गरीब 20 प्रतिशत से लगभग दोगुनी है। बोलिविया, निकारागुआ और दक्षिण अफ्रीका के बीच भी भारी अन्तर देखे गए हैं। उच्च आयवाले देशों में अमीर और गरीब के बीच मा0वि0सू0 की आय विषमताएं कम हैं अंशतः क्योंकि आय में कमी जीवन प्रत्याशा विषमताओं और मूलभूत शिक्षा परिणामों को कम प्रभावित पाती है। फिर भी, अमेरिका आय समूह के आधार पर महत्वपूर्ण मा0वि0सू0 विषमताएं प्रदर्शित करता है।

अंर्तदेशीय तुलना मानवीय विकास की असमानताएं उजागर करती हैः

- बोलिविया के 20 प्रतिशत सबसे अमीर लोगों का क्रम उन्हें उच्च मानव विकास समुदाय में, पोलैण्ड के समकक्ष रखता है जबकि सबसे गरीब 20 प्रतिशत का क्रम उन्हें पाकिस्तान के औसत के समकक्ष रखता है। पाकिस्तान, पोलैण्ड से 97 पायदान नीचे है। निकारागुआ के मामले में सबसे अमीर और सबसे गरीब 20 प्रतिशत के बीच वैश्विक स्तर पर मा0वि0सू0 अंतर 87 पायदानों का है।
- दक्षिण अफ्रीका में सबसे अमीर 20 प्रतिशत का मा0वि0सू0 क्रम 20 प्रतिशत सबसे गरीब की तुलना में 101 स्थान ऊपर है।
- इन्डोनेशिया में मानव विकास प्रसार 20 प्रतिशत सबसे अमीर के लिए चेक रिपब्लिक के समतुल्य स्तर का है 20 प्रतिशत सबसे गरीब का स्तर कम्बोडिया के बराबर है।
- अमेरिका में 20 प्रतिशत सबसे अमीर मानव विकास उपब्धियों की सूची के शीर्ष पर हैं और सबसे गरीब समूह का क्रम 50 है।

मा0वि0सू0 अमानताओं का कारण– बाल मृत्युदर और शैक्षिक असमानताएं

आय समूह के संदर्भ में मा0वि0सू0 कल्याण के कुछ महत्वपूर्ण आयामों का सम्पूर्ण

बर्कीनाफेसो बोलोबया इन्डोनेशिया दक्षिणी अफ्रीका

घरेलू आय के परे देखने पर मा0वि0सू0 को अलग रखकर विभिन्न स्तरों पर असमानताओं का पता लगाया जा सकता है। अनेक देशों में क्षेत्रों के बीच बड़े अंतर उजागर होते हैं। केन्या में मा0वि0सू0 नैरोबी में(तुर्की के समान) 0.75 की श्रेणी में है, तो देश के ग्रामीण क्षेत्र तुर्काना में 0.29 (आकृति 6) तुर्काना यदि एक देश होता, तो यह वर्तमान मा0वि0सू0 के पैमाने से बहुत नीचे हो जाता क्योंकि यहां बराबर अकाल पड़ता है, स्वास्थ्य और जल सुविधा की स्थिति खराब है और कुपोषण दर अधिक है।

ग्रामीण–शहरी अंतर और क्षेत्रीय विषमताओं के बीच अंर्तक्रिया होती है। चीन में शंघाई शहर भूमंडलीय मा0वि0सू0 समूह में ग्रीस से थोड़ा ऊपर, 24वें क्रम पर है,जबकि ग्रामीण गुइझो प्रांत बोत्सवाना के समकक्ष क्रम में होगा।

कुछ देशों के मामले में मा0वि0सू0 समूह सदस्यता पर आधारित बहुत विशाल असमानताएं प्रकट करता है। इसका एक उदाहरण ग्वाटेमाला है, जहां विकास के अवसर मूलवासी समूहों के विरूद्ध जाते हैं। क्वेची समूह का मा0वि0सू0 क्रम कैमरून के बराबर और लेडिनोज़ के क्रम से 32 स्थान नीचे है।

आकृति 5 जीवित बचे रहना– अवसर समृद्धि से जुड़े हैं

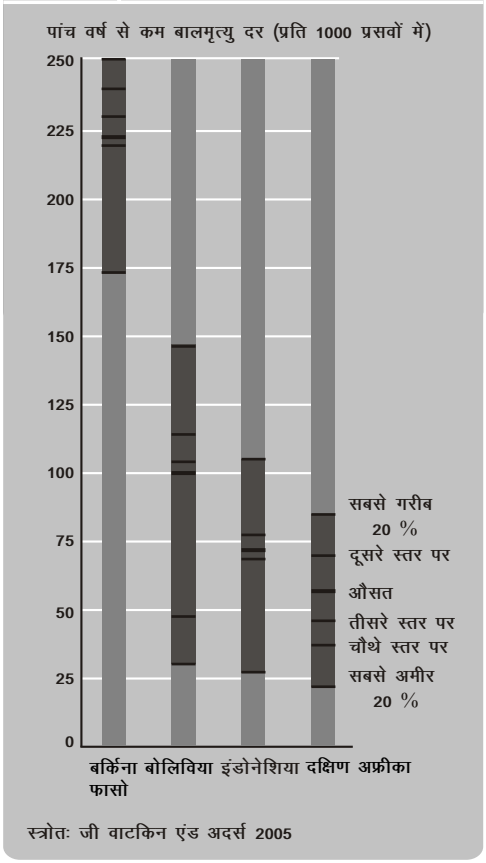

स्त्रोतः जी वाटकिन एंड अदर्स 2005

आकृति 6 केन्या के क्षेत्रों में विकास में व्यापक असमानताएं

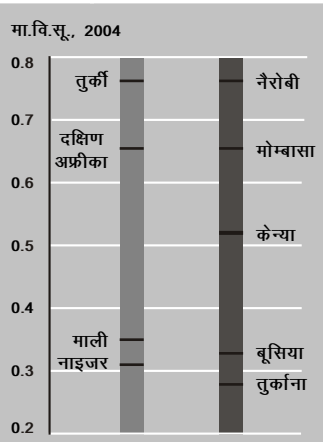

स्त्रोत यूएनडीपी 2005 c

आय असमानता

आय असमानता में क्षेत्रीय अंतर विशाल है। असमानता का एक पैमाना गिनी गुणांक 0 (पूर्ण समानता) से प्रारंभ होकर 100(पूर्ण असमानता) की ओर जाता है। इसके अनुसार इस क्रम में दक्षिण अफ्रीका, 33 लैटिन अमेरिका 57 और उपसहारा अफ्रीका 70 की श्रेणी में आता है। वैसे तो अंर्तक्षेत्रीय तुलनाओं में सावधानी बरती जानी चाहिए, लेकिन यह क्षेत्रीय विषमताएं 20 प्रतिशत सबसे अमीर और गरीब लोगों के बच्चों की आय वितरण में बड़े अंतर से सम्बन्धित हैं। वे औसत आय और मध्यम आय के बीच अंतर दर्शाती हैं, जो असमानता के साथ बढ़ता जाता है। मेक्सिको जैसे उच्च असमान देश में मध्यम आय औसत का केवल 51 प्रतिशत है। वियतनाम में, जहां आय वितरण अधिक समान है, मध्यम औसत के 77 प्रतिशत तक पहुंच जाता है।

गरीबी में कमी आय वितरण से क्यों जुड़ी हुई है?तकनीकी मायने में आय गरीबी की कमी की दर किसी देश में दो बातों का परिणाम होती हैंः आर्थिक विकास की दर और वृद्धि का गरीबों को मिल पाया हिस्सा अन्य बातें समान होते हुए, आय में गरीबों की सहभागिता जितनी अधिक होगी देश उतनी ही सक्रियता से विकास को गरीबों में कमी लाने में परिवर्तित कर पाएगा। आय वितरण पैटर्न स्थिर रखने और भविष्य में वर्तमान विकास दर बनाएं रखने में मेक्सिको के गरीबी रेखा के मध्यम

परिवारों को गरीबी रेखा से पार पाने में तीन दशक लगेंगे। भविष्य में आयवृद्धि में गरीब की भागीदारी दोगुनी होने से यह समयसीमा आधी रह सकती है। केन्या के मामले में यह समयसीमा 17 वर्ष होगी। यह परिवर्तन 2030 की बजाय 2013 में ही देश को सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य के आय गरीबी आधा करने के अलभ्य लक्ष्य के नजदीक ले जाएगा।

जैसाकि उदाहरण दर्शाते हैं, वितरण से अंतर पड़ता है क्योंकि यह उस दर को प्रभावित करता है जिससे आर्थिक वृद्धि गरीबी में बदलती है। इस प्रकार वृद्धि में 1 प्रतिशत की बढ़त वियतनाम में 1.5 प्रतिशत गरीबी कम करती है– मेक्सिको में 0.75 प्रतिशत से दोगुनी। अच्छी खबर यह है कि नितांत असमानता जीवन का अपरिवर्तनीय तथ्य नहीं है। पिछले 5 सालों में विश्व के सबसे असमानतावाले देश ब्राजील, ने आय असमानता और गरीबी घटाने के साथ मजबूत आर्थिक प्रदर्शन किया है (राष्ट्रीय स्त्रोतों के अनुसार गिनी सूचकांक 2001 में 56 से घटकर 2004 में 54 हो गया है) आर्थिक वृद्धि ने रोजगार और वेतनों में बढ़त का मार्ग प्रशस्त किया है। एक विशाल सामाजिक कल्याण कार्यक्रम –बोल्सा फेमीलिया– ने 70 लाख मध्यम और अधिक गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जिससे पोषण स्वास्थ्य और शिक्षा में मदद मिले और आज का लाभ कल की संपत्ति बन जाए।

विकासशील देशों में आय वितरण केवल एक मुद्दा नहीं है– जैसाकि अमेरिका के लिए विभिन्न आयवर्गों के 20 प्रतिशत के लिए मा0वि0सू0 रेखांकित करता है, यह विश्व के कुछ सबसे अमीर देशों के लिए भी महत्वपूर्ण है। पिछले 25 वर्षों में अमेरिकी आय वितरण का निम्न तथ मध्य और शीर्ष के बीच का अंतर नाटकीय ढंग से बढ़ा है। सन् 1980 और 2004 के बीच 1 प्रतिशत सबसे अमीर परिवारों की आय (सन्2004 में 7,21,000 डॉलर से अधिक औसत आय) में 135 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इसी अवधि में असली निर्माण मजदूरी में 1 प्रतिशत की कमी आई। राष्ट्रीय आय में 1 प्रतिशत सबसे अमीरों का भाग बढ़कर इसी अवधि में 16 प्रतिशत हुआ। दूसरे शब्दों में अमेरिका में वृद्धि में योगदान करने वाले उत्पादकता लाभ के फल ज्यादातर समाज के सबसे धनी वर्गों के ही पल्ले पड़े।

क्या असमानता के बढ़ने से अवसर कम हो जाते हैं?इस प्रश्न का एक समाधान यह है कि मां–बाप की अर्जन क्षमता के प्रभाव का आकलन कर उनके बच्चों की भावी आमदनी का आकलन किया जाए। कम असमानता वाले देशों – जैसे डेनमार्क और नार्वे में माता–पिता की आय बच्चों की 20 प्रतिशत आय की व्याख्या करती है। अमेरिका के और ब्रिटेन के मामले में यह अनुपात 50 प्रतिशत में अधिक बढ़ जाती है।

एक ही देश के भीतर आय और अवसरों में असमानता के ऊंचे स्तर मानवीय विकास को बाधित करते हैं। आर्थिक गतिशीलता,वृद्विऔर सामाजिक समरसता के लिए विपरीत निहितार्थों के अलावा यह वृद्धि के मानव विकास में बदलने को भी बाधित करते हैं। वैश्विक स्तर पर भी यही होता है जहां लगातार बढ़ते सम्पन्न और निर्धन को अलग करनेवाले विभाजक असंतोष का एक केंद्रीय बिन्दु बन गए हैं। आनेवाले दशकों में मानव विकास के सामने एक केंद्रीय चुनौती 1990 के दशक के शुरूआती दौर से भूमंडलीकरण की एक विशेषता सी बन गई अति–असमानताओं के प्रति सहिष्णुता में कमी करना और यह सुनिश्चित करना होगा कि समृद्धि का ज्वार बहुसंख्य लोगों तक पहुंचे केवल मुट्ठीभर विशेषाधिकार–प्राप्त लोगों तक सीमित न रह जाए।

HDR website: http://hdr.undp.org